BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Admission Open

For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Vision -
To prepare the children
empowered
with Indian ethical
and spiritual values
to face the global challenges.

Mission-
To produce
enriched and enlightened
human resource
for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Streams:
Science,
Commerce &
Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao,
Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक उपनिषद)

पोस्टल रजि.नं.यू0-नैनीताल-356-2021-2023

दिसंबर 2025

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

पुतिन से न मिल पाने की बेचैनी

₹:40

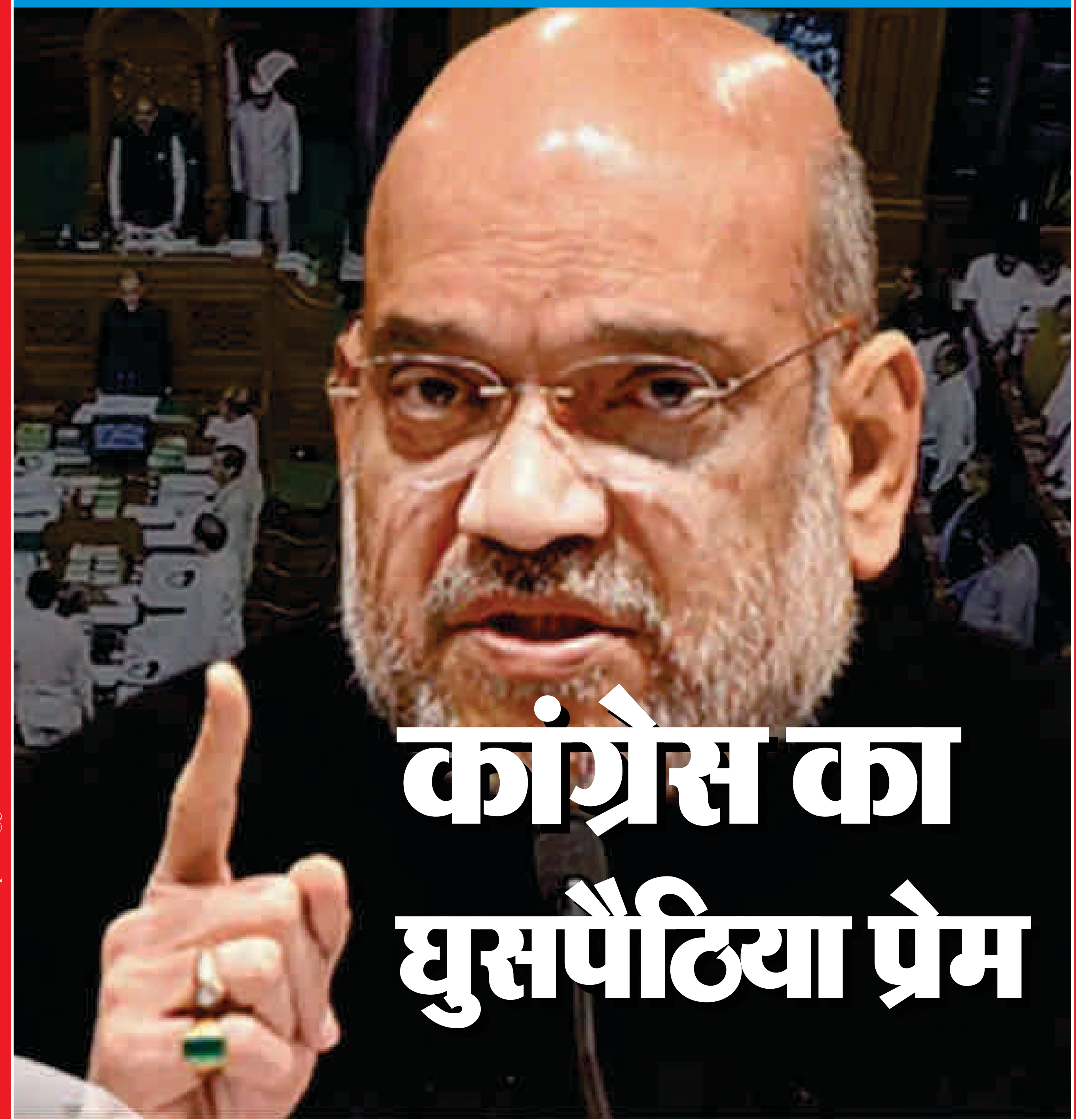

कांग्रेस का घुसपैठिया प्रेम

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

मासिक
उत्तरांचल दीप
पत्रिका

वर्ष:8, अंक 8, दिसंबर 2025

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र किसी हथियार से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जहरीली बयानबाजी का हमला झेल रहा है, भारत का लोकतंत्र जहरीले बयानों की वजह से खतरे में है।

धरोहर
पहाड़ी धरोहर गागर गायब
उत्तराखंड में तांबे के बर्तनों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है, यहां पुराने दौर में तांबे के बर्तनों में भोजन बनाने और खाने की प्रथा थी ...

पर्यटन
सुकून मिलता है कनातल गांव में
उत्तराखंड अब ग्रामीण पर्यटन के लिए ज्यादा विख्यात हो रहा है, पर्यटकों को गांवों की सुंदरता, होमस्टे, पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ियों की ...

आपबीती
पलायन न करने का दर्द
'लगभग 25 साल पहले में इस गांव में शादी होकर आई, तभी से यहां हूं। हमने खेती करके ...

नेशनल

घुसपैठियों में भगदड़?
एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल की कई बस्तियों की झुग्गी खाली हो गई हैं ...

साकेत अग्रवाल

युवा प्लान, नबीन को कमान

भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह जो भी करते हैं वो लीक से हटकर होता है। लिहाजा एक बार फिर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए भाजपा ने पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 45 साल के युवा को भाजपा की कमान सौंप दी। बिहार में पांच बार विधायक और तीन बार मंत्री रहे नितिन नबीन की तत्काल प्रभाव से ताजपोशी भी हो गई है। हालांकि भारतीय राजनीति में ओबीसी पैटर्न सेट होने के बाद माना जा रहा था कि अब सत्ता की राजनीति में सवर्णों के दिन लद गए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस धारा के खिलाफ तैरने की हिम्मत की। शायद इसलिए भी भाजपा सफलता की सीढ़ी चढ़ती है। पार्टी में किसी भी नेता का चयन सिर्फ योग्यता के आधार पर होता है। यहां परिवारवाद की कोई जगह ही नहीं है। यानी कोई भी पद एक उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार को ही मिलता है। भले ही उसकी जाति कोई भी क्यों न हो। नरेंद्र मोदी की इस विचारधारा ने देश की राजनीति में हमेशा नए-नए प्रयोग किए हैं। उनका हाल में सबसे नया प्रयोग भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हैं। लिहाजा नितिन नबीन नाम ने राजनीति के विश्लेषकों को हैरान कर दिया। बहुत से विश्लेषक तमाम नामों पर मोहर लगा रहे थे, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में बताए जा रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि कोई महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन की संगठन क्षमता, चुनावी रणनीति, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह नियुक्ति सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। यानी भाजपा को जब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को धार देने की जरूरत महसूस हुई, तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर नितिन नबीन पर जाकर ठहरी। इससे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को जो भी जिम्मेदारी दी उसमें उन्होंने शत प्रतिशत परिणाम दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जहां उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर खास फोकस किया। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी और निर्णायक जीत मिली। छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में उनके कामकाज ने दोनों शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खासा प्रभावित किया था। नितिन नबीन की नियुक्ति से साफ है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दिशा पर ही चल रही है।

ऐसा भी नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने सीधे नितिन नबीन की नियुक्ति कर दी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों से भी सलाह ली। उन्होंने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के सामने कुछ सवाल रखे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष किस क्षेत्र से हो? किस आयु वर्ग का हो? उसकी भाषा क्या हो? किस जाति अथवा धर्म से ताल्लुक रखता हो? इन सवालों में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं मांगा गया था। इन सवालों के साथ संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल बैठक भी की। वर्चुअल बैठक करने के पीछे मकसद शायद ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में गोपनियता बनी रहे। बैठक में अधिकांश सदस्यों की राय थी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी भाषी होना चाहिए, दूसरी राय थी कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। क्षेत्र और जाति को लेकर सदस्यों के मत कुछ अलग थे। इसके बाद ही नितिन नबीन के नाम पर आरएसएस की मोहर लगी। वैसे नितिन नबीन आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस उनके काम से संतुष्ट भी है। लिहाजा 14 दिसंबर को उनके नाम की घोषणा कर दी गई। 15 दिसंबर को नितिन नबीन दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचे। जहां गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में नितिन नबीन की कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हुई। इसके साथ भाजपा कार्यालय में जेपी नड्डा की कुर्सी बदल गई। क्योंकि पीएम मोदी ने ओबीसी आधारित बिहार की राजनीति से एक सवर्ण नेता नितिन नबीन को चुनकर राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर दिया। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को सीएम का पद सौंपा है। यहां तक कि हरियाणा की जाट वर्चस्व वाली राजनीति में मनोहर लाल खट्टर को पहला गैर जाट मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति में नए प्रयोग किया था। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने फैसलों के कारण नेताओं भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। नितिन नबीन भाजपा के एक बड़े नेता बन चुके हैं। अब जब अहम मामलों पर पार्टी की बैठक होगी तो नितिन नबीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बगल में बैठेंगे। अब वे प्रधानमंत्री के नियमित संपर्क में रहेंगे। यानी वो भाजपा की शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित होंगे। इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी तक भाजपा ने बिहार में सम्राट चौधरी को अपने चेहरे के रूप में सामने रखा है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से नितिन नबीन अब बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये सम्राट चौधरी के लिए भी एक चेतावनी है।

उत्तराखंड में होगी 'सत्य ही नारायण' फिल्म की शूटिंग

फिल्म का संयुक्त रूप से निर्देशन सुधाकर शर्मा और अरुण सिंह कर रहे हैं, सुधाकर शर्मा बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और स्थापित निर्देशक हैं, जो 2500 फिल्मी गीत लिख चुके हैं, इनमें सलमान खान की फिल्मों के लिए भी उन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं, सुधाकर शर्मा ने 'प्यार किया तो डरना क्या' फिल्म के लिए 'ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की...' लिखा है।

उत्तरांचल दीप ब्यूरो

आमतौर पर मान्यता है कि 'नारायण ही सत्य है', लेकिन असल पहलू तो 'सत्य ही नारायण है।' ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि सनातन में कहते है कि 'अहम ब्रह्माष्मि' यानी नर ही नारायण हैं। जब आप कहते हैं कि नायरण ही सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि जो सत्य है वही नारायण है। तो फिर ये भी उतना ही सत्य है कि जो आपका सत्य है वही नारायण है। जब मानव अपना सत्य पा लेता है और उस सत्य के साथ जीना शुरू कर देता है तब मानव खुद ही नारायण बन जाता है। इसलिए हम 'सत्य ही नारायण' फीचर फिल्म के माध्यम से ये बताने और अहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव अपने भीतर के सत्य की खोज करे और स्वयं के नारायण को पहचाने। हमारी ये फिल्म सत्यनारायण व्रत पर आधारित है। यानी सत्यनारायण व्रत कथा में जो चार अध्याय है वो हर अध्यायय हमसे एक-एक बात कहता है कि आप झूठ न बोलों, मोह मत करो, लालच न करो और घमंड मत करो, क्योंकि यही चारों भाव भौतिक और आध्यात्मिक रूप से मानव के पतन का कारण बनते हैं। जब हम अपने जीवन से इन चार भावों को निकाल देते हैं तो हम खुद में नारायण का स्वरूप हो जाते हैं और हमारा जीवन बैकुंठ स्वरूप हो जाता है। जबकि इस कलियुग में लगभग हर मानव चारों भाव झूठ, लालच, मोह और घमंड के साथ जी रहा है। यही कारण है कि मानव अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी नरक बना रहा है। सत्य ही नारायण है फिल्म बनाने का मकसद यह है कि समाज में व्याप्त लालच, मोह, झूठ और घमंड के दुष्प्रभाव से ही मानव परेशान है। यही संदेश फिल्म के माध्यम से समाज को देना है। यदि सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के सत्य को पहचानना होगा।

'सत्य ही नारायण' फिल्म हिंदी फीचर फिल्म हैं, लेकिन इसके गढ़वाली और कुमाऊंनी वर्जन भी होंगे, फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत लोकेशन का चयन किया जा रहा है, इनमें नैनीताल जिले को भी शामिल किया गया है, उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे आलोकनाथ, राजेंद्र गुप्ता, अनुपम खेर आदि के साथ काम करने का मौका मिलेगा।

फिल्म का आधार सत्य नारायण व्रत है तो फिर आपके जहन में सवाल उठना लाजमी है कि फिर तो एक तरह से ये धार्मिक फिल्म होगी? जी नहीं ये फिल्म धार्मिक नहीं है बल्कि आधुनिक समाज में धर्म को केंद्र में रखते हुए सामाजिक, धार्मिक, प्रेम, सद्भाव और हास्य के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। जिस तरह से किसी समय में भगवान विष्णु ने समाज में सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य नारायण के व्रत की प्रेरणा दी थी। उसी तरह से किसी कारण वश आज के समाज में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, और लक्ष्मी जी को कलियुग में धरती पर आकर रहना पड़ता है। तब नारद जी के आग्रह पर कलयुगी समाज में सत्य की स्थापना करने का एक प्रयास है। इस फिल्म का लेखन 40 वर्षों से बॉलीवुड से जुड़े अरुण सिंह ने किया है। फिल्म का संयुक्त रूप से निर्देशन सुधाकर शर्मा और अरुण सिंह कर रहे हैं। सुधाकर शर्मा बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और स्थापित निर्देशक हैं। जो 2500 फिल्मी गीत लिख चुके हैं। इनमें सलमान खान की फिल्मों के लिए भी उन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं। सुधाकर शर्मा ने 'प्यार किया तो डरना क्या' फिल्म के लिए 'ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की...।' जैसे सुपर हिट गीत भी लिखे हैं। 'सत्य ही नारायण' फिल्म हिंदी फीचर फिल्म हैं, लेकिन इसके गढ़वाली और कुमाऊंनी वर्जन भी होंगे। फिल्म 'सत्य ही नारायण' की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत लोकेशन का चयन किया जा रहा है। इनमें नैनीताल जिले को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे आलोकनाथ, राजेंद्र गुप्ता, अनुपम खेर आदि के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए एक 19 से 22 साल की युवा जोड़ी को उत्तराखंड में ही तलाश किया जा रहा है। मनोरंजन संगीत से भरपूर इस फिल्म में सामाजिक समरसता का अनुभव दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश है।

इस फिल्म में आठ गीत होंगे जिनकी रिकार्डिंग का काम मुंबई में शुरू हो चुका है। कुछ गीत रिकार्ड हो चुके हैं, जिनको संगीतबद्ध किया है संगीतकार सतीश देहरा ने, इन गीतों को स्वर दे रहे हैं मशहूर गायक सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णा मूर्ति, अनूप जलोटा और उदित नारायण आदि। संगीतकार सतीश देहरा रविंद्र जैन के शिष्य हैं और उन्होंने 25 साल तक रविद्र जैन के साथ काम किया है। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने 'सत्य ही नारायण' फिल्म के लिए बहुत ही मलोडियस धुने तैयार की हैं, जो दर्शकों को 1970-80 के दशक के संगीत की यादें ताजा कराएंगी। फिल्म 'सत्य ही नारायण' की शूटिंग की संभावित तारीखों का ऐलान शीघ्र होगा, लेकिन फिल्म का प्री प्रोडेक्शन कार्य शुरू हो चुका है और मई 2026 में आउटडोर शूटिंग उत्तराखंड में की जाएगी। हमारी कोशिश है कि फिल्म को 2026 में ही रिलीज कर दिया जाए।

सुर्खियां

धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लटका

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत) ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक-2025 सरकार को लौटा दिया है। जबरन धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक को तकनीकि खामियों के कारण लोकभवन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ धामी सरकार को लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि लोकभवन ने विधेयक के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों की वजह से यह कदम उठाया है। उत्तराखंड विधायी विभाग को 16 दिसंबर को ही यह विधेयक मिला है। लोकभवन के अधिकारी अगस्त 2025 से इस विधेयक का अध्ययन कर रहे थे। माना जा रहा है कि विधेयक का ड्राफ्ट बनाते समय अफसरों ने सावधानी नहीं बरती थी। यानी संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया था। किस कानून के तहत कितनी सजा मिलनी है और किसमें नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया था। लोकभवन ने धर्मस्व विभाग और विधायी विभाग के अफसरों को दो बार बुलाकर उनसे चर्चा भी की फिर भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। भविष्य में कानूनी समस्याएं पैदा होने की संभावनाओं को भांपते हुए लोकभवन ने इस विधेयक पर सहमति की मुहर लगाने से हाथ पीछे खींच लिए और सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की सलाह के साथ इसे वापस भेज दिया। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने के लिए केवल दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या फिर अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित कराना पड़ेगा।

उत्तराखंड सरकार ने 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक लागू किया था। इसके बाद धामी सरकार ने 2022 में इस कानून में कुछ संशोधन करते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 लागू किया। जिसमें सजाओं को कुछ और बढ़ाया गया था। धर्मांतरण के मामले सामने आने पर 13 अगस्त 2025 को धामी सरकार ने सजा को और सख्त करते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को 20 अगस्त को गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी मिली थी। सरकार ने इसे विधेयक को कानूनी मंजूरी के लिए लोकभवन भेजा था। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) कानून-2025 के अनुसार धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया था। ऐसे मामलों में पुलिस को बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई थी। जमानत तभी दी जाएगी जब निचली अदालत (सत्र न्यायालय) को यह विश्वास हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है और अपराध को दोहराएगा नहीं। इस विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें किसी भी प्रकार का उपहार, रिश्वत, नकद धन या वस्तु के रूप में भौतिक लाभ, रोजगार, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना अथवा किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करना शामिल किया गया था। इसके अलावा यह सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देने या उकसाने जैसे कृत्यों को भी दंडनीय बनाया गया था।

धामी सरकार आपके द्वार

सरकार ने 17 दिसंबर से मेगा अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये मेगा अभियान शुरू किया गया है। 45 दिन के इस अभियान को 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' नाम दिया गया है। उत्तराखंड के सामान्य प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी डीएम को अभियान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक शिविर में डीएम को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। बाकी शिविरों में सीडीओ, एडीएम, एसडीएम अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इन शिविरों की पूरी रिपोर्ट सीएम और मुख्य सचिव कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन कार्यालय विभाग को देनी होगी। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील भी की है। सीएम के आदेश पर लगने वाले इन शिविरों में 23 विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शिविर में समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन, जाति और आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना या कटवाना, किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि और इसके सत्यापन की प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान कार्ड बनाने, बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान, रोजगार के लिए पंजीकरण और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। मेगा अभियान के दौरान सभी जिलों की न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे। बड़ी न्याय पंचायतों में दो स्थानों पर शिविर लगेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र लोगों से आवेदन भी भरवाएं जाएंगे। शिविर के बाद अधिकारी गांवों में जाकर पात्र लोगों से योजनाओं के फार्म भरवाएंगे।

राशन साफ कर रहे भालू

कंदमूल फल और जड़ी-बुटियों से भालुओं का अब मोह भंग होने लगा है। भालू लोगों के बंद घरों के दरवाजे तोड़ नमक, दाल, चावल और आटा आदि भोजन सामग्री चोरी कर रहे हैं। भालू अब तक मुनस्यारी के माइग्रेशन गांवों में 40 घरों के दरवाजे तोड़ चुके हैं। भालुओं की इस बदलती प्रवृति से विशेषज्ञ भी हैरान है। ग्रामीण अब भालुओं को राशन चोर कह रहे हैं। भालुओं के इस आतंक से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाले भालू आमतौर पर जड़ी-बूटी और कंदमूल ही खाते हैं। लेकिन अब भालुओं को लोगों के घरों में रखे राशन का स्वाद भाने लगा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी के माइग्रेशन गांवों में इन दिनों भालुओं ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल ठंड शुरू होने के बाद इन गांवों में रहने वाले लोग निचले इलाकों की तरफ लौट जाते हैं। मार्च तक ये इलाके बर्फ से ढके रहते हैं। इन इलाकों के लोग मार्च और अप्रैल तक अपने गांवों में लौटते हैं। लिहाजा उच्च हिमालयी क्षेत्रों के इन गांवों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के बंद घरों में लोग राशन भी छोड़ गए हैं। घरों में रखे नमक, दाल, चावल, गेहूं आदि खाद्यान्न की खुशबू भालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुछ दिन पहले ही ने मुनस्यारी के लास्पा में सरपंच बीरबल सिंह लस्पाल के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी खाद्य सामग्री भालुओं ने साफ कर दी। इधर धारचूला के बोन की सरपंच छोरी देवी का कहना है कि भालुओं ने दारमा घाटी के 14 गांवों में आतंक मचाया रखा है। कई घरों में तोड़फोड़ कर भालूओं ने राशन बर्बाद कर दिया है। कुछ घरों की छतें भी भालू तोड़ चुके हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि शीतनिद्रा में जाने से पहले भालू अधिक भोजन और ऊर्जा संरक्षित करते हैं। भोजन की तलाश करते हुए भालू आबादी के करीब पहुंच रहे हैं। माइग्रेशन गांव रालम के ग्रामीणों ने एसडीएम आशीष जोशी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि भालुओं ने गांव के अधिकांश घरों की छत, दरवाजे तोड़ दिए हैं, घरों के अंदर रखी खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा प्रशासन उन्हें मुआवजा दे।

महामंडलेश्वर अखाड़े से बाहर

श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि महाराज को तत्काल प्रभाव से अखाड़े से बाहर कर दिया है। अखाड़े ने उन पर यह कार्रवाई हरिद्वार अर्धकुंभ-2027 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक पर सवाल उठाने और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने पर हुई है। इस संबंध में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती महाराज ने कहा कि अखाड़ा व्यवस्था संत परंपरा, मर्यादा और सामाजिक आचरण के उच्च आदर्शों पर आधारित है और इन मूल्यों के विपरीत जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पद या प्रभाव का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। महंत मोहन भारती का कहना है कि इस प्रकरण में अन्य संतों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रमाण मिलने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दोनों ने सरकार और प्रशासन के विरोध में अनर्गल बयानबाजी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। यह सनातन विरोधी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रबोधानंद गिरी के विरुद्ध पूर्व में भी कई शिकायतें आई थीं, जिनमें उनके विरुद्ध हत्या का मामला भी है। जिसकी जांच चल रही है, जबकि स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज 2009 में भाजपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

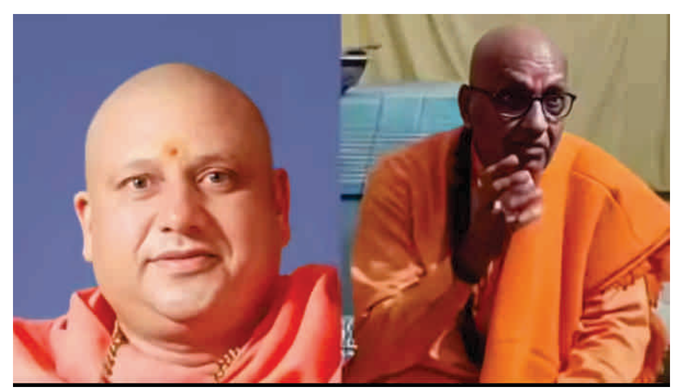

महंत मोहन भारती का कहना है कि ये लोग सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगामी कुंभ मेला बिगाड़ना चाहते हैं, जिससे सनातन धर्म की छवि खराब हो रही है। अब 2027 अर्धकुंभ मेले से पहले साधु-संत आपस में ही दो धड़ों में बंट गए हैं। पूर्व में भी स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने अखाड़ा परिषद के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने की परंपराओं से खिलवाड़ बताया था। जबकि 13 जनवरी 2027 को हरिद्वार में अर्धकुंभ का शुभारंभ होना है। अर्धकुंभ का पहला स्नान 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति के दिन होगा। इस बार प्रदेश सरकार और संतों की सहमति से इस आयोजन को महाकुंभ का नाम दिया जा रहा है। यह अर्धकुंभ 97 दिन चलेगा, जिसमें 4 प्रमुख अमृत स्नान यानी शाही स्नान होंगे।

कांग्रेस का घुसपैठिया प्रेम

संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को 'वोट चोरी' बताया, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने देते हुए जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर वोट चोरी करने का प्रमाण दिया तब पूरा विपक्ष सुनता रहा, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष संसद से पीठ दिखाकर भाग गया।

केके चौहान

संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मांग पर लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि यह चर्चा चुनाव सुधार पर तो बिल्कुल नहीं थी। चर्चा का केंद्र सिर्फ एसआईआर रहा। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने एसआईआर पर ही सवाल उठाए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में भी 'वोट चोर...वोट चोर' के नारे लगाते नजर आए। पहले 9 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को 'वोट चोरी' बता दिया, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर वोट चोरी करने का प्रमाण दिया तब पूरा विपक्ष सुनता रहा, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष संसद से पीठ दिखाकर भाग गया। संसद के बाहर निकल कर राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए अमित शाह के भाषण को डिफेंसिव बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में अमित शाह का व्यवहार सामान्य नहीं था। उन पर मानसिक दबाव था। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी ने कहा कि 'हमने जो पॉइंट्स रखे हैं, उनका जवाब गृह मंत्री ने नहीं दिया, वो डरे हुए हैं उनके हाथ भी कांप रहे थे।' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 'सबसे बड़ा देशद्रोह का काम वोट चोरी है।' उन्होंने कहा 'जब आप वोट को बर्बाद करते हैं, तो आप इस देश की बुनियाद को बर्बाद करते हैं, आधुनिक भारत को बर्बाद करते हैं, भारत के विचार को बर्बाद करते हैं।' राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि 'ब्राजील की एक महिला का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार आया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक महिला ऐसी भी है जिसका नाम हरियाणा के एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 200 से ज्यादा बार आया है।' 'यह बिल्कुल साफ है और मैंने बिना किसी शक के यह साबित किया है कि हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ है। ये वोट चोरी भारत के चुनाव आयोग ने सुनिश्चित की थी।' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी ओर से उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का जिक्र करते हुए कहा, 'ऐसा क्यों है कि बिहार में एसआईआर के बाद भी बिहार की वोटर लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटोज मौजूद हैं? अगर आपने वोटर लिस्ट साफ कर दी है, तो बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटोज क्यों हैं?' राहुल गांधी ने कहा, 'सबसे बड़ा एंटी नेशनल काम जो आप कर सकते हैं, वह है- वोट चोरी। वोट-चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है क्योंकि जब आप वोट को खत्म करते हैं, तो आप इस देश के ताने-बाने को खत्म करते हैं। आप मॉडर्न इंडिया को खत्म करते हैं, आप इंडिया के आइडिया को खत्म करते हैं। वोट चोरी एक एंटी नेशनल काम है और जो लोग सदन में दूसरी तरफ हैं, वे एंटी नेशनल काम कर रहे हैं।'

'आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, सभी प्रांतों के 28 कांग्रेस अध्यक्षों ने वोट सरदार पटेल दिया जबकि दो वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले और नेहरू प्रधानमंत्री बने, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी रायबरेली से वोट चोरी कर जीती, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहर लगाते हुए चुनाव रद्द कर दिया, उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन इंदिरा ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना।

अमित शाह ने कांग्रेस के धागे खोले

नौ दिसंबर को संसद में राहुल गांधी गरज रहे थे तो 10 दिसंबर को बारी गृह मंत्री अमित शाह की थी। विपक्ष के हर सवाल के जबाव में अमित शाह ने कांग्रेस के धागे खोलने शुरू कर दिए। कांग्रेस पर 'झूठ फैलाने और देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ताकि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाएं, जो 18 साल से बड़े हो गए हैं उनके नाम जुड़ जाएं, जो दो जगह मतदाता हैं उनके एक जगह से नाम कट जाएं और जो विदेशी नागरिक हैं उनको चुन-चुनकर हटाया जाए। अमित शाह ने सवाल किया कि 'क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, यह घुसपैठिए तय करेंगे? एसआईआर से कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। निर्णय करना पड़ेगा कि देश की संसद और विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं।' इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी की कथित फर्जी वोटर लिस्ट पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा, कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पांच नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉफ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। उस परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है बल्कि एक एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट में कई परिवार रह रहे हैं और घर का नंबर 265 ही है। यह फर्जी घर नहीं है और न ही फर्जी वोटर हैं। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए और अमित शाह से पूछा कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या चुनाव आयुक्तों को पूरी तरह माफी दी जाएगी, इसका जवाब दें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरी तीन प्रेस कॉफ्रेंस पर आइए और बहस करिए।

विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए

इस पर अमित शाह ने बेहद आक्रामकता से कहा, 'मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं, मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता कहते हैं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से संसद नहीं चलेगी। उनको धैर्य रखना चाहिए।' अमित शाह ने 'पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि तीन वोट चोरी की घटनाएं सदन और जनता को बताना चाहता हूं। 'आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों ने वोट दिया। 28 वोट सरदार पटेल को मिले और दो वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से वोट चोरी कर जीती, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई और इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना और देश में इमरजेंसी थोप दी थी।' इसके बाद अमित शाह घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा किया और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस वॉकआउट पर गृह मंत्री ने कहा कि वो तो घुसपैठियों पर बात कर रहे थे, जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया तब सब सुन रहे थे, लेकिन घुसपैठियों की बात पर सदन से ये क्यों भागे, हमारी घुसपैठियों को लेकर नीति है डिटेक्ट करो, नाम डिलीट करो और डिपोर्ट करो।

जब नेता प्रतिपक्ष को आइना दिखाया

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं

अमित शाह ने बेहद आक्रामकता से संसद में कहा, 'मैं 30 साल से जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं, मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है, विपक्ष के नेता कहते हैं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, उनको धैर्य रखना चाहिए।'

कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'प्रोजेक्ट' के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया। राहुल ने सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया ताकि किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके। इनके जबाव में अमित शाह ने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल बनाया, कैसे चुनाव आयुक्तों को संसद पहुंचाया। अमित शाह ने राहुल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थाओं पर कब्जे वाले सवाल पर जबाव दिया कि संविधान में कहा लिखा है कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों की किसी संस्था में तैनाती नहीं की जा सकती? उन्होंने राहुल के ज्ञान को आइना दिखाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस की विचारधार रखते हैं। मैं देश का गृह मंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधार से ताल्लुक रखता हूं।

पार्ट टाइम राजनीति

दरअसल राहुल गांधी पार्ट टाइम राजनीति करते हैं ये एक-दो बार नहीं बल्कि बार-बार साबित होता है। वो मानकर बैठे हैं कि जिस दिन भाजपा के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होगी उस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए वो राजनीति का ज्यादा सिरदर्द नहीं लेते। वो देश के राज्यों के मुकाबले विदेश के दौरे ज्यादा करते हैं। ऐसा इंडिया गठबंधन के साथी दल समाजवादी पार्टी के नेता एपी सिंह का भी मानना है। उनका राजनीति करने का अपना अलग अंदाज है, यानी बिना सिर पैर के आरोप लगाकर निकल जाओ। आरोपों का जबाव मिले तो संसद छोड़ कर भाग जाओ। इसलिए दस दिसंबर को जब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं के आरोपों का जबाव देना शुरू किया तो पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ वॉकआउट कर गया। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी को अपनी 'हिट एंड रन' वाली आदत छोड़नी होगी। अगर वे बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार हम भी उन्हें सदन में बोलने नहीं देंगे। इससे लगता है कि संसद का शीतकालीन सत्र अभी और गरम होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी तो शीतकालीन सत्र छोड़कर जर्मनी निकल गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सत्र नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चलेगी। लिहाजा सरकार के लिए काम आसान हो सकता है। उसके सभी अध्यादेश आसानी से पारित हो सकते हैं।

एसआईआर के बहाने एनआरसी

इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि सरकार 'एसआईआर के बहाने एनआरसी' कर रही है। ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा यह 'एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है।' एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) वालों को निकाल देंगे।' उन्होंने पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को डराते हुए कहा कि याद रखो जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया। फिर आरक्षण छीन लेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) के बाद निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का एलान किया था, जहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। संसद में इस पर 10 दिसंबर को भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव आयुक्त के चयन के लिए कानून बना, उसमें प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता भी हैं।●

राहुल से लोकतंत्र को खतरा

देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस पर सवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र किसी हथियार से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जहरीली बयानबाजी का हमला झेल रहा है, भारत का लोकतंत्र जहरीले बयानों की वजह से खतरे में है।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

भारत के लोकतंत्र को खतरा न केंद्र की सरकार से है और न ही भाजपा अथवा स्वयंसेवक संघ से है, असल में भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वामपंथी सोच के कांग्रेसी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंड कंपनी है। जो अपनी राजनीतिक हताशा-निराशा और नाकामी छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, राहुल गांधी ने ही नेपाल की तरह भारत के जेन जी को भी भड़काने की कोशिश की, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जेन जी ने ऐसा करारा जबाव दिया कि राहुल गांधी की कांग्रेस महागठबंधन के बावजूद 19 सीटों से सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। ईवीएम हैक, चौकीदार चोर, जातिय जनगणना, हिंडनबर्ग, अडानी-अंबानी, पाकिस्तान, चीन का झूठा नैरेटिव नहीं चला तो भारत की उस संवैधानिक संस्था के खिलाफ वोट चोरी का नारा लगाया जिस चुनाव आयोग की निष्पक्षता की वजह से खुद राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा सदस्य हैं। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता की वजह से ही राज्यसभा सदस्य हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष न होता तो सोचिए क्या गांधी परिवार संसद में घुस पाता? राहुल गांधी भारत के लिए वो खतरा है जो देश की हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं, देश से लेकर विदेश तक में भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। आपरेशन सिंदूर के बाद चीन के इशारे पर सबसे पहले राहुल गांधी ने ही सवाल किया था कि भारत सरकार बताए कि पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जैट रफाल गिराए हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हैं। कहते हैं कि परमाणु बम जब फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। वो धमकी देते हैं कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, वो उन्हें रिटायर होने के बाद भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों, जिसमें 16 पूर्व न्यायाधीश, 14 पूर्व राजदूत सहित 123 रिटायर्ड नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने एक खुला पत्र जारी करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इन हस्तियों ने कहा कि भारत का लोकतंत्र किसी हथियार से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जहरीली बयानबाजी का हमला झेल रहा है। भारत का लोकतंत्र जहरीले बयानों की वजह से खतरे में है।

कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत्र ने जबाव दिया कि वोट चोरी के इतने सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधने वालों में कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, पूर्व राजदूत विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, सुरक्षा एर्जेसी वाले दिल्ली ब्लास्ट में विफल खुफिया एर्जेसी पर नहीं बोल रहे हैं, सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं।

चुनाव आयोग पर अटूट विश्वास

खुले पत्र में सीधे-सीधे बिना किसी लाग लपेट के आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस व राहुल गांधी द्वारा सैन्य बलों, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई, आईटी और संसद पर सवाल उठाने के बाद अब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया, 'एटम बम' 'हाइड्रोजन बम' जैसी भाषा इस्तेमाल की। यहां तक कहा कि आयोग 'देशद्रोह' कर रहा है, लेकिन अपने इन दावों के समर्थन में किसी सक्षम अधिकारी के सामने आज तक कोई औपचारिक शिकायत या शपथ पत्र नहीं दिया। खुले पत्र के अनुसार, बिना सबूत के लगाए जाने वाले आरोप एक 'क्रोध' का रूप हैं, ऐसा गुस्सा जो बार-बार चुनावी हार और जनता से दूरी के कारण पैदा हुआ है। आगे कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल विश्लेषण की जगह नाटकीयता को चुन रहे हैं और सार्वजनिक सेवा की जगह राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं। देश की हस्तियों ने लिखा कि जब किसी विपक्ष शासित राज्य में चुनाव आयोग के परिणाम विपक्ष के अनुकूल होते हैं, तब उसकी आलोचना गायब हो जाती है। लेकिन जब परिणाम उनके खिलाफ आते हैं, तब आयोग को हर कहानी का खलनायक बना दिया जाता है। इसलिए उन्हें यह चुनिंदा नाराजगी राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण लगती है। वरिष्ठ नागरिकों के खुले पत्र में टीएन शेषन और एन गोपालस्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का उल्लेख करते हुए लिखा कि उन्होंने लोकप्रियता या सुर्खियों के बजाय निष्पक्षता और कड़ाई से नियमों का पालन कराया। वरिष्ठ नागरिकों का मानना है कि भारत की संस्थाओं को राजनीतिक हमलों का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, यही परंपरा देश को मजबूत बनाती है। पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पारदर्शिता बनाए रखे, सभी आंकड़े सार्वजनिक करे और आवश्यक होने पर कानूनी तरीकों से अपना बचाव करे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे 'बिना सबूत वाले आरोपों' की जगह नीतिगत विकल्प और देश के लिए ठोस दृष्टि पेश करें। पत्र में देश की वरिष्ठ हस्तियों ने भारतीय सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विशेष रूप से चुनाव आयोग पर अपना अटूट विश्वास जताते हुए यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और अब समय आ गया है कि राजनीति, नाटकीयता नहीं, बल्कि सत्य, विचार और सेवा के आधार पर आगे बढ़े।

चुनाव आयोग के खिलाफ षडयंत्र

देश के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुले पत्र के माध्यम से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी व कांग्रेस भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने का प्रयास करते हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर सवाल उठाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। अब भारत के चुनाव आयोग पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमले किए जा रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी और मृत वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग को भाजपा की बी-टीम बताना एक राजनीतिक हताशा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता वास्तविक राजनीतिक विकल्प देने की बजाय भड़काऊ और तथ्यहीन आरोपों के जरिये अपनी सियासी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर-नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान को ही लोकतांत्रिक की आधारशिला माना जाता है। भारत के चुनाव आयोग को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए। वरिष्ठों ने चुनाव आयोग से अपील की कि वह चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करे। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा कि वे बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें।

राहुल गांधी ने बार-बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया, 'एटम बम' 'हाइड्रोजन बम' जैसी भाषा इस्तेमाल की, यहां तक कहा कि आयोग 'देशद्रोह' कर रहा है, लेकिन अपने इन दावों के समर्थन में किसी सक्षम अधिकारी के सामने आज तक कोई औपचारिक शिकायत या शपथ पत्र नहीं दिया।

बांग्लादेशी व रोहिंग्या वोट क्यों करें?

खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा,'हम अपने देशवासियों को यह बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना और सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर भी हमला किया है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर कर रहा है, तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। जिन लोगों ने धोखाधड़ी से वोटर आईडी हासिल की है उन्हें भारत में चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक बांग्लादेशी या रोहिंग्या को भारत में चुनाव में वोट क्यों देना चाहिए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को निशाना बनाकर एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रखा है। उन्हें एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जब कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में थी तब बूथ कैप्चरिंग और पुनर्मतदान होता था। राहुल गांधी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग के बारे नहीं बल्कि अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।' उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 'मैं हाइड्रोजन बम और परमाणु बम निर्यात करने की बात कहने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं। हमें अपनी न्यायपालिका, चुनाव आयोग और कार्यपालिका पर पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाना और यह कहना कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन पर कार्रवाई की जाएगी, बेहद गलत व शर्मनाक है। विपक्ष के नेता को ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। न केवल देश, बल्कि हम सभी एकजुट हैं, इसलिए हमने इस खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्लीज राहुल गांधी अपने आरोपों में संयम बरतें क्योंकि उनमें कोई दम-खम नहीं है।' पूर्व न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा ने कहा, 'पिछले कुछ समय से, विपक्ष के नेता, लोकसभा सांसद राहुल गांधी नियमित रूप से भारत के चुनाव आयोग पर बेबुनियाद हमले कर रहे हैं। वह एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। केवल एक नासमझ व्यक्ति ही एसआईआर के खिलाफ विरोध कर सकता है। केवल आतंकवादी ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वे 'एटम बम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के ऐसे व्यवहार को न तो माफ करना चाहिए और न ही बर्दाश्त करना चाहिए।'

कांग्रेस का पलटवार

पूर्व न्यायाधीशों, सेवानिवृत नौकरशाहों और पूर्व राजदूतों व पूर्व सैन्य अधिकारियों के खुले पत्र पर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत्र ने जबाव दिया। सुप्रिया ने कहा कि वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे। पूर्व राजदूत विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, सुरक्षा एजेंसी वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली लालकिले पर बम ब्लास्ट की विफल खुफिया एजेंसी पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र ने खुला पत्र लिखने वालों को सलाह देते हुए कहा कि असलियत तो ये है कि 2014 से पहले जिम्मेदार, प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, आखिर जिसके पास सत्ता संसाधन और संस्थान हैं, सवाल भी तो उसी होंगे। लेकिन अब सवालों के घेरे में वो व्यक्ति है जो इस देश के लोकतत्र की धज्जियां उड़ने के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। इन प्रतिष्ठित नागरिकों में से कितनों में यह साहस है कि फर्जी पते फर्जी आईडी, फर्जी फोटा, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं। इनमें से कितनों में यह साहस है कि चुनाव के बीचों बीच सरकार पैसे बांटती रही और चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा? आखिर इन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे।

पहाड़ी धरोहर गागर गायब

उत्तराखंड में तांबे के बर्तनों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है, यहां पुराने दौर में तांबे के बर्तनों में भोजन बनाने और खाने की प्रथा थी, तांबे को एकदम शुद्ध और सेहत के लिए रामवाण माना गया है, इसलिए लोग तांबे के बर्तनों में ही खाना पकाते थे और तांबे के बर्तनों में रखा हुआ शुद्ध पानी पीते थे।

कमल कपूर
अल्मोड़ा

मानव सभ्यता में जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन का महत्वपूर्ण स्थान है यानी हमारी जीवनशैली 'ज' पर निर्भर है और ये सब कहीं न कहीं हमारी प्राचीन सभ्यता, आस्था और धार्मिक आयोजनों के प्रतीक भी हैं सदियों से ये अपना स्थान बनाए हुए हैं। यह भी सच है कि पहाड़ की संस्कृति और लोक जीवन में अनेक रंग हमारी जीवनशैली को, हमारे लोक को दर्शाते हैं। उत्तराखंड का वो जिला जो अपनी पहचान सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नगर के रूप में रखता है, जी हां यही अल्मोड़ा है। यहां की कला और संस्कृति व इतिहास इस शहर को और जिलों से अलग बनाता है। साहित्य, कला हो या राजनीति इस शहर के कई बड़े हस्ताक्षर देश विदेश में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी इस शहर में पहुंचे और यहां कई स्थानों पर तपस्या की। स्व.गोविंद बल्लभ पंत, स्व.सुमित्रानंदन पंत, मुरली मनोहर जोशी, प्रसून जोशी और बद्री दत्त पांडे जैसे लोगों का यह शहर अपनी संस्कृति ही नहीं बल्कि अपनी ताम्र कला के लिए भी देश विदेश में पहचाना जाता रहा है। उत्तराखंड में तांबे के बर्तनों का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है, यहां पुराने दौर में तांबे के बर्तनों में भोजन बनाने और खाने की प्रथा थी। तांबे को एकदम शुद्ध और सेहत के लिए रामवाण माना गया है, इसलिए लोग तांबे के बर्तनों में ही खाना पकाते थे और तांबे के बर्तनों में रखा हुआ पानी पीते थे। तांबे के तौले (भात पकाने के लिए बड़े बर्तन) भड्डू (दाल बनाने के लिए बड़े बर्तन) गागर (गगरी) केसरी, फिल्टर, लोटे, दीये प्रमुख थे, जिनकी मांग हमेशा से बाजार में रहती थी। उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों में तुतरी, रणसिंह और भौखर हमेशा से प्रमुख रहे हैं, जिन्हें तांबे से ही बनाया जाता था और यह सारे काम हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले कारीगर ही किया करते थे। आज से 15 साल पहले अल्मोड़ा में करीब डेढ़ सौ परिवार तांबे के कारखानों में हैंडीक्राफ्ट का काम किया करते थे।

हस्तशिल्प मजदूरों की रोजी रोटी छिनी

एक जमाना था जब अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ले की गलियों से गुजरते हुए हर समय टन...टन...टन...की आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज तांबा हस्तशिल्पकारों के घरों से आती थी। क्योंकि दिन रात मेहनत करके वह ताबे के बड़े आकर्षक बर्तनों को आकार दिया करते थे। उस दौर में अल्मोड़ा के तांबा हैंडीक्राफ्ट का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोलबाला था। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते रहे यह आवाजें गायब सी होती गई। एक दौर ऐसा भी था जब अल्मोड़ा कि हर दुकान में आपको 'गगरी' नजर आती थी जिसे स्थानीय भाषा में 'गागर' भी कहा जाता है। परंपरा यह थी की लड़की की शादी में 'गगरी' शगुन के रूप में देना अनिवार्य था। इसे शुभ भी माना जाता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि एक ही शादी में एक से अधिक 'गगरी' मिल जाती थी। नववधु के आगमन पर धारा पूजने की रस्म और फिर उसी जल स्रोत से तांबे की गागर में जल भरकर घर लाना गागर के महत्व को बताता है। लेकिन समय के साथ तांबे की जगह स्टील व एल्यूमीनियम के बर्तनों ने ले ली। तौली व भडडू की जगह कुकर ने ले ली तो गागर की जगह स्टील की गगरी ने ले ली। लिहाजा तांबा कारीगरों को इस बात की चिंता सताने लगी कि देश में जब मशीनीकरण हो जाएगा तो शायद उनका काम भी छिन जाएगा, हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसे-जैसे तांबे के काम को मशीनों के जरिए किया जाने लगा हस्तशिल्प मजदूरों के हाथ से मानो काम ही नहीं बल्कि रोजी-रोजगार भी छिन गया।

अल्मोड़ा के जिस टम्टा मोहल्ले में एक जमाने में हस्तशिल्पकारों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, आज उसी टम्टा मोहल्ले की हालत यह है कि उनके पास काम ही नहीं है, क्योंकि व्यापारी मशीनों से मुनाफा भी कमा रहे हैं और कम समय में ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं।

तांबा कारीगरों के पास काम नहीं

जिस अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ले में एक जमाने में हस्तशिल्पकारों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, आज उसी टम्टा मोहल्ले की हालत यह है कि उनके पास काम ही नहीं है। क्योंकि व्यापारी मशीनों से मुनाफा भी कमा रहे हैं और कम समय में ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं। अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ले में रहने वाले तांबा हैंडीक्राफ्ट के कारीगर सुनील टम्टा का कहना है कि 'अब तो ऐसा लगता है कि शायद तांबा कारीगरी का यह हुनर उनकी पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगा। नई पीढ़ी इस काम को नहीं करना चाहती है। क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है और कमाई ना के बराबर है।' सुनील टम्टा कहते हैं की 'एक वह भी दौर था जब वह महीने भर तांबे के बर्तनों का आर्डर भी पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती थी और सभी लोग हैंडीक्राफ्ट के काम को ही पसंद करते थे। महंगा होने के बावजूद लोग तांबे के बर्तन खरीदते थे। शादियों के सीजन में 'गगरी' और 'तांबे के तौले' बनाने का काम उनके पास सबसे ज्यादा रहता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनको बाजार में जाकर काम मांगना पड़ता है।' सुनील टम्टा कहते हैं कि अब मशीनों से तांबे का काम ज्यादा हो रहा है, समय बच रहा है और उत्पादन भी ज्यादा मिल रहा है। मशीनों से किया गया काम हैंडीक्राफ्ट की तुलना में सस्ता है, इसलिए व्यापारी भी मशीनों से ही काम करवा रहे हैं उनके पास अब वो काम आ रहा है जो मशीनों से नहीं किया जा सकता है या जो बर्तन पुराने हो गए हैं उन्हें नई चमक देनी है। सरकार से भी तांबा हैंडीक्राफ्ट कारीगर नाराज नजर हैं, क्योंकि सरकारें वादा करती रही कि अल्मोड़ा की ताम्र नगरी को बेहतर और आधुनिक बनाया जाएगा लेकिन 1992 में बनाई गई ताम्र नगरी में आज भी तकनीकी के मामले में सन्नाटा है। अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टम्टा शिल्प कला संस्थान ने तांबा हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में प्रगति के सपने भी दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मशीनों से काम सुगमता और कम समय में ज्यादा उत्पादन के तौर पर हो रहा है इसलिए लोग हैंडीक्राफ्ट की ओर कम जा रहे हैं।

तांबे के गागर में शुद्ध होता था पीने का पानी

ये वो दौर था जब लोग लगभग एक या आधा किलोमीटर दूर से पीने का शुद्ध पानी भरकर लाया करते थे। क्योंकि गांव की आबादी पानी के स्रोत से लगभग दूरी ही हुआ करती थी जिसके बहुत सारे कारण भी रहे होंगे। वो चाहे स्वास्थ या स्वच्छता के हिसाब से रहा हो, धर्मिक मान्यताओं की वजह से या कुछ और ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। घरेलू काम में सुबह उठकर सबसे पहले ताजा पानी भरना रोज का नियम होता था और ये दिन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम भी था। गागर में पानी भरकर लाना वो भी कम मुश्किल काम नहीं होता था पर पहाड़ी जीवनशैली में उतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि पहाड़ी लोग रोजमर्रा की जीवनशैली में इन कामों को आसानी से कर लेते हैं। एक समय वो भी था जब लोग पहाड़ में 'फिल्टर' और 'आरओ' जैसी तकनीक से बिल्कुल अनजान थे। लोग परिचित थे तो सिर्फ गागर से या मिट्टी के घड़े से। यही पहाड़ी फिल्टर और आरओ होते थे। पानी को तांबे की गागर में भर कर रखा जाता था तो उसका स्वाद और मीठा हो जाता था। पहाड़ी क्षेत्र में 12 महीने पानी की जलधारा बहती थी, जो कभी दूषित नहीं बल्कि मौसम के अनुसार सर्दियों में गरम और गर्मियों में ठंडा पानी देती थी। लेकिन आज समस्या ये है कि न जल स्रोत बचे न गागर घर के अंदर दिख रही है। क्योंकि जल संस्थान और जल जीवन मिशन और न जाने सरकारी महकमे की बड़ी-बड़ी योजनाओं ने हमारे जल स्रोतों और हमारी तांबे की गागर की संस्कृति को निगल लिया है। जल धाराओं के जीर्णोद्वार के नाम पर सीमेंट और कंक्रीट के निर्माण से जल स्रोत सूख गए हैं। लिहाजा जब जल धाराएं ही नहीं बची तो तांबे की गागर कैसे बचेगी?

हर घर नल से जल

सरकार का दावा है कि हर घर में पानी के लिए नल पहुंचाया जाएगा। नल तो पहुंच गए पर पानी नहीं पहुंचा और यदि पानी पहुंच भी जाए तो उसकी स्वच्छता की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि बरसात में गंदा पानी नल से निकलना आम बात है। इसलिए पहाड़ के घरों में तांबे के गागर जैसे बर्तन जो पानी को फिल्टर करते थे, गायब हो गए। उनकी जगह फिल्टर और आरओ जैसी तकनीक ने ले ली है। तांबे की गागर सिर्फ पहाड़ी गानों में, शादी ब्याह और धार्मिक आयोजनों में एक रस्म अदायगी भर दिखती है। लोग आज भी बेटी को दहेज में गागर तो देते है पर उसके महत्व को समझाने का एक छोटा सा प्रयास भी कर लें तो आज इस बर्तन की उपयोगिता हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली में हो सकती है। यह हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है। क्योंकि जिस तरह समय बदला है उसी तरह तांबे की गागर की जगह प्लास्टिक के गागर नुमा बर्तन भी गांव पहुंच गए हैं। आज जब पानी की पाइप लाइन ने पानी को घर-घर पहुंचा दिया है तो पानी की स्वच्छता और गुणवत्ता में फर्क आया है। पानी के स्रोतों की साफ सफाई न होने से लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का एक ही कारण होता है और वो है दूषित पेयजल लिहाजा अब जरूरत है, पानी के जल स्रोतों के संरक्षण की, उनकी स्वच्छता की और तांबे की गागर की। जिससे एक बार फिर से चरित्रार्थ होती वो कहावत 'गागर में सागर' नजर आएगी वरना आने वाली भावी पीढ़ी तांबे की गागर और जल स्रोतों की विलुप्तता का जिम्मेदार अपने पूर्वजों को मानेंगी। सरकार को तांबा कारीगरों को स्किल युक्त बनाने की जरूरत है। मशीनों के तौर पर उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए जिससे वह मशीनों के जरिए भी अपना कार्य कर सकें। तांबा हैंडीक्राफ्ट का काम विदेशों में भी बड़े पैमाने पर पसंद किया जाता है। अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमने आने वाले पर्यटक काफी मात्रा में तांबे के बर्तन खरीदते हैं। विदेशों से बड़े पैमाने पर इनकी डिमांड भी आती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि तांबा हैंडीक्राफ्ट को बचाने के लिए योजनाएं शुरू की जाए। वरना अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट इतिहास बन जाएगा और इस कला को किताबों में पढ़ाया जाएगा।

- **पहाड़ी लोगों की रोजमर्रा की जीवनशैली एक समय वो भी था जब लोग पहाड़ में 'फिल्टर' और 'आरओ' जैसी तकनीक से बिल्कुल अनजान थे, लोग परिचित थे तो सिर्फ तांबे की गागर से या मिट्टी के घड़े से, यही पहाड़ी फिल्टर और आरओ होते थे, पानी को तांबे की गागर में रखा जाता था तो उसका स्वाद और मीठा हो जाता था।**
- **अल्मोड़ा के तांबा हैंडीक्राफ्ट को विदेशों में भी पसंद किया जाता है, अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटक काफी मात्रा में तांबे के बर्तन खरीदते हैं, विदेशों से बड़े पैमाने पर इनकी डिमांड भी आती है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि तांबा हैंडीक्राफ्ट को बचाने के लिए ठोस योजना शुरु की जाए।**

सुकून मिलता है कनातल गांव में

उत्तराखंड अब ग्रामीण पर्यटन के लिए ज्यादा विख्यात हो रहा है, पर्यटकों को गांवों की सुंदरता, होमस्टे, पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ियों की जीवनशैली के करीब रहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उत्तराखंड के गांव अब केवल पहाड़ी बस्ती नहीं रहे बल्कि हिल स्टेशन बन रहे हैं, ऐसा ही गांव कनातल है जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है।

हरीश भट्ट
रामनगर

देवभूमि उत्तराखंड औली, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, रानीखेत और चारधाम केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री जैसे तीर्थाटन और पर्यटन के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों के लिए पॉपुलर है। लेकिन सच में उत्तराखंड अब ग्रामीण पर्यटन के लिए ज्यादा विख्यात हो रहा है। पर्यटकों को गांवों की सुंदरता, होमस्टे, पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ियों की जीवनशैली के करीब रहने का अवसर मिल रहा है। इसलिए उत्तराखंड के गांव अब केवल पहाड़ी बस्ती नहीं रहे बल्कि हिल स्टेशन बन रहे हैं। ऐसे ही बहुत से बेहद खूबसूरत गांव पर्यटकों की नजरों से अब तक बचे हुए थे। इनमें ही एक गांव कनातल है जो हिमालय की गोद में बसा होने के कारण शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश करने वालों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस बार शीतकालीन छुट्टियों में उत्तराखंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस अनदेखे हिल स्टेशन कनातल गांव का प्लान बना सकते हैं। यह क्षेत्र अपने शांत और खूबसूरत परिवेश, मनमोहक दृश्यों और साफ सुथरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। कनाताल आपके मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा करने के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है। हालांकि यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से अभी अविकसित है और व्यावसायीकरण से अछूता है। लिहाजा सामूहिक पर्यटन से जुड़ी हलचल और व्यवस्था के बिना, पर्यटक कनाताल के दर्शनीय स्थलों के साथ स्थानीय लोगों की वास्तविक संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि यह अविकसित गांव अपने मनमोहक प्राकृतिक वैभव, हरे-भरे जंगलों, पहाड़ों और स्वच्छ जलधाराओं के लिए पहचान बना रहा है। अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, कनाताल उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो रोमांच पसंद करते हैं। यह क्षेत्र रोमांच और रोमांच की तलाश करने वालों के लिए एकदम सही है क्योंकि यहां ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और रैपलिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के ट्रैकिंग मार्ग चुनौतीपूर्ण होने के साथ रोमांचक भी हैं, और इनसे मनमोहक दृश्य भी दिखाई देते हैं।

मेहमाननवाज ग्रामीण

कनातल गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यहां कई जनजातियां हैं जिनके अनोखे रीति-रिवाज, लोकगीत और लोकनृत्य हैं। साल भर त्योहारों और मेलों में भाग लेने से आगंतुकों को स्थानीय जीवन शैली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। कनातल के निवासियों के साथ बातचीत निस्संदेह आप पर एक अमिट छाप छोड़ेगी, क्योंकि वे मिलनसार और मेहमाननवाज हैं। कनातल का एक और आकर्षक पहलू यहां के पारंपरिक व्यंजन है। यहां का क्षेत्रीय भोजन सादा लेकिन उत्कृष्ट है, जिसमें ताजी और स्थानीय सामग्री का ही इस्तेमाल होता है। फानू, चैनसू और बादी जैसे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न हस्तशिल्प और स्मृति चिह्नों से बने सुंदर उपहार और यादगार वस्तुओं के साथ, स्थानीय बाजार कनातल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक हैं। देवभूमि का कनातल गांव उन सभी पर्यटकों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन कहा जा सकता है जो रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से सुकून की तलाश में रहते हैं। यह जगह पाक-कला, संस्कृति, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श संगम है, जो आपको अनमोल यादे देता है। कनातल में कौड़िया वन विभिन्न पौधों, वनस्पतियों, औषधियों और पशु प्रजातियों का एक हरा-भरा जंगल है। अगर आप भाग्यशाली रहे, तो आपको भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर, तेंदुआ, हिमालयी लोमड़ी, हिमालयी गिद्ध और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जंगल में टहलते हुए प्रकृति के वैभव का आनंद ले सकते हैं। यदि वन्यजीवों और पक्षियों में रुचि रखते हैं, तो यह जंगल कनातल में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है, क्योंकि यहां पक्षी की कई प्रजातियों का घर है। इसलिए पक्षी देखने की उत्कृष्ट संभावनाओं के लिए। आप किराए पर वाहन ले सकते हैं क्योंकि यह ट्रैक मोटर वाहन के लिए उपयुक्त है, जो एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट की ओर ले जाता है।

आप भाग्यशाली रहे, तो आपको भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर, तेंदुआ, हिमालयी लोमड़ी, हिमालयी गिद्ध और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकते हैं, जंगल में टहलते हुए प्रकृति के वैभव का आनंद ले सकते हैं, कनाताल का जंगल दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियों का घर भी है।

बर्फ से ढके हिमशिखर

उत्तराखंड के टिहरी जिले का कनातल गांव इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा केंद्र बिंदु है। कनातल पॉइंट, अद्‌भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है जो वीडियो बनाने के लिए एकदम सही हैं। पहाड़ की चोटी तक चढ़ाई कठिन है। कनातल की चोटी पर जाने के लिए किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। चोटी पर पहुंच कर बर्फ से ढके हिमशिखर का अदभुत दृश्य नजर आएगा। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का समय कनातल से हिमालय की पर्वतमाला देखने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन महीनों में आमतौर पर आसमान साफ रहता है और पर्वतमाला साफ नजर आती है। कनातल के पास स्थित सुरकंडा देवी मंदिर, एक पूजनीय शक्तिपीठ है, यहां देवी सती का सिर गिरा था। यह मंदिर अक्सर आसमान की धुंध से ढका रहता है और कद्दूखाल से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है, जहां आप अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। यहां एक रोपवे सेवा भी है, जहां से आप पर्वतों के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। आध्यात्मिकता और शांति की अंतर्निहित भावना, जो मंदिर परिसर के भ्रमण के दौरान आपको शांति और सुकून का अहसास करा सकती है। कनातल में बाजार भी है जहां पर्यटक न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि खरीदारी भी कर सकते हैं। यह जीवंत बाजार उत्तराखंड की पारंपरिक वस्तुओं और गहनों को देखने और खरीदने के लिए उपयुक्त है। पर्यटक चीनी मिट्टी से बने सामान, लकड़ी के हस्तशिल्प और ऊनी शॉल खरीद सकते हैं। सर्दियों का मौसम कनातल बाजार घूमने का सबसे अच्छा समय होता है।

कनातल एक छिपा रत्न

देवभूमि उत्तराखंड का टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कनातल के पास ही है। यह बांध भी लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है जो आसपास के पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों के दर्शन करता है। पर्यटक बांध के किनारे आराम से टहल सकते हैं या अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। जलाशय की झील में नौका विहार और अन्य जल क्रीड़ाओं का भी आनंद ले सकते हैं। कनातल स्थित पहाड़ी हाउस में स्थानीय ग्रामीण संस्कृति का भी अनुभव कर सकते हैं। यहां योगा रिट्रीट ग्रामीण घरों की तरह बना है और आयुर्वेदिक मालिश और जैविक भोजन उपलब्ध करता है। इसलिए कह सकते हैं कि कनातल एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर किसी के लिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। चाहे वो बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने वाले हों, रोमांच की तलाश में हों या आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की तलाश करने वाले हों। यानी कनातल निस्संदेह एक छिपा हुआ रत्न है जो अपने हरे-भरे जंगलों, ऊबड़-खाबड़ चोटियों, साहसिक गतिविधियों, शांत मंदिरों, जीवंत बाजारों, मनमोहक बांधों और सुखदायक विश्राम स्थलों, होमस्टे के साथ पर्यटकों का इंतजार करता है।

- **कनातल में बाजार भी है जहां पर्यटक न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि खरीदारी भी कर सकते हैं, यह जीवंत बाजार उत्तराखंड की पारंपरिक वस्तुओं और गहनों को देखने और खरीदने के लिए उपयुक्त है, पर्यटक चीनी मिट्टी से बने सामान, लकड़ी के हस्तशिल्प और ऊनी शॉल खरीद सकते हैं, सर्दियों का मौसम कनातल बाजार घूमने का सबसे अच्छा समय है।**
- **कनातल ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने वाले हों, रोमांच की तलाश में हों या आध्यात्मिकता और शांति की तलाश करने वाले हों, यानी कनातल एक छिपा हुआ रत्न है जो हरे जंगलों, ऊबड़-खाबड़ चोटियों, शांत मंदिरों, जीवंत बाजारों, विश्राम स्थलों, होमस्टे के साथ पर्यटकों का इंतजार करता है।**

कनातल विंटर वंडरलैंड से कम नहीं

कनातल छोटा सा लेकिन विचित्र गांव है। यहां आपको शानदार हिमालय और घाटी के अद्‌भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। कनातल से न केवल पवित्र बदरीनाथ पर्वतमाला देख सकते हैं, बल्कि कभी न देखे गए नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको हाइकिंग करना पसंद है, तो उत्तराखंड आते समय कनातल को अपनी घूमने की लिस्ट में शामिल कर लें। पहली बार ट्रैकिंग करने वाले लोग सुरकंडा देवी मंदिर या बटवालदार वन की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप धनौल्टी या रानी चौरी वन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा कनातल और इसके आसपास बहुत से ट्रैकिंग ऑप्शन भी हैं। सुमद्र तल से 8500 मीटर की ऊंचाई पर बसे होने के कारण सर्दियों में कनातल किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं लगता। हिमालय के खूबसूरत नजारों से लेकर पहाड़ों और टिहरी डैम के बीच कैंपिंग तक कनातल ही है जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर देगा। कनातल के पास टिहरी झील एक गर्म जगह है। लेकिन वाटर स्पोर्ट्स और चलते-फिरते होटल गर्म मौसम को भुला देते हैं। लिहाजा वीकेंड की छुट्टी के लिए कनातल का चयन कर सकते हैं। जो शोर और भीड़-भाड़ से दूर इस छोटे से हिल स्टेशन पर आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगा। कनातल के होम स्टे अपनी साफ-सफाई, स्वच्छता और अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध है। होमस्टे में स्थानीय और जैविक भोजन परोसा जाता है। यदि आप सर्दियों में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो गर्म कपड़े जरूर लाएं क्योंकि कनातल का मौसम बहुत ही मनमौजी होता है।

कनातल के ऊंचे पहाड़ों और हरे-भरे जंगलों के बीच बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अद्‌भुत है। यहां ताजी हवा और विविध वनस्पतियों और जीवों के कारण, यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बनने जा रहा है। खुला नीला आकाश और हिमालय की चोटियों पर बर्फ की चादर प्रकृति प्रेमियों को मौन निमंत्रण देती है। उत्तराखंड का कनातल अपनी जैविक खेती, अखरोट, शाहबलूत, ताजा सेब आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का आनंद लेने के इच्छुक सैलानियों के लिए कनातल का मौसम बेहद अनोखा रहता है। कनातल की सुबह और शाम अद्‌भुत होती है। हरे-भरे जंगलों की ठंडी हवाएं हिमालय में होने का एहसास कराती हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि कनातल तक पहुंचना भी आसान है। स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया का कोई भी हिल स्टेशन इस काल्पनिक रेखा को नहीं दिखा सकता। यही कारण है कि कनातल का मौसम एक खास जगह बनाता है। बर्फबारी के दौरान यहां सर्दियों का रोमांच महसूस किया जा सकता है।

पलायन न करने का दर्द

‘लगभग 25 साल पहले मैं इस गांव में शादी होकर आई, तभी से यहां हूं। हमने खेती करके अपने बच्चों को पाला। हम यहां से कहीं नहीं गए, पर आपदा ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। यह सब तबाही कालबन मोटर मार्ग का मलबा नदी में गिराने से हुई। पहले कभी, मैंने और परिवार ने यहां नदी से इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा। अब तो सरकार से यही मांग है कि हमें यहां से विस्थापित करने की कृपा करे।’

राजेश पांडेय
देहरादून

उत्तराखंड इस साल रजत जयंती मना रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून जिले के सेबूवाला गांव में देवेंद्र मनवाल और उसकी पत्नी गीता के जहन से 15 सितंबर की आपदा शायद जीवन की सबसे बड़ी आपदा के रूप में जीवन भर याद रहेगी। गीता मनवाल, देहरादून जिला के सेबूवाला गांव में पति देवेंद्र मनवाल के साथ रहती हैं। तीनों बच्चे देहरादून में पढ़ाई करते हैं। देवेंद्र और गीता की आजीविका पशुपालन और कृषि पर निर्भर है। उनके भाई-भाभी परिवार के साथ भोगपुर में रहते हैं। अक्सर घर आते रहते हैं। देवेंद्र मनवाल का वर्षों पुराना 12 कमरों का मकान 15 सितंबर, 2025 की आपदा में ध्वस्त हो गया। मकान का जो हिस्सा बचा है, वो रहने लायक नहीं है। इन दिनों 55 वर्षीय देवेंद्र और गीता टीनशेड के नीचे वक्त गुजार रहे हैं, जो तीन ओर से खुला है। उनके पास दो बैल, एक भैंस को पालने की भी जिम्मेदारी है। करीब 50 वर्षीय गीता मनवाल 15 सितम्बर 2025 की रात आई आपदा की आपबीती न्यूज लाइव से साझा करती हैं। बताती हैं, हमने गांव में ही रहकर खेती को बंजर होने से बचाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि यहां से कहीं जाएंगे। जबकि यहां रहना बहुत कठिन है। हम पलायन नहीं चाहते, पर आपदा ने हमें मजबूर किया। सरकार को हमारी सुरक्षा और मदद करनी चाहिए। देवेंद्र बताते हैं, उस रात साढ़े दस बजे बारिश बहुत तेज थी। सोने से पहले मैंने घर के आसपास एक चक्कर लगाया। नदी में पानी बढ़ गया था, पर ऐसा अक्सर हो जाता था। करीब दो बजे के आसपास नदी का शोर बढ़ गया। हमने पानी बढ़ते देखा तो कुछ सामान और पशुओं को, जो घर के आंगन में ही बंधे रहते थे, को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। यह सब बहुत जल्दी में किया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें? उस समय अंधेरा छाया था। रात करीब दो-ढाई बजे थे। देखते ही देखते मकान का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया, जिसमें दो परिवारों का सामान, अनाज, बर्तन, कपड़े, जेवर, टीवी,

जल प्रलय के समय घर में देवेंद्र व पत्नी गीता थे, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने का प्रश्न था, शुक्र है, हम बच गए, मकान से करीब 30 मीटर दूर पशुओं की छानी बनी में हम दोनों पहुंच गए, पशु हमारे साथ थे, सुबह-सुबह हमने खुद को बर्बाद होता देखा।

जो भी एक घर में रखा रहता है, नदी के सैलाब में बह गया। पानी काफी ऊपर तक बढ़ गया था। नदी की आवाज बहुत डराने वाली थी, उसमें लुढ़कते हुए पत्थरों का शोर सुनाई दे रहा था। बिजली चली गई थी, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से हम किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकते थे। क्योंकि आसपास में कोई नहीं रहता।उस जल प्रलय के समय घर में हम पति-पत्नी ही थे। हम घबरा गए थे, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने का प्रश्न था। शुक्र है, हम बच गए। मकान से करीब 30 मीटर दूर पशुओं की छानी बनी है, हम दोनों उसमें पहुंच गए। पशु हमारे साथ थे। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हमने खुद को बर्बाद होता देखा, पर क्या कर सकते थे। शुक्र हैं हमारी जान बच गई। सुबह भाई का फोन आया, उनको सारी जानकारी दी। हालात यह थे कि हम तीन ओर से पानी से घिरे थे। पहाड़ की तरफ से आगे भी बढ़ेंगे तो भी नदी और बरसाती गदेरे को पार नहीं कर पाते। वैसे भी हम अपने पशुओं को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। वो हमारे लिए अमूल्य हैं। हम सात दिन तक पानी में घिरे रहे। बीच में एसडीआरएफ ने फोन पर संपर्क किया, वो हमें सुरक्षित बाहर निकालने आए, पर हमनें खुद मना कर दिया। भैंस ब्याहने को थी। सभी पशु हम पर निर्भर थे, इसलिए कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। हम कई दिन तक घर से थोड़ा दूर एक कमरे में ही रहे। सातवें दिन पानी कुछ कम हो पाया। भाई और परिवार के लोग तारों के सहारे खुद को जोखिम में डालकर हम तक पहुंचे। हमारे पास राशन और जरूरी सामान पहुंचाया। अब हम तो सुरक्षित हैं, पर हमारी लगभग 11 बीघा जमीन नदी में समा गई। मछली पालन के चार तालाब, सिंचाई के पानी की वर्षों पुरानी पाइप लाइन भू समाधि ले चुकी है। पहले जैसा मकान बनाने की अब हमारी हिम्मत नहीं है।

कहां है यह गांव, कैसा था यह गांव

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर दूर सेबूवाला गांव रायपुर ब्लॉक की सिंधवाल ग्राम पंचायत में आता है। सूर्याधार झील से आगे बेहद सुंदर और संभावनाओं से भरा यह गांव संकट में है। तीनों और हरे-भरे पहाड़ से घिरे सेबूवाला की खूबसूरती जिस जाखन नदी की वजह से बनती थी, उसी जाखन नदी ने इसके सौंदर्य को बदसूरत कर दिया। आर्गेनिक फार्मिंग, इको टूरिज्म, मछली पालन की संभावनाओं वाले गांव को फिर से संवारने की जरूरत महसूस की जा रही है। जून 2022 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जाखन नदी में मलबे के पहाड़ खड़े हो गए। नदी से खेतों तक, जिन गूलों के जरिये पानी पहुंच रहा था, वो लगभग सात से आठ फीट मलबे में दब गईं। जाखन से खेतों तक पानी पहुंचाने का लगभग आठ दशक पुराना सिस्टम तबाह हो गया था। गीता मनवाल के घर से करीब एक से डेढ़ किलोमीटर दूर जाखन नदी में गहरी झील बन गई। गीता बताती हैं, पहले कभी यह झील नहीं दखी थी। ऊपर पहाड़ पर कालबन-इठारना सड़क की कटिंग का मलबा नीचे फेंकने से यह झील बनी थी, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। आपदा पीड़ित देवेंद्र कहते हैं, सड़क बनाना अच्छी बात है, पर मलबे के डंपिंग जोन भी बनाए जाने चाहिए थे। 15-16 सितंबर 2025 की आपदा की वजह भी यही मलबा था, नहीं तो आज तक हमने ऐसी बाढ़ इस नदी में नहीं देखी। इस मलबे की वजह से नदी में कई जगह बंधे बन गए थे, जो उस तेज बारिश में आई बाढ़ से टूटे और पानी हमारे मकान के पीछे जोरदार टक्कर मारता रहा। आखिर में उसने पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। देवेंद्र का कहना है कि हम दोनों भाइयों को सरकारी मदद के तौर पर ढाई-ढाई लाख रुपये मिले हैं, जबकि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा है। हमारे पास अब रहने के लिए मकान तक नहीं हैं। वर्तमान में हम सुरक्षित बचे एक हिस्से में, जो खुला है, जिस पर कुछ महीने पहले ही टीन शेड डाला था, ही बचा है। हम वहीं रह रहे हैं, चाहें रात में कितनी भी ठंड क्यों न हो।

यह पहले वाला सेबूवाला नहीं

आपदा से पहले जब भी हम सेबूवाला गांव गए, वहां प्राकृतिक नजारे हमेशा संभावनाओं से भरे रहे। इन नजारों को हमने हर बार कैमरे में कैद किया। आपदा ने मनवाल परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके रोजगार को तहस नहस कर दिया, पर अपना गांव नहीं छोड़ने वाले देवेंद्र मनवाल और गीता अब पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। यहां सवाल उठता है, क्या सरकार पलायन से खाली हो गए गांव के अंतिम परिवार को रोक पाएगी? क्योंकि सरकार हमेशा पलायन रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने का दावा करती रही है। सितंबर, 2025 की आपदा के बाद, हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हम उसी सेबूवाला में आए हैं, जिसके खूबसूरत नजारे हमें यहां बार-बार आने के लिए प्रेरित करते थे। कंडोली से सेबूवाला जाते समय जाखन नदी को पार करने के लिए बना पुल पिछले साल ध्वस्त हो गया था। पुल ध्वस्त होने के बाद भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपदा से पीड़ित 61 साल के मेहर सिंह मनवाल बताते हैं, हमारी लगभग 11 बीघा जमीन जाखन नदी में मिल गई, जिस पर अब रेत बजरी, बड़े पत्थर कब्जा कर चुके हैं। चार तालाब खत्म हो गए। मकान भी ध्वस्त हो गया। रहने लायक एक भी कमरा नहीं बचा। हमें दोबारा से मकान बनाना होगा। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि मकान बना सकें। सरकार से मिली सहायता नुकसान से बहुत कम है। अगर सड़क निर्माण का मलबा नदी में नहीं गिराया होता, तो नदी में बाढ़ का इतना विकराल नहीं होता। हमारा मकान दादाजी से भी पहले का है।

- **रात करीब दो-ढाई बजे थे, देखते ही देखते मकान का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया, जिसमें दो परिवारों का सामान, अनाज, बर्तन, कपड़े, जेवर, टीवी, जो भी एक घर में रखा रहता है, नदी के सैलाब में बह गया, नदी की आवाज बहुत डराने वाली थी, उसमें लुढ़कते हुए पत्थरों का शोर सुनाई दे रहा था।**
- **आपदा से पीड़ित 61 साल के मेहर सिंह बताते हैं, हमारी 11 बीघा जमीन जाखन नदी में मिल गई, जहां अब रेत बजरी, बड़े पत्थर हैं, चार तालाब खत्म हो गए, मकान ध्वस्त हो गया, रहने लायक एक भी कमरा नहीं बचा, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि दोबारा मकान बना सकें।**

दादा जी का 90 साल की आयु में देहांत हुआ था। हमारे पूर्वज इस जमीन पर लगभग डेढ़ सौ साल पहले आकर बसे थे। उन्होंने मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ बनाया था, इस गांव को रहने लायक बनाया। हमने कभी अपने दादा और पिता से यहां इतनी भारी आपदा के बारे में नहीं सुना। हमारा मकान तो नदी से लगभग 30 फीट से अधिक ऊंचाई पर था। वो बताते हैं 16 सितंबर 2025 की सुबह भोगपुर से सेबूवाला आने का रास्ता कई जगह बंद था। सनगांव पुल के पास काफी पानी था। हम लोग भोगपुर नहर के सहारे चलते हुए कंडोली और खरक गांव पहुंचे। खरक गांव सेबूवाला के समानांतर ऊंचाई पर बसा गांव है। वहां से नीचे उतरकर नदी है, पर वहां तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं था। हमने वहां से देवेंद्र और गीता को सुरक्षित देखा तो ईश्वर का शुक्रिया किया। पानी कम होने पर हम रस्सियों के सहारे नदी पार करके अपने छोटे भाई देवेंद्र के पास तक पहुंचे। जरूरी सामान पहुंचाया। वैसे बिजली तीसरे दिन बहाल हो गई थी, फोन पर बात होने लगी थी। मनवाल कहते हैं कि सरकार हमें विस्थापित करे, साथ ही हमारी भूमि को नदी से बचाने के लिए पुश्तों का निर्माण कराए। यदि यही हालात रहे तो पूरा गांव पलायन होने के बाद भी सेबूवाला गांव में रह रहे देवेंद्र और गीता भी यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। ग्राम यात्री मोहित उनियाल भी सेबूवाला गांव पहुंचे और प्रभावित परिवार से मुलाकात की। उनियाल बताते हैं, वो पहले भी कई बार इस गांव में आए। यह गांव संभावनाओं से भरा हुआ बेहद सुंदर गांव था। पिछली बार हम धान की पौध लगाने के अवसर पर यहां आए थे। मनवाल दंपति ने यहां की भूमि को बहुत सहेज कर रखा था। पूरा हरभरा इलाका था यह, पर आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया।

न्यूज लाइव साभार

नेशनल

घुसपैठियों में भगदड़?

एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल की कई बस्तियों की झुग्गी खाली हो गई हैं, कुछ घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं, बंगाल की सीमा पार कर वो पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो काम एनआरसी लागू करने के बाद होता वो काम चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दिखा दिया है।

उत्तराचंल दीप डेस्क

नवंबर में पश्चिमी बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर क्या शुरू हुई पश्चिमी बंगाल में टीएमसी समर्थक बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों में भगदड़ मच गई। गिरफ्तार होने के डर से घुसपैठिये भारत छोड़कर भाग रहे हैं। कोई नाव से नदी पार कर बांग्लादेश जा रहा है तो कोई बार्डर पर लाइन लगाकर भारत छोड़ रहा है। जिसे जहां से रास्ता मिल रहा है वो बांग्लादेश लौट रहा है। मीडिया में घुसपैठियों के भारत छोड़ने की खबरें छाई हुई हैं। हालांकि इससे पहले जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो इस तरह की खबरें नहीं आई थी, जबकि बिहार में भी घुसपैठियों की संख्या कम नहीं है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण घुसपैठियों में ऐसी भगदड़ क्यों मची? पश्चिमी बंगाल-बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठियों की भीड़ बता रही है कि वो अपने देश लौटने के लिए कितनी उतावली है? जबकि इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास भारतीय आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक है, लेकिन वो अब भारत में नहीं रहना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि एसआईआर की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें उन्हें पकड़े जाने और डिटेंशन सेंटर या जेल जाने का खतरा नजर आ रहा है। ये वो वोटर हैं जो टीएमसी के लिए न सिर्फ वोट करते हैं बल्कि मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन्हीं को आगे कर टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि बड़ी संख्या में घुसपैठिये दशकों से पश्चिम बंगाल में बिना किसी डर के रह रहे थे, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे थे, मुफ्त राशन खा रहे थे, भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। लेकिन एसआईआर से वो इतना डर गए कि अब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शरण में नहीं रहना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके पकड़े जाने पर टीएमसी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं कि घुसपैठियों का जितना शोर मचाया जाता है, उतने घुसपैठिये भारत में नहीं हैं। किंतु भारत छोड़कर भागते हुए घुसपैठियों को देखकर विपक्षी नेताओं की आंखें खुल जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की कई ऐसी बस्तियां हैं जिसमें दो लाख लोग रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल की कई बस्तियों की झुग्गी खाली हो गई हैं। कुछ चालू टाइप के घुसपैठियों ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर वो पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं।

एक तरह से कहा जा सकता है कि जो काम एनआरसी लागू करने के बाद होता वो काम चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया लागू करके दिखा दिया है।

मोदी की घुसपैठियों को निकालने की गारंटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का बचाव करने वाले विपक्षी गठबंधन की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी गांरटी है कि घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरा देश इसके परिणाम देखेगा। इसके बाद बिहार के पूर्णिया जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध घुसपैठियों के कारण सीमांचल और पूर्वी क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफी चेंज को बड़ा संकट बताते हुए कहा था कि बिहार, बंगाल और असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए भी मैंने लालकिले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी, लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए कांग्रेस और विपक्ष के ईको सिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने तथा उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों के लिए वो नारे लगा रहे हैं। यात्राएं निकाल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहता है। लेकिन एनडीए सरकार की पक्की गारंटी है कि वो घुसपैठ पर ताला लगाने का काम करेगी। पीएम मोदी ने घुसपैठियों का बचाव करने वाले नेताओं को चुनौती दी थी कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए आगे आएं, घुसपैठियों को बचाने का चाहे जितना प्रयास कर लें, पर उनकी सरकार घुसपैठियों को निकालने के संकल्प पर काम करती रहेगी, यह भी मोदी की गारंटी है।

- **घुसपैठिये अपने देश क्यों जाना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ एसआईआर का डर है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? तो इसका जबाव है 'इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करने वाला यह नया कानून है, जो 1 सितंबर, 2025 से लागू हो चुका है।**
- **विपक्ष का ईको सिस्टम घुसपैठियों की वकालत कर उन्हें बचाने में लगा है और बेशर्मी से विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगा रहा है, यात्राएं निकाल रहा है, विपक्षी गठबंधन देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहता है, लेकिन एनडीए सरकार की पक्की गारंटी है कि वो घुसपैठ पर ताला लगाने का काम करेगी।**

एसआईआर और घुसपैठियों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को फटकार लगा दी, सीजेआई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? दरअसल वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कह दिया कि चुनाव आयोग तानाशाह बन गया है।

जनता का विश्वास भाजपा की ताकत

प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मानना है कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। उनका तर्क था कि गुजरात और राजस्थान की सीमा से घुसपैठ क्यों नहीं होती? अमित शाह ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपनी बेबाक राय रखी थी। उनका कहना था कि घुसपैठ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विपक्ष का कहना है कि घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) उसके नियंत्रण में है, लेकिन सीमा पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भौगोलिक स्थिति के कारण बाड़ नहीं लगाई जा सकती। फिर 'केंद्र अकेले घुसपैठ नहीं रोक सकता। राज्य सरकारें ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां उनमें वोट बैंक देखती हैं।' केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में घुसता है और जिला प्रशासन उसकी पहचान करने में विफल रहता है, तो घुसपैठ कैसे रोकी जा सकती है? जब कोई व्यक्ति शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर नहीं समझता, तो वह अपनी अंतरात्मा को धोखा देता है। शाह का कहना था कि घुसपैठ को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हम घुसपैठियों का पता लगाएंगे और उन्हें देश से बाहर भी करेंगे। क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जो भारत के नागरिक हैं। भाजपा ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र को 1950 के दशक से स्वीकार किया है। घुसपैठ और चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को भी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में घुसपैठिए शामिल हो गए हैं जो भारत के संविधान की भावना को दूषित करने जैसा है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर कोई फैसला करते हैं तो वो पूरा होता है। दोनों नेता खोखली बयानबाजी नहीं करते। कोई भी ऐलान करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। इसलिए मोदी और शाह जब कुछ कहते हैं तो देश विश्वास करता है। इस विश्वास पर भाजपा सरकार खरी भी उतरती रही है। यही विश्वास भाजपा की ताकत है। जो विपक्ष को समझ से परे है।

'इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' का डर

पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में भगदड़ मची है। वो भारत की जिस सीमा से आसानी से भारत में घुस आते थे, अब बड़ी संख्या में घुसपैठिये उसी रास्ते से रिवर्स कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि घुसपैठियों में खलबली मची है और वे अपने देश क्यों जाना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ एसआईआर का डर है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? तो इसका जबाव है 'इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करने वाला यह नया कानून है, जो 1 सितंबर, 2025 से लागू हो चुका है। यह अधिनियम चार पुराने कानूनों को बदलता है और अवैध प्रवासियों को पकड़ने, नकली दस्तावेजों के खिलाफ सख्त दंड (5 साल तक जेल और 5 लाख तक जुर्माना) और विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग के लिए संस्थानों और एयरलाइनों की जवाबदेही तय करने जैसे प्रावधानों के साथ देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाला है। इस नए कानून के तहत नकली या फर्जी पासपोर्ट या वीजा के साथ भारत में प्रवेश करने वाले को 2 से 7 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना वैध वीजा के भारत में आने वाले या अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिये को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद होटल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और नर्सिंग होम जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों के प्रवास की जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसा न करने पर उनका पंजीकरण रद्द हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को भारत आने से पहले सभी यात्रियों की सूची और अन्य अग्रिम जानकारी इमीग्रेशन विभाग को देनी होगी। यह कानून देश की सीमाओं और आव्रजन चौकियों पर विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निकास की निगरानी को मजबूत करने वाला है। यह कानून फॉरेंस एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमीग्रेशन एक्ट 2000 जैसे चार पुराने कानूनों को निरस्त करके बनाया गया है। यह भी एक वजह है कि घुसपैठियों में खलबली मची है। क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ इतना कठोर कानून पहले कभी जमीन पर लागू नहीं हुआ था।

घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दे क्या?

एसआईआर का डर एक तरफ है, जो सिर्फ वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करता है, लेकिन 'इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' में फंस गए तो फिर कोई राजनीतिक छतरी साथ नहीं खड़ी होगी यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों या टीएमसी नेता ममता बनर्जी घुसपैठियों को कोई नहीं बचा पाएगा। यही घुसपैठियों में दहशत का सबसे बड़ा कारण है। 'इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' कानून लागू होते ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कराने वाले दलालों का नेटवर्क चौपट हो गया है। फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र बनाने वाले गैंग और घुसपैठियों को बसाने वाला गिरोह अचानक भूमिगत हो गया है। जिन्हें पश्चिम बंगाल में कभी कोई रोक टोक नहीं थी, वो आज खुद रास्ता ढूंढकर सीमा पार बांग्लादेश लौट रहे हैं। यह केवल प्रशासनिक बदलाव ही नहीं है बल्कि मानसिक बदलाव है। जिसका असर टीएमसी नेताओं पर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरा विपक्ष एक संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। ये वही विपक्ष है जो लोकतंत्र और संविधान बचाने का ढोंग करता है और लोकतंत्र व संविधान की धज्जियां उड़ाता है। विपक्ष के ईको सिस्टम के लोग घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बदला हुआ है। इसलिए एसआईआर और घुसपैठियों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को फटकार लगा दी। सीजेआई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? दरअसल वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करते हुए कह दिया कि चुनाव आयोग तानाशाह बन गया है। देश में बड़ी संख्या में लोग चुनाव आयोग को एक निरंकुश के रूप में देख रहे हैं। भूषण की इस टिप्पणी पर तुरंत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और उन्हें संयम बरतने को कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा, कृपया ऐसी व्यापक टिप्पणियां न करें, कृपया अपनी बात तक ही सीमित रहे। कोर्ट का यह रुख साफ संकेत देता है कि सुनवाई केवल कानूनी दायरे और याचिकाओं में दर्ज तथ्यों तक सीमित रहेगी, न कि संस्थाओं के सामान्य आकलन तक।

राजनीति में अब छल-कपट नहीं !

बिहार विधानसभा चुनाव में छल-कपट की सियासत को करारा जबाव मिल गया है, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने, संविदा पर काम करने वालों को स्थाई करने, जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने का छल औंधे मुंह गिर गया।

कृष्ण कुमार चौहान

राजनीति में सब कुछ जायज है, वो चाहे छल ही क्यों न हो, लेकिन छल की राजनीति अब चल नहीं पा रही, रेंग रही है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में छल-कपट की राजनीति करने वालों को करारा जबाव मिल भी गया है। यानी हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का छल नहीं चला। संविदा पर काम करने वालों को स्थाई करने, जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने का छल औंधे मुंह गिर गया। बिहार की जनता जानती है कि ये सारे वादे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जा रहे हैं। यानी उनके साथ कपट किया जा रहा है। चुनाव के बाद जब सत्ता की ताकत हाथ में होगी तो फिर वही जंगल राज देखने को मिलेगा। इसी तरह के छल-कपट की राजनीति कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी करती है। चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों से लेकर घोषणा पत्र तक में वोटर्स को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने न जाने कितने हसीन सपने दिखाए, वोटर्स को डराने की कोशिश भी की, कि भाजपा सत्ता में आई तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी, मुफ्त पानी और महिलाओं को फ्री बस सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली की जनता 10 साल में समझ गई कि वो एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार छली गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल तक को विधानसभा में बैठने लायक नहीं छोड़ा, यानी दिल्ली के 70 विधायक जिताने वाले केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 18 साल और इससे अधिक उम्र की हर महिलाओं को प्रतिमाह 1100 रुपये भत्ता दिया जाएगा, लेकिन तीन साल बीत गए किसी महिला को फूटी कोड़ी नहीं मिली। अब फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होने है तो पंजाब सरकार इस योजना पर काम कर रही है। लेकिन अब इस योजना में हर महिला की जगह पात्रता का पैमाना तय किया जा रहा है। ताकि हर महिला को 1100 रुपये न देने पड़े।

हसीन सपनों को बोझ जनता पर

कांग्रेस ने तो 55-56 साल तक एक दो राज्यों को नहीं बल्कि पूरे देश को छला है। इसलिए हासिये पर पहुंच गई है। फिर भी कांग्रेस ने छल कपट की राजनीति नहीं छोड़ी। वह अब भी चुनाव में झूठ का सहारा लेती है। कांग्रेस ने तीन राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने बूते सरकार बनाई है साथ ही झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। खास तौर से कांग्रेस शासित तीन राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनका बोझ जनता पर ही थोप दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर परिवार को गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, बीपीएल परिवारों को अन्न भाग्य के तहत 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा, बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए हर महीने तीन हजार रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए डेढ़ हजार रुपये प्रति महीने की युवनिधि दी जाएगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति योजना का वादा किया था, लेकिन इन सभी वादों को पूरा करने के लिए राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ा तो उसे कम करने के लिए राज्य सरकार ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए।

तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी हर तरह का छल-कपट किया गया था, तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, 18 साल उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी जैसे तमाम वादे किए थे, लेकिन ये वादे आज भी पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।

यानी 'एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले' वाली रणनीति अपनाई। कर्नाटक सरकार ने वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी लेकिन बिजली की दरें महंगी कर दीं। स्नातक और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को कठिन बना दिया। महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा दी तो बसों के किराये में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी। बाकी वादे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर रोड टैक्स में वृद्धि के साथ ही डीजल, पेट्रोल, बिजली, पानी और दूध की कीमतें बढ़ा दी, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा है। कर्नाटक के लोगों को हसीन सपने अब काट रहे हैं।

हिमाचल में 5 लाख नौकरी नहीं मिली

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस मोर्चे पर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। कर्नाटक की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन हर यूनिट बिजली के दाम में 22 पैसे की वृद्धि कर दी, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था, सरकार गठन के बाद इस योजना पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी आया, लेकिन योजना आज तक लागू नहीं हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी हर तरह का छल-कपट किया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, 18 साल उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी जैसे तमाम वादे किए थे, लेकिन ये वादे आज भी पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से किए गए वादे, किसानों, किरायेदार किसानों और अन्य लोगों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सहायता देने का वादा पूरा नहीं हुआ। तेलंगाना में आधे से ज्यादा नियमित बसें नाममात्र के लिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू करती हैं। झारखंड में कांग्रेस व जेएमएम गठबंधन की सरकार है। झारखंड में फिर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। पांच साल पहले जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने जनता से कई वादे किए थे, इनमें युवाओं को लाखों नौकरियां देना और उन्हें पांच से सात हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी शामिल था, लेकिन बेरोजगार युवा इसका अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। इसी तरह महिलाओं को कर्ज देने के लिए महिला बैंक बनाने और किसानों के लिए किसान बैंक बनाने का वादा किया था, किंतु छल-कपट की राजनीति करने वाले अपने ही वादे भूल गए। अब मतदाता परखने लगा है कि नेता जो वादे करते हैं वो जमीन पर किस हद तक उतरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए जाएं वो सत्ता में आने के बाद भुला दिया जाए या उन्हें पूरा करने के लिए जनता पर दूसरे तरीके से बोझ लाद दिया जाए? जनता अब जागरूक हो रही है बिहार इसका उदहारण है।

खाते में खटाखट...खटाखट रुपये डालने का वादा

यह वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 25 गारंटी दी थी। राजस्थान में घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में सरकार द्वारा हर महीने खटाखट...खटाखट 8500 रुपये डाले जाएंगे। यह रुपये तब तक डाले जाएंगे जब तक यह लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाते। कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद करेगी, उनके खाते में पैसा डालेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि एक ही झटके में हिंदुस्तान से हम गरीबी मिटा देंगे। चुनावों से पहले कांग्रेस ने कई परिवारों को गारंटी कार्ड भी बांट दिए थे। जिनमें प्रत्येक गरीब परिवार की महिला मुखिया को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये देने का वादा किया गया था। लोकसभा चुनाव में इस झूठे वादे पर महिलाओं ने यकीन किया और कांग्रेस को बढ़त मिल गई। चुनाव परिणाम आने पर महिलाओं ने गारंटी कार्ड के साथ कांग्रेस के दफ्तरों पर लाइन लगा दी और एक लाख रुपये खाते में खटाखट...खटाखट डालने की मांग की तो फिर महिलाओं के साथ छल किया गया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने गारंटी कार्ड जमा किया और रसीदें तक दे दी। बाद में पता चला कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए इस तरह का झूठा वादा किया था। इसी तरह राहुल गांधी ने युवाओं से केंद्र में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद भरने, ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप कानून लागू बनाने और ठेका प्रथा को खत्म कर सरकार में पेंशन वाली पक्की नौकरी देने जैसे वादे किए थे। किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करने और कर्ज माफी का भी वादा किया था। कांग्रेस को पता रहता है कि वो चुनाव में तो जीतने वाली नहीं है, इसलिए भी सामने वाले प्रतिद्वंदी को परेशान करने के लिए वादों की लंबी झड़ी लगा देती है।

- **'एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले' वाली कांग्रेस की रणनीति है, कर्नाटक सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी लेकिन बिजली की दरें महंगी कर दीं, स्नातक और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को कठिन बना दिया, महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा दी तो बसों के किराये में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी।**
- **हिमाचल में कांग्रेस ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया लेकिन हर यूनिट के दाम में 22 पैसे की वृद्धि कर दी, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया, लेकिन योजना आज तक लागू नहीं हुई।**

मोदी की गारंटी पर विश्वास

इसके विपरीत 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। सबसे पहले जनधन योजना के तरह गरीबों के बैंक खाते खुलवाए, शौचालयों (इज्जतघर) का निर्माण कराया। उज्जवला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए। जीवन बीमा कवरेज। दुर्घटना बीमा कवरेज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना, कौशल विकास और रोजगार योजना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी, गर्भवती महिलाओं और माताओं को वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी करीब 200 योजनाएं शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई, आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई, रोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की गई। नागरिकों के लिए सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। मुस्लिम महिलाओं को स्वाभिमान से जीने के लिए तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथा को खत्म करने का भी वादा भाजपा सरकार ने पूरा किया। एक तरह से भाजपा ने वादे कम और काम ज्यादा किए। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने की कोशिश की है। जब दुनिया में कोरोना महामारी फैली थी तब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी 2022 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करा दी। हालांकि इससे पहले विपक्षी नेता भाजपा पर तंज कसते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा के एजेंडे में समान नागरिक संहिता लागू करना भी रहा है। जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 25ए को समाप्त कर दिया। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम एनडीए सरकार ने ही किया। नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम, मेडिकल एजुकेशन और फाइनेंसिंग के साथ सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कराया। ग्रामीण भारत के जीवन में सुधार के लिए लड़कियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। विदेशों में रखे गए काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया अभी तक जारी है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा करने के लिए तीन किसान कानून बनाएं, लेकिन विपक्षी दलों और वामपंथियों की वजह से सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। स्वरोजगार के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने की योजना केंद्र की पीएम मोदी सरकार ही लेकर आई। मोदी सरकार की गारंटी ने विपक्ष की छल-कपट की राजनीति को हासिये पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए मोदी की गारंटी पर जनता आंख मूंद कर विश्वास करती है। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।

पहाड़ का छोटा स्वर्ग रायथल

गोट विलेज एक ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल है, उच्च श्रेणी का आवास है जहां मिट्टी व लकड़ी के कॉटेज, मौसमी टेंट और किफायती विला हैं जिनमें रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी सुविधाएं हैं। गोट विलेज में मेहमानों को खेती सीखने, बकरियों का दूध निकालने, बुनाई सीखने या पहाड़ियों पर दिन बिताने जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाता है।

अफजल फौजी
नैनीताल

उत्तराखंड के पहाड़ों पर शांतिपूर्ण प्रवास और प्रकृति के शानदार दृश्य देखना चाहते हैं तो रायथल गांव एकदम परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियां बिताने की योजना बना सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो ज्यादा रंगीन, जीवंत और अनोखी है। हिमालय से प्यार करने वालों के लिए देवभूमि के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर रायथल गांव सैलानियों को आकर्षित करता है। हालांकि उत्तरकाशी का यह रायथल गांव पर्यटन मानचित्र पर नहीं है, लेकिन यह अपने संपन्न स्थानीय समुदाय के साथ आगंतुकों को आश्चर्यचकित करता है। स्थानीय लोग कई सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे खेती, पारंपरिक होमस्टे, शहद उत्पादन, सौर ऊर्जा का उपयोग, बकरी पालन जैसी योजना पर काम करते हैं। यह गांव महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के कारण आत्मनिर्भर भी माना जाता है। कुछ युवा गांव के गाइड और पोर्टर के रूप में काम करते हैं। गांव के घर पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला की तर्ज पर बने हैं। स्थानीय लोग सोमेश्वर मंदिर में पूजा करते हैं जहां मुख्य देवता शिव और शनि हैं। सोमेश्वर मंदिर श्रीकांत पर्वत शिखर के ठीक सामने है। जो विशाल हिमालय का मनमोहक दृश्य दिखाता है। यह गांव भटवारी, बंद्रानी, क्यार्क और नटिन जैसे आस-पास के गांवों के निवासियों के साथ मिलकर फुल्यार मेले का आयोजन करता है। रायथल गांव में ट्रैकिंग और साइकिलिंग करना सबसे अच्छी गतिविधियों में से एक है। पर्यटक गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) के पर्यटक विश्राम गृह से साइकिल किराए पर ले सकते हैं और राजसी पहाड़ियों की सैर कर सकते हैं।

गोट विलेज ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल

रायथल में आपके बजट के अनुसार कई आरामदायक ठहरने के विकल्प उपलब्ध हैं। मुख्य गांव के पास ही गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित एक विश्राम गृह है जहां पर्यटकों के लिए अटैच बाथरूम वाले गैर-पारंपरिक और साधारण कमरे मिल जाते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यटक स्थानीय लोगों द्वारा संचालित होमस्टे में ठहरना भी चुन सकते हैं। ये होमस्टे असल में पुश्तैनी घर होते हैं जिन्हें पर्यटन को बढ़ावा देकर आजीविका कमाने के लिए गेस्ट हाउस में बदल दिया गया है। गोट विलेज एक ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल है, एक उच्च श्रेणी का आवास है जहां मिट्टी व लकड़ी के कॉटेज, मौसमी टेंट और किफायती विला उपलब्ध हैं जिनमें रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोट विलेज में मेहमानों को खेती सीखने, बकरियों का दूध निकालने, बुनाई सीखने या पहाड़ियों पर दिन बिताने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी होमस्टे में पर्यटकों को भोजन परोसा जाता है। स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन जैसे लिंगड़ा, कंडाली साग, मंडुआ की रोटी और मिठाई के लिए झंगोरी की खीर होती है। इन्हें तैयार करने के लिए स्थानीय खेत से सब्जियां और फल खरीदे जाते हैं। स्थानीय लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन पकाते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मेजबानों को अपनी भोजन पसंद के बारे में पहले ही बता देना चाहिए। गोट गांव से निकलकर रायथल गांव की संकरी गलियों में आराम से टहलते हुए उसके अनोखे आकर्षण का अनुभव भी कर सकते हैं। आप मिलनसार स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनके रहन-सहन के बारे में जान सकते हैं और स्थानीय संस्कृति में गोते लगा सकते हैं।

दयारा बुग्याल ट्रेक का बेस कैंप

सुरम्य रायथल गांव समुद्रतल से लगभग 7,700 फीट की ऊंचाई पर है। हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा है। इस गांव से भागीरथी, गंगोत्री और अन्य चोटियों के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। रायथल गांव मुख्य रूप से दयारा बुग्याल ट्रेक के आधार शिविर के रूप में जाना जाता है। जो घने जंगलों से घिरा एक विशाल, ऊंचा घास का मैदान है। दयारा बुग्याल का ट्रेक मध्यम माना जाता है। जो शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के ट्रैकर्स के लिए उपयुक्त है। यह मार्ग सुंदर ओक के जंगलों और जंगली फूलों से भरे खुले मैदानों से होकर गुजरता है और हिमालय के मनोरम दृश्यों का दीदार कराता है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी का रायथल गांव प्रकृति प्रेमियों, साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों और हिमालय की गोद में शांति चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को निहारने के इच्छुक पर्यटकों के लिए कई तरह की गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। वैसे तो उत्तरकाशी जिला अनगिनत ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। रायथल कई ट्रैकिंग रूट्स के लिए शुरुआती केंद्र है। रायथल का सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट दयारा बुग्याल ट्रेक है, जो सैलानियों को हिमालय की चोटियों के मनमोहक दृश्यों के साथ हरे-भरे घास के मैदानों से होकर ले जाता है। यादगार आउटडोर अनुभव के लिए रायथल के प्राचीन व प्राकृतिक परिवेश में कैम्प लगाया जा सकता है। पहाड़ों की शांति से घिरे, तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताई जा सकती है। हिमालय के मनमोहक दृश्यों, हरी-भरी घाटियों और पारंपरिक ग्रामीण जीवन को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। रायथल फोटोग्राफरों को अपने कौशल को निखारने और शानदार तस्वीरें खींचने के भरपूर अवसर देता है। उत्तराखंड विविध प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर भी है और रायथल गांव इसका अपवाद नहीं है। पक्षी-प्रेमी गांव के आसपास के हरे-भरे जंगलों और पहाड़ी ढलानों के बीच विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को देख सकते हैं। मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा करने के लिए रायथल के शांत प्राकृतिक वातावरण में योग और ध्यान सत्रों में शामिल हो सकते हैं। गांव का शांत वातावरण आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए एकदम परफेक्ट है। रायथल में स्थानीय शहद, हाथ से बुने हुए सामान और शिल्प वस्तुएं सबसे अच्छी चीजें हैं जिन्हें सैलानी रायथल से स्मृति चिह्न के रूप में खरीद कर घर ले जा सकते हैं इस संतुष्टि के साथ कि आपका पैसा स्थानीय निवासियों की मेहनत पर खर्च हुआ है।

उत्तरकाशी का रायथल गांव प्रकृति प्रेमियों, साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों और हिमालय की गोद में शांति चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को निहारने के इच्छुक पर्यटकों को कई तरह की गतिविधियों के लिए ठीक है।

500 साल पुरानी इमारत

रायथल गांव के देहाती और अनोखे घर सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इन ऐतिहासिक घरों व इमारतों के धीरे-धीरे विलुप्त होने की आशंकाएं भी स्थानीय लोग जताते हैं। हालांकि कई ऐतिहासिक घरों को होमस्टे में बदलकर संरक्षित करने की कोशिश की गई है। रायथल आने वाले पर्यटकों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर 500 साल पुराना रायथल होमस्टे है। शहर के शोरगुल से दूर पर्यटक इस होमस्टे में अच्छा समय बिताने और इसके भूकंपरोधी इतिहास के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। रायथल होमस्टे के संचालक पृथ्वीराज सिंह राणा हैं। उनका कहना है कि यह इमारत तीन भूकंपों का सामना कर चुकी है। यह होमस्टे पृथ्वीराज सिंह राणा के परिवार का पैतृक घर भी है। मिट्टी के कमरों और अद्भुत डिजाइन वाली खिड़कियों के साथ यह होमस्टे सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। पृथ्वीराज सिंह राणा अपने पिता विजय सिंह राणा के साथ होमस्टे का संचालन करते हैं। उनका बचपन इस तीन मंजिला घर में बीता है। अब वो जवान है, लेकिन अपने बचपन के किस्से मेहमानों के साथ साझा करते रहते हैं। राणा पर्यटकों को बताते हैं कि 2017 में गैर सरकारी संगठन बालाजी सेवा संस्थान ने उत्तराखंड सरकार के सहयोग से रायथल की पर्यटन क्षमता को पहचाना और हमारी विरासत संपत्ति को क्षेत्र के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया। करीब 500 साल पुराने इस घर ने राणा परिवार की पीढ़ियों को हर मौसम और विपत्ति में सुरक्षित रखा है। पृथ्वीराज राणा कहते हैं कि मुझे तो गिनती भी नहीं पता है कि इस इमारत ने कितने भूकंप झेले होंगे। हालांकि 1991 के विनाशकारी भूकंप में हमारे गांव के लगभग सभी घर तबाह हो गए थे, सिर्फ हमारे घर के साथ गिनती के घर ही टिके रहे थे। क्योंकि इन घरों की मजबूती बानल वास्तुकला की वैज्ञानिक उत्कृष्टता के कारण है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री पर निर्भर करती है। इस इमारत के निर्माण में मिट्टी, पत्थर और देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। छत पठाल की हैं, जो गर्मियों में अंदरूनी हिस्से को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती हैं। ये सभी तत्व मिलकर घरों की नींव और संरचना को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं।

- **रायथल आने वाले पर्यटकों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर 500 साल पुराना रायथल होमस्टे है, शहर के शोरगुल से दूर पर्यटक इस होमस्टे में अच्छा समय बिताने और इसके भूकंपरोधी इतिहास के बारे में जानने के लिए भी आते हैं।**
- **रायथल गांव में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, यहां लगभग 1000 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाता है, सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव और शनि देव को समर्पित है, जो गांव के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है, लोग मानते है कि मंदिर के अंदर दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है।**

रायथल की धार्मिक संस्कृति

रायथल गांव में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। यहां लगभग 1000 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव और शनि देव को समर्पित है। जो गांव के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर एक दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है, जो शाश्वत आशीर्वाद का प्रतीक है। मां जगदंबा और कंदार देवता को समर्पित मंदिर भी हैं। रायथल में स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती है। इन देवताओं को पालकी (डोली) में सजाकर मेलों और त्योहारों के दौरान निकाला जाता है। लोक कथाएं, संगीत और लोकनृत्य इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो पीढ़ियों से चला आ रहा हैं। रायथल के त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। बटर फेस्टिवल एक अनूठा त्योहार है जो भादों संक्रांति (अगस्त के मध्य) के आसपास मनाया जाता है। चरवाहों और मवेशियों के गर्मियों में बुग्याल (ऊंचे घास के मैदान) से लौटने का स्वागत करने के लिए, ग्रामीण एक-दूसरे पर मक्खन, छाछ और दही लगाते हैं, जो होली जैसा प्रतीत होता है। फूल्यार मेले में ग्रामीण स्थानीय देवताओं की पूजा करने और पवित्र ब्रह्मकमल फूल के खिलने का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सेलकू मेला मकर संक्रांति के दिन लगाया जाता है। यह मेला वसंत के नए मौसम के स्वागत का प्रतीक है और इसमें भक्त पारंपरिक लोकनृत्य करते हुए आपस में खुशियां बांटते हैं। यहां के परिवार पांडव नृत्य, रासो और तांदी जैसे पारंपरिक लोकनृत्य को अपनी परंपरा मानते हैं, जिनमें महाभारत की कहानियों का गुणगान अभिनय के माध्यम से किया जाता है। कुल मिलाकर रायथल की धार्मिक संस्कृति प्रकृति, स्थानीय मान्यताओं और सामुदायिक जीवन का एक सुंदर मिश्रण है, जिसे प्राचीन मंदिरों और जीवंत त्योहारों के माध्यम से संरक्षित किया गया है।

पुतिन से न मिल पाने की बेचैनी

एलओपी राहुल गांधी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, उप राष्ट्रपति और देश के सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते, किंतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात न होने पर खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का पारा क्यों हाई हो जाता है?

उदय भान सिंह
लेखक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, उप राष्ट्रपति और देश के सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते। संसद के अंदर हंगामा और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की राजनीति करते हैं, विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र और संविधान को कमजोर बताकर अपने ही देश को अपमानित करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि नेता प्रतिपक्ष के पद की क्या गरिमा होती है? क्या जिम्मेदारी होती है और क्या भूमिका होती है? वो शायद यही जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ संसदीय कार्य में बाधा डालना, राष्ट्रीय पर्वों में शरीक न होना और हंगामा करना है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है? पिछले एक साल में कई विदेशी मेहमान भारत आए और चले गए, लेकिन कभी कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये सवाल नहीं उठाया कि विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष की भेंट क्यों नहीं कराई गई? अभी हाल ही में अफगानिस्तान के मंत्री डेलिगेट्स के साथ भारत आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर वो सिर्फ अफगानिस्तान के मंत्री थे राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, शायद इसलिए मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा होगा। 12 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आए तो पहले एलओपी राहुल गांधी का और फिर कांग्रेसी चाटुकारों का ब्लड प्रेशर इसलिए हाई हो गया क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एलओपी राहुल गांधी की मुलाकात कराने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। लिहाजा राहुल गांधी ने सीधे-सीधे आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार खुद को असुरक्षित महसूस करती है। राहुल का यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही आया था। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से कहा कि नेता प्रतिपक्ष से मिलने वाले विदेशी नेताओं की लंबे समय से चली आ रही परंपरा का नरेंद्र मोदी सरकार या विदेश मंत्रालय सम्मान नहीं कर रहा है।

- **राहुल गांधी खुद को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाएं हैं, उनके बारे में आम राय है कि उन्हें वैश्विक राजनीति का ज्ञान भी नहीं है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सांसद सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि गांधी परिवार में जन्मे हैं और नकारात्मक राजनीति के कारण ही सुर्खियों में रहते हैं।**
- **राहुल गांधी की बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है, जबकि प्रोटोकॉल है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष विपक्ष के नेता से मिलते रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सरकार को किस तरह का डर है? लोकतंत्र में सब को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए।**

प्रियंका ने प्रोटोकॉल याद दिलाया

राहुल गांधी ने कहा कि आम तौर पर परंपरा यह है कि जो नेता विदेश से आते हैं, वे विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं। ऐसा वाजपेयी जी (अटल बिहारी वाजपेयी) के समय में होता था, मनमोहन सिंह के समय में होता था, लेकिन आजकल जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और मैं विदेश जाता हूं तो सरकार विदेशी राजनयिकों को विपक्ष के नेता से नहीं मिलने का सुझाव देती है। मीडिया हाउस टेलीग्राफ के मुताबिक राहुल गांधी ने पुतिन का सीधे तौर पर नाम लिए बिना कहा, कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल सरकार भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेता विदेशी नेताओं से मिलें। यह एक परंपरा है। यह एक नियम है, लेकिन मोदी जी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, भारत का विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करता है। राहुल गांधी की बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है। यह प्रोटोकॉल है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष विपक्ष के नेता से मिलते रहे हैं, लेकिन इस सरकार की नीति विपक्षियां की आवाज दबाने की है। मुझे नहीं पता कि सरकार को किस तरह का डर और असुरक्षा है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। यह सरकार असुरक्षित है और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है।

राहुल गांधी गंभीर नेता हैं क्या?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने स्टेट डिनर का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तो निमंत्रण दिया गया, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला। इससे कांग्रेस का पारा हाई हो गया। कांग्रेस को लगा कि शशि थरूर को स्टेट डिनर में आमंत्रित कर, राहुल गांधी और खड़गे का अपमान किया गया है। इसलिए कांग्रेसियों ने चिल्लाना शुरू किया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है। हालांकि ये वही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे है जिन्हें अयोध्या में श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात इसलिए भी नहीं कराई गई क्योंकि राहुल गांधी कब क्या बोल दें, ये खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता होता, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ऐसा कुछ बोल सकते थे जिससे भारत और रूस के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। क्योंकि राहुल गांधी खुद को कभी एक गंभीर राजनेता के रूप में अभी तक तो स्थापित नहीं कर पाएं हैं। उनके बारे में आम राय ये है कि राहुल गांधी को वैश्विक राजनीति का तनिक भी ज्ञान ही नहीं है। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सांसद सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि गांधी परिवार में जन्मे हैं। वो अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण ही सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस नेता की सोच ही नकारात्मक हो उसका विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलना क्या देश हित में हो सकता है?

कोई आधिकारिक नियम नहीं है

विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे पर विपक्ष के नेता से मिलना कोई तय और आधिकारिक 'नियम' नहीं है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक 'परंपरा' और शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता रहा है। भारत सरकार या विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य नियम नहीं है कि हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या डेलिगेट्स को विपक्ष के नेता से मिलना ही है। भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति को देखते हुए यह एक स्थापित परंपरा रही है। विपक्ष के नेता भी संसद और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं की उनसे मुलाकात, देश की राजनीति और विभिन्न दृष्टिकोणों की एक व्यापक तस्वीर दिखाती है। किंतु यह मुलाकात मुख्य रूप से आने वाले विदेशी नेता या राष्ट्राध्यक्ष के कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है कि उनके पास समय है या नहीं। शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं हैं बल्कि वो विदेशी मामलों की संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं। इसलिए उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित राष्ट्रपति के स्टेट डिनर में आमंत्रित किया गया था।

न्योता न मिलने पर सियासत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इस भोज में न्योता मिला था, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस 'चुनिंदा निमंत्रण' पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए भड़ास निकाली, जबकि भाजपा ने थरूर के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस की आपत्तियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर तंज किया और कहा कि 'हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते।' उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला, तब किसी अन्य नेता को बुलाए जाने का अर्थ समझना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं। खेड़ा ने कहा दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह हैरानी की बात है, लेकिन इस सरकार में इससे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने आरोप

- **भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य नियम नहीं है कि हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या डेलिगेट्स को विपक्ष के नेता से मिलना ही है, भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति को देखते हुए यह एक स्थापित परंपरा रही है, लेकिन मुलाकात विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है कि उनके पास समय है या नहीं।**
- **सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेसियों को साफ-साफ शब्दों में बताया कि शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं हैं बल्कि वो विदेशी मामलों की संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित राष्ट्रपति के स्टेट डिनर में उन्हें आमंत्रित किया गया था, ये विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए।**

लगाया कि सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर पवन खेड़ा ने कहा-आप उनसे ही पूछिए। इसके विपरीत भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना को खारिज करते हुए सांसद शशि थरूर का बचाव किया। दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस के सोचने का क्या तरीका है? सरकार अक्सर विभिन्न दलों के विशेषज्ञों को कूटनीतिक प्रयासों में शामिल करती है। मनोज तिवारी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतर-पार्टी सहयोग आम बात है। उन्होंने कहा 'दूसरी पार्टियों के सदस्यों समेत कई अनुभवी सदस्यों ने सरकार की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। शशि थरूर उनमें से एक हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस लीडरशिप को इससे क्या दिक्कत है?' यह विवाद ऐसे वक्त उभरा है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वह परंपरा तोड़ते हुए विपक्षी नेताओं को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के लिए आमंत्रित नहीं कर रही। लिहाजा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेसियों को साफ-साफ शब्दों में बताया कि शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस सांसद ही नहीं हैं बल्कि वो विदेशी मामलों की संसदीय स्थाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित राष्ट्रपति के स्टेट डिनर के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। ये विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए।

खतरा

चारधाम पर कचरे के ढेर

चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु ने गंदगी फैलाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतते, हर यात्री औसतन डेढ़ किलो कचरा अपने पीठे छोड़कर जाता है, इससे पता चलता है कि आज हम कितने लापरवाह हो गए हैं कि हम अपने भगवान के घर को भी साफ नहीं रख पा रहे।

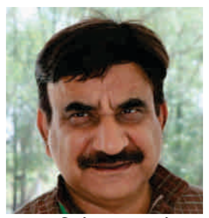

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

चारधाम अब सिर्फ तीर्थस्थान नहीं रहे हैं बल्कि धार्मिक यात्रा, अब पर्यटन में बदल गई है। यहां बहुत सी दुकानें और होटल खुल गए हैं। पेड़ काट कर सीमेंट से निर्माण तेजी से हो रहा है। 2023 में प्राचीन तीर्थस्थल जोशीमठ का धंसना इसके दुष्प्रभाव का उदहारण है। एक अध्ययन रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी, फिर भी निर्माण को बेहिसाब अनुमति दी गई और शहर में पर्यटकों के लिए होटल बनाकर विस्तार किया गया। पर्यटकों के आने से पहाड़ों पर बढ़ता कचरा भी बड़ी समस्या बन रहा है। केदारनाथ में पीक सीजन यानी अप्रैल से जुलाई के बीच प्रतिदिन 1.5 से 2 टन कचरा उत्पन्न हुआ, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई सरकारी नीति नहीं बनी है। परेशान करने वाली बात तो यह है कि यात्रियों की भीड़ केवल कुछ हिस्सों में ही बढ़ती है। परंतु भीड़ बढ़ने के बावजूद, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ग्रामीणों के जीवनस्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उत्तरकाशी में 80.10 प्रतिशत, चमोली में 60.07 प्रतिशत और रुद्रप्रयाग में 53.74 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय आज भी 5159 रुपये मात्र है। 2025 में लगभग 60 लाख तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आए जिससे राज्य को करीब 89 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ। मगर स्थानीय ग्रामीणों का विकास नहीं हुआ। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस धार्मिक यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों ने पर्वतीय क्षेत्रों पर कचरे का भारी अंबार छोड़ा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस बार 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। जिससे केदारनाथ और बदरीनाथ में प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसे नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे में भारी वृद्धि देखने को मिली।

केदारनाथ में 2400 टन कचरे का ढेर

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते का कहना है कि कचरे को नियंत्रित करने के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। हम सिंगल-यूज प्लास्टिक पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लागू करने के लिए फारेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करेंगे ताकि बैन के बाद लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस सब के बावजूद अकेले केदारनाथ में 17 लाख तीर्थ यात्रियों ने 2400 टन कचरा अपने पीछे छोड़ा है। ये कचरा पिछले साल की तुलना में 350 टन अधिक है। वहीं बदरीनाथ में कचरे की मात्रा 220 टन तक पहुंच गई। गंगोत्री से 70 टन और यमुनोत्री से करीब 44 टन कचरे को नीचे लाया गया है। ये हालत तब है जब उत्तराखंड में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर कड़े प्रतिबंध हैं। फिर भी चारधाम यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक की बोतलें, कप और पैकेजिंग सामग्री बड़ी मात्रा में मिली है और मिलने का सिलसिला अभी जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहां न तो कचरा जलाने की अनुमति है और न ही निपटारे के लिए प्लांट लगाए जा सकते हैं। लिहाजा कचरे को निस्तारित करने की प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। चारधाम में जमा हुए कचरे को नीचे तक लाना पड़ रहा है। यह काम खच्चरों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई और कठिन मार्गों के कारण मशीनों का उपयोग संभव नहीं है। प्रत्येक खच्चर केवल 10 से 12 किलो कचरा ही एक बार में ले जा सकता है। एक फेरा कराने का खर्च लगभग 1700 रुपये आ रहा है। प्रशासन का अनुमान है कि अकेले केदारनाथ धाम से कचरा नीचे लाने में लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके विपरीत पर्यावरणविद् मान रहे हैं कि अगर प्लास्टिक पर सख्ती और यात्रियों के बीच जागरूकता नहीं पैदा की गई तो चारधाम क्षेत्र में पर्यावरण संकट का गंभीर रूप ले सकता है। बदरी-केदार समिति के अध्यक्ष का कहना कि हमारे लिए कचरा बहुत बड़ी चिंता का विषय है। समिति भी सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हिमालय में बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। उनका दावा है कि केदारनाथ और बदरीनाथ मंदिर परिसरों में कूड़ा मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

आर्थिक लाभ की कीमत हिमालय चुका रहा

श्रद्धालुओं की भारी संख्या चारधाम यात्रा पर आती है तो सत्ताधीश तीर्थाटन से होने वाली आमदनी को देखकर गदगद होते हैं। सरकार आर्थिक लाभ के कारण पर्यटकों की बढ़ती आमद को बेहद वांछनीय मानती है। लेकिन सरकार के आर्थिक लाभ की भारी कीमत हिमालय और स्थानीय निवासियों को चुकानी पड़ती है। क्योंकि जब श्रद्धालुओं की भीड़ अपने पीछे कचरा छोड़कर जाती है तो कचरे के निस्तारण में सत्ताधीशों के पसीने छूट जाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण अकेले केदारनाथ धाम में 2300 टन कचरे का पहाड़ जमा हो चुका है। इसमें लगभग 100 टन प्लास्टिक कचरा और 2200 टन अन्य कचरा शामिल है। इससे चारधाम यात्रा के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जिसका खामियाजा हिमालय को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा में शामिल केदारनाथ धाम में स्थानीय निवासियों के लिए कचरा बड़ी समस्या बन गया है। आलम ये है कि मंदिर के आसपास लैंडफिल साइटों पर कई टन अपशिष्ट कचरा डम्प किया गया है, जिससे हिमालय के पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर पर्यावरणविदों ने भी गहरी चिंता जाहिर की है। यूपी के नोएडा निवासी एक पर्यावरणविद् ने आरटीआई के तहत चौंकाने वाली जानकारी निकाली है। जिसमें पता चला है कि केदारनाथ में 2022 और 2024 के बीच 49.18 टन अप्रसंस्कृत कचरा मंदिर के पास दो लैंडफिल साइटों पर डाला गया था। अब आरटीआई में मांगी गई जानकारी के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र में गैर-प्रसंस्कृत कचरे में इजाफा देखा गया है। 2022 में केदारनाथ में 13.2 टन अनुपचारित कचरा निकला था। जबकि 2023 में यह कचरा बढ़कर 18.48 टन हो गया और 2024 में सूचना मांगे जाने तक 17.5 टन कचरा निकाला गया था। चिंता की बात यह है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु ने गंदगी फैलाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतते। हर यात्री औसतन डेढ़ किलो कचरा अपने पीठे छोड़कर जाता है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 150 ग्राम अधिक है। इससे पता चलता है कि आज हम कितने लापरवाह हो गए हैं कि हम अपने भगवान की जगह को साफ नहीं रख पा रहे। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि धार्मिक स्थल के आसपास कचरा फैलाना किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा है? क्यों नहीं हम अपने पवित्र धर्मस्थलों के पास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते? क्या हम अपने पवित्र धर्मस्थलों के आसपास कचरा फैला कर पाप के भागी नहीं बन रहे? क्योंकि प्रत्येक श्रद्धालु का कर्तव्य है कि वो अपने भगवान के घर को उसी तरह साफ स्वच्छ रखे, जिस तरह अपने घर के मंदिर को स्वच्छ रखते हैं।

अकेले केदारनाथ में 17 लाख तीर्थ यात्रियों ने 2400 टन कचरा अपने पीछे छोड़ा है, ये कचरा पिछले साल की तुलना में 350 टन अधिक है, वहीं बदरीनाथ में कचरे की मात्रा 220 टन तक पहुंच गई, गंगोत्री से 70 टन और यमुनोत्री से करीब 44 टन कचरे को नीचे लाया गया है, ये हालत तब है जब उत्तराखंड में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हैं।

ओवर लोड हो रहे पहाड़

उत्तराखंड में ठंड का असर तेजी से बढ़ने लगा है। यहां कई इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है। चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम के आसपास झरने और झीलें जमने लगी हैं। यहां तापमान माइनस 8 डिग्री तक चला गया है। ठंड से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ का हर क्षेत्र एक सीमा तक ही इंसानों का वजन और संख्या झेल सकता है। इसे ही वहन क्षमता कहते हैं। अध्ययन में इसे दो तरह से स्टडी किया गया है। भौतिक वहन क्षमता से पता लगाया गया कि केवल क्षेत्रफल और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अधिकतम कितने लोग एक समय में एक स्थान पर मौजूद रह सकते हैं, लेकिन यह मानक पर्यावरण या सामाजिक स्थिरता को नहीं दर्शाता है। ऐसे में वास्तविक वहन क्षमता बताती है कि बिना पर्यावरण, संसाधनों और स्थानीय समुदाय को क्षति पहुंचाए कितने पर्यटक सुरक्षित रूप से पहाड़ पर आ सकते हैं। अध्ययन में बताया गया है कि हर दिन बदरीनाथ की वास्तविक वहन क्षमता 11,833 से 15,778 और केदारनाथ की 9,833 से 13,111 पर्यटकों के बीच होनी चाहिए। जबकि यमुनोत्री के लिए ये सीमा 6,133 से 8,178 और गंगोत्री के लिए 4,620 से 6,160 पर्यटक प्रतिदिन है। इसका मतलब है कि यदि पर्यटकों की भीड़ इस सीमा के भीतर हो, तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। संसाधन और बुनियादी ढांचे पर भी भार कम पड़ेगा।इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत तो की, लेकिन उसका पर्यावरण पर नकारात्मक असर ही देखने को मिला है। चारधाम यात्रा मार्ग परियोजन का मकसद भले ही तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाना हो लेकिन इसने पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी दबाव पड़ा है। लगभग 889 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के तहत निर्माण के लिए 17.5 हेक्टेयर वनभूमि का रास्ते के लिए उपयोग किया गया है। बड़े पैमाने पर पहाड़ों की कटाई की गई। जिससे क्षेत्र की ढलानों की स्थिरता कमजोर हुई और जल निकासी तंत्र में बदलाव आ गया। इसका असर ये हुआ कि इस परियोजना के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। क्योंकि पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में सड़क निर्माण, सुरंग और पुल बनाने से ढलानों पर दबाव बढ़ता है। जिससे भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और हिमस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ता है। अभी पर्यटक केवल चारधाम के रास्ते पर ही सीमित है। वे यहीं रुकते हैं, खाना खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिससे उस रास्ते पर भीड़ बढ़ती है। जरुरी है कि पर्यटन का विकेंद्रीकरण हो। जैसे बदरीनाथ के बगल में सप्त कुंड, ब्रह्म कपाल और केदारनाथ के पास चोराबारी और वासुकि ताल को विकसित किया जाना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों जैसे पंडुकेश्वर, गोविंद घाट, जोशीमठ और औली का 'ऑल वेदर टूरिज्म के रूप में विकास किया जाना चाहिए। ताकि ग्रामीणों को पर्यटन से फायदा मिल सके और एक ही जगह पर पर्यटकों की भीड़ भी ना रहे। चार धाम के निकटवर्ती ऐसे अन्य और क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। सर्दियों में हिमालय क्षेत्र में आसमान साफ रहता और सूरज खिलाता है। यह समय भी पर्यटन के लिहाज से अच्छा माना जाता है। लिहाजा पर्यटकों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि चारधाम यात्रा सर्दियों के मौसम में भी की जा सकती है। इससे हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन के महीनों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह केवल सबसे कम यात्रा वाले महीनों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही पर्वतीय गांवों में होमस्टे की योजना, वाहन पार्किंग की व्यवस्था और स्थानीय समुदाय आधारित जिम्मेदार पर्यटन को विकसित करने जैसे सुझाव भी शोधकर्ताओं ने दिए है। सुरक्षित यात्रा के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाना चाहिए। ये सब कदम पर्यटन को सुरक्षित, सुविधाजनक और सतत बनाने में मदद करेंगे। साथ ही एप के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जाए कि वो यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें तो अच्छा है। इससे पहाड़ पर कचरा इकट्ठा नहीं होगा।

अध्ययन पता चला कि हर दिन बदरीनाथ की वास्तविक वहन क्षमता 11,833 से 15,778 और केदारनाथ की 9,833 से 13,111 पर्यटकों के बीच है, जबकि यमुनोत्री के लिए ये सीमा 6,133 से 8,178 और गंगोत्री के लिए 4,620 से 6,160 पर्यटक प्रतिदिन है, इसका मतलब है कि यदि पर्यटकों की भीड़ इस सीमा में रहती है तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

सियासत

हिंदू विरोधी है कांग्रेस ?

राहुल गांधी को लगता है कि उनके परिवार से देश के तीन प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पैदा भी प्रधानमंत्री के खानदान में हुए हैं उनके पिता राजीव गांधी भी पीएम रहे हैं, इसलिए वो मानते है कि उन्हें भी प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लिहाजा सत्ता से बाहर रहकर इंसान कैसे तड़पता है यह राहुल गांधी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

देश की सबसे पुरानी और बूढ़ी पार्टी कांग्रेस क्या वास्तव में हिंदू विरोधी छवि के कारण हासिये पर पहुंची है। ये एक वजह हो सकती है। वैसे सच ये भी है कि कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने के प्रमाण खुद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद भी देते रहते हैं। अब तो उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई का साथ दे रही हैं। भाई-बहन की जोड़ी जब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुत्व का अपमान करती है, हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं, हिंदुओं को संसद में हिंसक कहा जाता है, तो चाटुकार नेता आग में घी डालने का काम करते हैं। यानी चाटुकार राहुल और प्रियंका का फेवरेट बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही हिंदू विरोध शुरू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेसी ये नहीं समझ पा रहे कि हिंदू विरोधी होने से ही कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। राहुल गांधी की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो देश पर राज करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार माने बैठे हैं, वो जनता को अपनी प्रजा समझते हैं, जो सिर्फ राहुल गांधी का गुणगान करें, हालांकि कुछ चाटुकार उनका गुणगान करते भी हैं। राहुल गांधी को लगता है कि उनके परिवार से देश के तीन प्रधानमंत्री रहे हैं। वो पैदा भी प्रधानमंत्री के खानदान में हुए हैं उनके पिता राजीव गांधी भी पीएम रहे हैं। इसलिए उन्हें भी प्रधानमंत्री होना चाहिए इसलिए सत्ता से बाहर रहकर इंसान कैसे तड़पता है यह राहुल गांधी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी बदहाली के कारणों को समझना भी चाहती? हिंदू विरोधी छवि वाला फार्मूला भी कांग्रेस के आत्ममंथन से बाहर आया। लेकिन क्या कांग्रेस स्वस्थ मन से आत्ममंथन करने की हालत में है? क्योंकि 2014 के बाद से कांग्रेस जिस तरह से डूब रही है उससे नहीं लगता कि कांग्रेस क्या आत्ममंथन भी कर पा रही है? वैसे सच ये भी है कि मानसिक रूप से बीमार कोई पार्टी सही से आत्ममंथन कर भी नहीं सकती। फिर काफी समय से कांग्रेस ने आत्ममंथन किया ही नहीं है और न वो इसकी आदी है। इसलिए कांग्रेस राजनीति की 'सोशल इंजीनियरिंग' में पूरी तरह फेल हो रही है।

हिंदू कोड बिल

कांग्रेस के हिंदु विरोधी होने का एक प्रमाण ये भी है कि पचास के दशक में जब जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब हिंदू कोड बिल पास हुआ था, तबसे कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगता रहा है। दरअसल हिंदू कोड बिल मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों को छोड़कर सिर्फ हिंदू नागरिकों पर लागू होता है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, आदि पारित किए। आलोचकों का तर्क है कि ये कानून केवल हिंदुओं पर लागू किए गए, जबकि मुसलमानों और अन्य समुदायों को उनके व्यक्तिगत कानूनों (जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ) में बदलाव किए बिना छोड़ दिया गया, जिससे हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ। जब भारत आजाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। हिंदू पुरूषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। किंतु आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पास कर कानून बनाया गया जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाईयों से आधा हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस कानून में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया। कानून दो प्रकार के विवाहों को मान्यता देता है सांस्कारिक व सिविल, इसमें हिंदू पुरूषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी रखे गए। हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया। एक तरह से हिंदू कोड बिल के तहत सभी स्थानीय रीति-रिवाजों को समाप्त कर दिया गया। साठ के दशक में गोहत्या विरोधी आंदोलन करने वाले साधु संतों पर इंदिरा गांधी ने गोलियों चलवाई जिसमें 400 संतों की जान चली गई। ये कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने के पुख्ता प्रमाण हैं।

जब जवाहर लाल नेहरु देश के प्रधानमंत्री थे तब हिंदू कोड बिल पास हुआ था, तब से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगता रहा है, दरअसल हिंदू कोड बिल मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों को छोड़कर सिर्फ हिंदू नागरिकों पर लागू होता है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, आदि पारित किए।

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक

पंद्रहवीं लोकसभा के अंतिम सत्र में यूपीए सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पारित कराने की कोशिश की। लेकिन विपक्षी दल भाजपा व अन्य सहयोगियों की वजह से सरकार विधेयक पारित नहीं कर पाई। यदि ये सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पारित हो जाता और कानून बन जाता तो केवल हिंदुओं पर ही सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक घृणा भड़काने का मुकदमा चलाया जाता, उन्हें दोषी ठहराया जाता और सजा दी जाती। क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा कानून यह मानने से इनकार कर देता कि मुसलमान और ईसाई हिंसा और घृणा फैलाने में सक्षम हैं। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो किसी भी गुमनाम शिकायत के आधार पर किसी भी हिंदू के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा भड़काने का पुलिस मामला दर्ज कर लेती और पुलिस को इसे गैर-जमानती अपराध के रूप में दर्ज करना होता। गिरफ्तार किए जाने वाले आरोपी को यह जानने का भी अधिकार नहीं होता कि शिकायतकर्ता कौन है? आरोपी हिंदू को तब तक दोषी माना जाता जब तक वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देता। इस कानून में लालच देकर आदिवासियों का धर्मांतरण करने वाले कट्टर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कोई हिंदू शिकायत करता तो उसे जेल भेज दिया जाता। जो ईसाई मिशनरी या कट्टरपंथी मुसलमान, हिंदुओं को 'काफिर' या 'विधर्मी' कहता है अथवा हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को रौंदता है या अपमान करता उसे भारतीय संविधान हमेशा के लिए निर्दोष मान लेता। एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा कानून बना होता तो हत्यारे केवल बहुसंख्यक होते और पीड़ित सिर्फ अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, हिंदू महिला का यौन उत्पीड़न करके भी निर्दोष माना जाता। यानी सांप्रदायिक हिंसा कानून की धारा में ये प्रावधान किया गया था कि यौन उत्पीड़न सिर्फ अल्संख्यकों के साथ ही हो सकता है।

प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट

कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने का एक प्रमाण धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 है। इस अधिनियम और विभिन्न राज्य स्तरीय कानूनों ने सरकारों को हिंदू मंदिरों के प्रशासन और धन पर नियंत्रण करने का अधिकार दे रखा है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह का कोई कानून मस्जिदों या चर्च के लिए नहीं बनाया गया, जिससे यह साबित होता है कि केवल हिंदू धार्मिक संस्थाओं को ही निशाना बनाया गया। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया। इस कानून में 15 अगस्त 1947 तक भारत में मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान किया गया, जिसका अर्थ था कि मुगलों द्वारा ध्वस्थ किए गए हिंदू धर्म स्थलों को मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आलोचक इस कानून को कांग्रेस की नफरत वाली राजनीति और हिंदू विरोधी बताते हैं। क्योंकि इसने अयोध्या के अलावा अन्य विवादित स्थलों, जैसे काशी और मथुरा पर हिंदुओं के दावों को प्रभावी ढंग से रोक दिया। अनुच्छेद 25, 28 और 30 संविधान के ये वो अनुच्छेद हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण को वैध बनाते हैं (अनुच्छेद 25), और सरकारी धन से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अनुच्छेद 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और धार्मिक शिक्षा देने की आजादी देते हैं। इन कानूनों के समर्थकों का तर्क है कि हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगतिशील कदम थे,और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हिंदू विरोधी होने का आरोप मुख्य रूप से कांग्रेस की कथित अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जैसा कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा प्रचारित किया जाता है।

- **प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार द्वारा पारित किया गया, इस कानून में 15 अगस्त 1947 तक भारत में मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान किया गया, जिसका अर्थ था कि मुगलों द्वारा ध्वस्थ किए गए हिंदू धर्म स्थलों को मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।**
- **कांग्रेस की वर्तमान हालत के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे कमजोर नेतृत्व है, कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों लेकिन हाईकमान की गद्दी गांधी परिवार के ही कब्जे में है, कांग्रेस का संगठन लुप्त हो चुका है, ऊपर से हिंदू विरोधी विचारधारा कांग्रेस को इतिहास बनाने पर आमादा है।**

मुस्लिम तुष्टिकरण

जून 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि कांग्रेस को 'छद्म धर्मनिरपेक्षता' और अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव रखने वाली छवि सुधारनी होगी। उनके इस बयान से लहरें उठी थीं, पर जल्द शांत हो गईं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि कांग्रेस की आंतरिक बैठकों में यह मसला कई बार उठा है, इसलिए अब पार्टी निचले स्तर के कार्यकर्ता की राय लेना चाहती है। राहुल गांधी ने सहज भाव से पार्टी महासचिवों से कहा था कि वे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की राय लें कि पार्टी को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। 'हिंदू विरोधी' छवि पार्टी की चिंता का विषय है या विरोधियों के प्रचार का हिस्सा है? विरोधी तो कांग्रेस की छवि बिगाड़ना ही चाहेंगे, पर क्या पार्टी-कार्यकर्ता की राय भी यही है? कांग्रेस की कोशिश रही है कि वो भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी साबित कर दे, ताकि मुस्लिम तुष्टिकरण का फायदा कांग्रेस को मिले। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। नरेंद्र मोदी को पराजित करने की जिम्मेदारी जिन पर थी उनके पास 2002 दंगों के बाद बनी मोदी की छवि का कार्ड था। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ही 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जैसे ही सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' कहा, मोदी ने उसे गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया। इसके विपरीत कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से जुड़े कदम जब भी उठाए, भाजपा उन्हें 'हिंदू विरोधी' साबित करने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के हितों को समझ पाई? क्या वे उसके साथ हैं? अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए कांग्रेस ने हिंदू विरोधी राजनीति का खुला कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद के इमाम से भेंट की लेकिन चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो गया। कांग्रेस की वर्तमान हालत के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे कमजोर नेतृत्व है, कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों लेकिन हाईकमान की गद्दी गांधी परिवार के ही कब्जे में है। कांग्रेस का संगठन लुप्त हो चुका है। ऊपर से हिंदू विरोधी विचारधारा कांग्रेस को इतिहास के पन्नों में कैद करने की तरफ बढ़ा रही। हालांकि कांग्रेस खुद को सांप्रदायिकता विरोधी और धर्मनिरपेक्ष छवि वाली पार्टी तो बताती है, लेकिन इसे साबित नहीं कर पाती। यही कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है।

व्यंग्य

बुलडोजर बाबा से पंगा

जिसे भी लगता हो योगी जी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो एक बार इनके फेरे में पड़कर देख लो, भाई इलाज के पहले चरण में ही पांच वक्त का नमाजी भी सुप्रभात व शुभ संध्या कहने लगता है, अगर कोई ज़्यादा ही ढीठ हुआ तो उसका इलाज जैसे-जैसे अंतिम चरण में पहुंचता है, उसे अपनी आठवीं पीढ़ी सनातनी नजर आने लगती है।

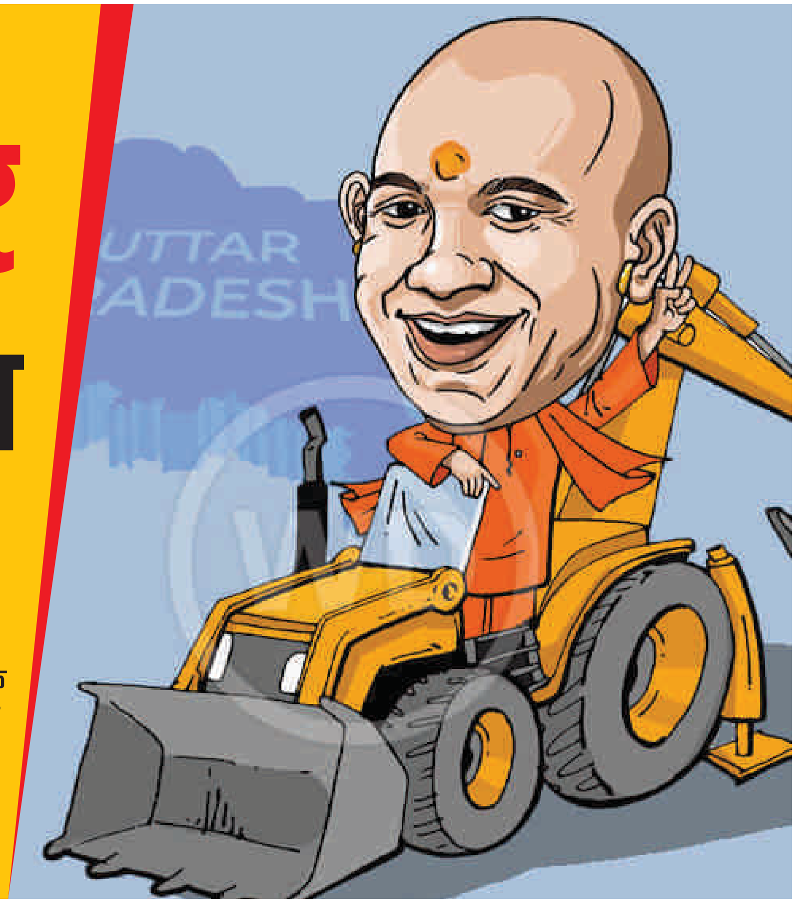

प्रदीप डीएस भट्ट
व्यंग्यकार, मेरठ

रहिमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल,
आप कह भीतर भई, जूती खाए कपाल।

आज से करीब 969 बरस पहले जब रहीम दास जी ने इस दोहे की रचना की होगी तो उन्हें थोड़े ही पता था कि 2014 में भाजपा जब केंद्र की सत्ता में आएगी और तीन बरस बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा सत्ता संभालेंगे तब इस दोहे को दस-बीस 'शूरमा' पूरे का पूरा मान सम्मान देंगे। बदले में पता नहीं अपना क्या-क्या लाल करवा लेंगे, सिर्फ अपना नहीं अपने रिश्ते-नातेदारों की भी मिट्टी पलीद करवाने से बाज नहीं आएंगे। वो क्या है न जब बुलडोजर बाबा किसी का इलाज करते हैं तो वो गर्म तवे पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों और ऐसे शूरमाओं के हमदर्दों का भी इलाज बड़ी शिद्दत और कायदे से करते हैं ताकि न रहे बांस न बजे बासुंरी। तुम्हें मेरी सच्ची वाली मुहब्बत की कसम बुलडोजर बाबा को चेलेंज करना छोड़ दो सच कह रिया हूं इसी में भलाई है महाराज। जिसे भी लगता हो योगी जी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो एक बार इनके फेरे में पड़कर देख लो, भाई इलाज के पहले चरण में ही पांच वक्त का नमाजी भी सुप्रभात और शुभ संध्या कहने लगता है। अगर कोई ज़्यादा ही ढीठ हुआ तो उसका इलाज जैसे-जैसे दूसरे, तीसरे चरण से अंतिम चरण में पहुंचता है, उसे अपनी आठवीं पीढ़ी सनातनी नजर आने लगती है और फिर वो बुलडोजर बाबा के चरणों में लोट-पोट होकर जय श्री राम राधे-राधे कहता हुआ इलाज रोकने की मिन्नतें करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तौबा करने लगता है, भूल से भी गलती नहीं करने की कसम खाने लगता है।

बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि

आपको याद होगा संभल वाले बर्क मियां, अरे महाराज नाराज काहे होते हो, 2011 में संभल को भीमनगर बनाया था मायावती ने नमाजवादी ने 2012 में फिर से संभल कर दिया। वैसे भाई साहब शास्त्रों के हिसाब से सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरि और द्वापर युग में पिंगल, वैसे कलयुग में नागभट्ट द्वितीय के लिखे ताम्र शिला लेखों में इसका नाम शम्भुपल्लिक है। पता नई किसने इसका नाम संभल कर दिया। हां...तो सीनियर वाले बर्क मियां अजी वही नमाजवादी पार्टी के बड्डे वाले नेता जी, भाई साहब...जब भी मुंह खोलते थे ऊटपटांग ही बोलते थे। शफ्फाक दाढ़ी और कपड़ों में लिपटे डेढ़ किलो के मियां बर्क बुलडोजर बाबा के प्रकोप से जैसे-तैसे बचकर पहली फुर्सत में निकल लिए। लेकिन जूनियर बर्क की एक गलती देखो क्या करा गई अभी तक कसमसा रहा है। योगी जी टैम-टैम पर मुगली घुट्टी 555 की डॉज जो देते रहते हैं। कुछ ऐसा ही दुस्साहस इलाहाबादी माफिया का हुआ...अजी क्या नाम था उसका हां...हां...हां याद आया अतीक अहमद उर्फ अतीकवा याद आया न, कोर्ट में किसी ने अतिकवा कहा तो भड़क गया था। बुलडोजर बाबा पूरे, 'प्राण जाए पर वचन न जाए' की तर्ज पर शोले के गब्बर की तरह विधानसभा में दहाड़े मिट्टी में मिला देंगे और भाई साहब कोर्ट से निकलते ही अतिकवा के साथ उसका सगे वाला भाई अशरफ का भी हैप्पी वाला बर्थडे। उसके बाद वो मूंछों पर ताव देते एक और माफिया मुख्तार अंसारी भाई साहब...क्या तूती बोलती थी, बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि पड़ी और उसका भी जेल में ही 'राम नाम सत्य है...' हो गया। जय श्रीराम।

बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि से ऐसे-ऐसे तीस मार खां तक ना बचे, तो फिर तौकीर किस खेत की मूली है, ये कौन तौकीर बरेली वाले अहमद रजा खान, बरेली आंदोलन के जनक का परपोता है, कहने को तो मदरसाछाप धर्म गुरु है पर बरेली मसलक का धार्मिक नेता और सियासी दल इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद् का संस्थापक है, सोनिया की बेटी का करीबी है।

रमपुरिया का सितारा गर्दिश में

रामपुर के चौधरी समझ रहे आजम खान जो अपने आप को आबे जम-जम खान समझने की भूल में थे, पहले कांग्रेस ने सहारा दिया और फिर नमाजवादी पार्टी ने सीधे सर पर बिठा लिया। जरा सोचिए 2012-2017 में जनाब का क्या जलवा-ए-जलाल था। एक मुख्यमंत्री अखिलेश तो दूसरा आजम खान और आधे बाकी यादव यानी कुल जमा यूपी में ढाई मुख्यमंत्रियों की बारात थी, लेकिन आजम खान का जलवा बस पूछो मति। जब आदमी पॉवर में होता है तो आएं बाएं शाएं कुछ भी बोल देता है, बस गलती से मिस्टेक इन्होंने भी कर दी और लोकसभा में अपने टर्म में बोलते-बोलते कुछ ज्यादा ही जौहर दिखा गए, जनाब रमपुरिया बोल गए राष्ट्रपति भवन से ज्यादा बेहतर तो मेरी जौहर यूनिवर्सिटी है। बस उस दिन से उनका सितारा ऐसा गर्दिश में आया है कि अभी-अभी जेल से बाहर की सांस ले रहे थे कि फिर सलाखों के पीछे बेटे के साथ चले गए। इल्जाम भी कैसे-कैसे हैं, भैंस, बकरी चोर, किताब चोरी, शराब की दुकान में डाका, जमीन चोरी मतबल कुल मिलाकर मुकदमों की सैंचुरी हो गई है। बुरे वक्त में नमाजवादी पार्टी ने भी मियां साहब की खूब फिरकी ली। पर जैसे ही जेल से बाहर निकले थे तो अपने आपको सनातनी घोषित करने में लगे थे और बात बात में भगवान राम और कृष्ण का गुणगान अलग से कर रहे थे। लेकिन एक और कहावत है किस्मत में हों ककंर, तो क्या करेंगे शंकर सो भैय्या अभी आजम ठीक से स्वांस भी नहीं ले पाए थे कोर्ट ने फर्जी पैनकार्ड मामले में बाप बेटे को सात-सात साल की सजा मुकर्रर हुई है। पचास हजार का जुर्माना अलग से कोर्ट ने ठोक दिया।

बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि

अब आप खुदई सोचो बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि से ऐसे-ऐसे तीस मार खां तक ना बचे तो फिर तौकीर किस खेत की मूली है। ऐ जी कौन तौकीर अरे भाई बरेली वाले अहमद रजा खान, बरेली आंदोलन के जनक का परपोता है। कहने को तो मदरसाछाप धर्म गुरु है पर बरेली मसलक का धार्मिक नेता और सियासी दल इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद् का संस्थापक है, सोनिया की बेटी का करीबी है। अब धर्मनीति में पिछवाड़े से राजनीति भी करनी है, सो पड़ोसी रामपुर जिले के आजम खान और संभल के बड़े वाले बर्क मियां की तरह इन्हें भी अनाप-शनाप बोलने की सुरसुरी उठी। अब सुरसुरी उठी तो उठी। मौका कोई भी हो दस्तूर कोई भी हो तौकीर मियां को तो जहर ही उगलना है, सो कांग्रेसियों की शह पाकर देश के खिलाफ जहर उगलने के इस बंदे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जितना ज्यादा जहर उगलता उतनी ही ज्यादा सरकारी गैर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता। न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। किसी ने ज्यादा चू चपड़ की तो एक आवाज पे हजारों की भीड़ सड़क पर उतार देता। जिले की क्या औकात जब तौकीर के तार लखनऊ और दिल्ली से जुड़े हों। केंद्र में बैठी कांग्रेस को तो ऐसे ही फिरकापरस्तों की जरूरत है। कोई करे भी तो क्या करे। 2010 का बरेली दंगा इस बात का जीता जागता गवाह है जी। तब यूपी की मुख्यमंत्री थीं मायावती जो अपने सख्त निजाम के लिए मशहूर थी सो दंगा कराने के इल्जाम में तौकीर को पकड़वा लिया, पर तौकीर के कसीदे पढ़ने वाले बहिन जी के चाटुकारों ने तौकीर का ऐसा भौकाल बनाया कि बहिन जी का 48 घंटे में ही उसे छोड़ना पड़ा लिहाजा तौकीर शान से बिना मूंछों के भी मूंछों पर ताव देता हुआ वापस घर पहुंच गया, पूरी शान ओ शौकत से वो भी ये कहते हुए की 'बरेली का झुमका हूं बरेली में ही सजूंगा।'

माफिया की डेटिंग-पेंटिंग का दस्तूर जारी

पर कहते हैं न 'समय-समय की बात है समय बड़ा बलवान, खड़ी गोपियां लुट गईं वही अर्जुन वही बाण' तो भैय्या 2017 में उत्तर प्रदेश में आए बुलडोजर बाबा वो भी लठ्ठ लेकर और मुनादी करा दी 'गुंडन-गुंडई छोड़ दें या उत्तर प्रदेश' वरना हम छुड़वा देंगे और महाराज उसके बाद जो गुंडन और माफिया की डेटिंग-पेंटिंग, धुलाई. रंगाई-पुताई होनी शुरू हुई वो दस्तूर, बदस्तूर जारी है। जो प्रेम से माना उसे लड्डू जो नहीं माना उसे लठ्ठ और जो खुद को खुदा समझने के फेर में था उसकी बत्ती जड़ से गुल। इधर इस चौराहे पर लड़की पर फब्ती कसी उधर अगले चौराहे पर यमदूत तैयार। कुछ जड़ बुद्धि फिर भी नहीं माने तो बुलडोजर बाबा ने पहली फुर्सत में ऑपरेशन लंगड़ा लॉन्च कर दिया। हर दूसरे दिन पैर में गोली लगे लंगड़ाते हुए तीन-चार छुटभैय्या नेता और कुछ टुच्चे से टटपुंजीए। ऐसे में बरेली वाले तौकीर की जुबान में फिर खुजली हो गई, अनाप-शनाप भौं-भौं शुरू कर दी। लोगों ने बहुत समझाया मियां बुलडोजर बाबा की दृष्टि आपके कुकर्मों पर पहले से ही है और पंगा मति लो, पर तौकीर कहां मानने वाला था। सो आई-लव-मुहम्मद पर 25 सितंबर को आएं-बाएं-शाय बोलते हुए बुलडोजर बाबा को चुनौती दे दी। प्रशासन सख्त हुआ तो इसने अगले दिन 26 सितंबर यानी जुमे के दिन बिहार, बंगाल, यूपी से हजारों की भीड़ इक्ट्ठी करके प्रशासन को चुनौती दे दी। बात बुलडोजर बाबा तक पहुंची, तौकीर का रसूख दादागिरी और बहन मायावती जैसी सख्त प्रशासक के बावजूद उसकी दबंगई की चर्चा हुई। बुलडोजर बाबा ने सख्त आदेश दिया जहरीले सांप का जहर एक ही बार में निकाल दो, साथ में बहिन मायावती की जो किरकिरी हुई थी उसका भी हिसाब किताब बराबर कर लो। अब ये बंदा मुगालते में था बुलडोजर बाबा मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे हम तो तौकीर हैं। हमने तो समजवदियो और बसपा को भी घुटनों पर ला दिया तो बुलडोजर बाबा किस खेत की मूली हैं। ये सुनकर इधर बुलडोजर बाबा धीरे से मुस्कुराए और उधर बरेली में लठ्ठ चालू और अगले तीन-चार दिन में बुलडोजर बाबा ने तौकीर समेत कइयों को समझा दिया बुलडोजर बाबा खेत की मूली नहीं बड़े वाले मठ के मठाधीश हैं। लठ कहां से घुसेगा और कहां से निकलेगा खुद बाबा जी को भी नहीं पता।

बुलडोजर बाबा पूरे, 'प्राण जाए पर वचन न जाए' की तर्ज पर विधानसभा में दहाड़े थे, मिट्टी में मिला देंगे और भाई साहब कोर्ट से निकलते ही अतिक और उसके भाई अशरफ का भी हैप्पी वाला बर्थडे, हो गया, उसके बाद वो मूंछों पर ताव देते एक और माफिया मुख्तार अंसारी भाई साहब...क्या तूती बोलती थी, बुलडोजर बाबा की वक्र दृष्टि पड़ी और उसका भी जेल में ही 'राम नाम सत्य है...' हो गया।

अब तौकीर गिड़गिड़ा रहा

तौकीर अब गिड़गिड़ा रहा है जुगाड लगा रहा है कह रहा है बुलडोजर बाबा कसम से पूरी जिंगदी किसी मंदिर में भजन कीर्तन सत्संग करके काट लूंगा बस किसी तरह इस बार बख्श दो। दंगा फसाद आगजनी तोड़फोड़ तो दूर मुंह भी नहीं खोलूंगा, बस बख्श दो, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ नाथ तो ठहरे पक्के वाले बाबा जी पहली फुर्सत में तौकीर को फतेहगढ़ जेल भेजा। दस-बीस मुकदमे दर्ज, अगली पिछली कई पीढ़ियों की जन्मकुंडली खंगाली गई फिर शुरू हुआ बरेली में स्वच्छ भारत अभियान का श्रीगणेश। तौकीर के दूर के पास के सभी रिश्तेदारों पर बुलडोजर बाबा का नजला गिर रहा है। ऐंठन बैठन, हेकड़ी वेकड़ी रंगबाजी छिनैति गिरी सब हवा। इतना बड़ा एक्शन लिया है बुलडोजर बाबा ने कि तौकीर के रिश्तेदार ही उसके जानी दुश्मन बन गए हैं। जब तौकीर के कारण कब्जा कर रहे थे तो सब अच्छा था लेकिन अब छिन गया तो आप समझ रहे हो न मैं क्या कह रिया हूं। सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ लौंडे लपाडो को तौकीर के साथ वही करने के लिए कहा गया है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जेल में हुआ है। सच्ची कह रिया हूं। ●

मध्य प्रदेश

मोहन के दो साल दमदार

सीएम के रूप में डॉ. मोहन यादव आलाकमान की कसौटी पर सौ प्रतिशत खरे ही उतरे हैं, उनका 2 साल का सफल सफर इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आगामी 3 वर्ष में प्रदेश सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में एक नई और खूबसूरत इबारत लिखेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यानी उन्होंने निर्विघ्न रूप से 730 दिन मध्य प्रदेश का शासन कर लिया है। 2 साल पहले 2023 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुआ और भाजपा को जीत मिली थी। डॉ. मोहन यादव विधायक चुनकर आए थे। अब बारी सीएम के चयन की थी। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्मिलित डॉ. मोहन यादव को यह सपने में भी इल्म नहीं होगा कि वह देश के हृदय प्रदेश के रूप में जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका नाम जब मुख्यमंत्री पद के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित किया तो इस बैठक में मौजूद वरिष्ठ विधायक समेत पुराने मंत्री और स्वयं डॉ. मोहन यादव तक अवाक रह गए थे, क्योंकि यह नाम न केवल सभी को अचंभित कर देने वाला था, बल्कि सोचने पर भी विवश कर देने वाला था। बेशक मोहन यादव मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के बीच कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, मगर पर्यटन निगम के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में वे अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। खैर सीएम बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने खुद को साबित करने के लिए 730 दिन में प्रदेश में जो काम जमीन पर कर दिखाया है, उसने मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान दी है। मध्य प्रदेश को देश में स्थापित करने का जो काम किया है उसने इस बात पर मोहर लगाई है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा उन्हें चुना जाना एक सही और सटीक निर्णय था। सीएम के रूप में वो आलाकमान की कसौटी पर सौ प्रतिशत खरे ही उतरे हैं। उनका 730 दिन का सफलता से भरा सफर इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आगामी 3 वर्ष में प्रदेश सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में एक नई और खूबसूरत इबारत लिखेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

आलोक एम इंदौरिया
लेखक व स्तंभकार

एबीवीपी का प्रोडक्ट

छात्र जीवन से बेहद सक्रिय रहे मोहन यादव मूलतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट है और संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात किया है। वो छात्र जीवन में न सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे बल्कि उज्जैन के नगर मंत्री से सियासी सफर प्रारंभ करते हुए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त एक स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने संघ में नगर सह खंड कार्यवाह से लेकर नगर कार्यवाह जैसे पदों का दायित्व भी संभाला। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने 2018 में दूसरी बार विधायक बने और उच्च शिक्षा मंत्री के पद को संभाला। 2023 में विधायक निर्वाचित होने के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। यानी संघ के एक साधारण स्वयं सेवक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साधारण कार्यकर्ता के रूप में निरंतर काम करते-करते मुख्यमंत्री बन जाना वास्तव में कुंडली में राजयोग का कमाल हो सकता है। मगर इसके साथ ही उनका मुख्यमंत्री पद के लिए चयन भाजपा का एक बेहद सामान्य और योग्य कार्यकर्ता को उसकी अच्छी राजनीतिक भूमिका का परिणाम कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री के पद पर बने रहकर प्रशासनिक कसावट, प्रदेश का विकास और अंतिम छोर तक के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करना यकीनन गंभीर और बड़ी चुनौती होती है। किंतु इन दो सालों में वे एक मजबूत और दमदार मुख्यमंत्री के रूप में न केवल स्थापित हुए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक बहुत मुकम्मल पहचान बन चुकी है जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी भरोसा करती है। 730 दिन की मोहन सरकार के कामों की फेहरिस्त पर यदि आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, उद्योग, सिंचाई, कृषि, महिला बाल विकास, पंचायत समेत ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां इन दो सालों में काम ना हुआ हो? इन 2 सालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उन पर गर्व किया जा सकता है। लेकिन डॉ. मोहन यादव इसे गर्व का विषय नहीं मानते बल्कि इस मौके पर उनका सारा ध्यान केवल और केवल इस बात पर केंद्रित है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य द्वारा प्रारंभ की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को हर हाल में मिले, साथ ही कोई भी शोषण और कोई पात्र इससे वंचित न रह सके। इसलिए उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों को निरंतर एवं विस्तार की नीति अपनाई और उस पर ठोस और सकारात्मक काम किया।

मोहन यादव मूलतः एबीवीपी का प्रोडक्ट है और संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात किया है, वो छात्र जीवन में न सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे बल्कि उज्जैन के नगर मंत्री से सियासी सफर प्रारंभ करते हुए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे।

विकास के पथ पर मध्य प्रदेश

मोहन सरकार के गठन के बाद से ही विकास ने गति पकड़ी है और लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में आए हैं। सरकार की योजना है कि एक ही दिन में ढाई लाख करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कराया जाए। क्षेत्रीय औद्योगिक परिषदों से जहां दो लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए वहीं तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश भी सुनिश्चित हुआ है। 2028 में होने वाले उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर जबरदस्त तैयारी जारी है, जिसके लिए कई करोड़ रुपये का प्रावधान करके सरकार ने योजनावद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। साइबर तहसीलों और तत्काल नामांतरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। डिजिटल पहल से संपत्ति नामांतरण स्वतः संभव हुआ है। प्रदेश में जीएसटी संग्रह में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कर्ज भार दो प्रतिशत घटा है। कृषि, डेयरी तथा सहकारिता को मजबूत करके दोगना दूध उत्पादन के लक्ष्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत दिशा मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार के साथ सिंचाई क्षमता में वृद्धि और प्रधानमंत्री जन मन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को दृढ़ता से लागू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य तीन वर्षों में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं तथा स्थाई आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को संबंधित 9 मंत्रालयों द्वारा 11 योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पिछड़े आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ये योजना शुरू की है।

नक्सलवाद घुटनों पर

सहकारी बैंकों की मजबूती कायम रखने की ठोस व्यवस्था की गई है। शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड बजट के साथ राज्य औसत से आगे निकल चुका है। 950 महिला ऊर्जा डेस्क और हर जिले में एक महिला थाना स्थापित किया गया है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 47 लाख महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। मनरेगा के तहत खेत तालाब अमृत सरोवर और सामुदायिक संरचनाओं के निर्माण के साथ वॉटरशेडों पर भी काम चल रहा है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उपज का सही मूल्य देने के प्रयास के साथ प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त किसानों को 1800 करोड़ की राहत राशि का वितरण किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए योजना पूरी तरह तैयार है और 2026 में योजना की शुरुआत का लक्ष्य तय किया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ भ्रष्ट्राचार पर सख्त कार्रवाई और भ्रष्ट अफसर को दंडित करने का ठोस काम मोहन सरकार कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए गंभीरता से काम किया गया है। खासकर प्रदेश को नक्सली विहीन करने के लिए बालाघाट क्षेत्र में जो मुहिम चलाई गई है उसने अब तक कई नक्सलियों का खात्मा किया गया है। वहीं हाल ही में दो करोड़ 36 लाख के ईनामी 10 नक्सलियों ने सिरेंडर करके नक्सली मुहिम को घुटनों पर ला दिया है। बालाघाट मंडला और डिंडोरी जिले नक्सल उन्मूलन के कारण अब लगभग शांत है। प्रदेश में बल की कमी को दूर करने के लिए 7000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की जा रही है। वहीं सिंहस्थ के मददेनजर लगभग 5000 होमगार्ड की भी भर्ती की घोषणा डॉ.मोहन यादव ने की है। सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपने डॉक्टर पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन से करके सामाजिक सद्भाव, समरसता और सादगी का सारे देश में एक ऐसा नवाचार प्रस्तुत किया है जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है।

- **मोहन सरकार के कामों की फेहरिस्त पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हेल्थ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, उद्योग, सिंचाई, कृषि, महिला बाल विकास, पंचायत समेत ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां इन दो सालों में काम न हुआ हो, मोहन सरकार के 2 सालों के कार्मो पर गर्व किया जा सकता है।**
- **एमपी को नक्सल मुक्त करने के लिए बालाघाट क्षेत्र में मुहिम चला कर कई नक्सलियों का खात्मा किया गया है, दो करोड़ 36 लाख के ईनामी 10 नक्सलियों ने सिरेंडर करके नक्सली मुहिम को घुटनों पर ला दिया है, बालाघाट मंडला और डिंडोरी जिले नक्सल उन्मूलन के कारण अब शांत है।**

सरकार व संगठन में बेहतर सामंजस्य

मोहन शासन के ये काम तो सिर्फ बानगी हैं, जबकि फेहरिस्त इससे कहीं लंबी है, क्योंकि सभी कामों का उल्लेख करना संभव नहीं है। यदि इन कामों की भारी भरकम सूची को देखा जाए तो लगेगा कि मोहन यादव के शासन के 730 दिन निश्चित रूप से उपलब्धि पूर्ण माने जा सकते हैं। उन्होंने जहां प्रशासनिक कसावट का काम किया तो वहीं विकास के पहिये को तेज गति से घुमाकर आम आदमी तक शासकीय योजना का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित किया। खास बात है कि मोहन यादव का न केवल संघ से बेहतर तालमेल है, बल्कि आलाकमान और संगठन से बेहतर सामंजस्य स्थापित करके भी शासन चला रहे हैं। मोहन यादव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि प्रदेश में उनका अपना कोई गुट ही नहीं है और वह अपने से वरिष्ठ, समकक्ष और जूनियर यानी सभी विधायक और नेताओं से समभाव रखते हुए न केवल प्रेम से मिलते हैं, संवाद करते हैं, इसलिए उनकी सभी के बीच स्वीकार्यता है। उनके बेमिसाल दो साल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बाकी आगामी 3 साल में मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में बेहद तेज गति से सफलता की एक नई इबारत लिखेगा। उम्मीद है एक सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव विकास के रथ पर प्रदेश को अरुढ़ कर इस प्रदेश को देश के सफल राज्यों मे अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल रहेंगे जहां विकास तो होगा, साथ ही आपसी भाईचारा, सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब भी फले फूलेगी।

सीएम पुत्र की शादी चर्चा में ?

डॉ मोहन यादव के बेटे की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन मात्र नहीं था, जो प्रशासनिक दृष्टि से सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र लगे, बल्कि सांस्कृतिक अर्थ में यह हमारे नैतिक और सनातन मूल्य के पुनर्जागरण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा उद्घोष है जिसकी गूंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से पूर्वोत्तर तक सुनाई देगी।

शादियों का सीजन है और सोशल मीडिया पर नए नवेले जोड़ों की तस्वीरें छाई हुई हैं। लेकिन कुछ समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे की शादी के चर्चा जोर-शोर से हो रही है। अब शादी सीएम के बेटे की है, तो सबसे पहले जहन में ख्याल आएगा कि इसे दिव्य और भव्य स्तर पर किया गया होगा इसलिए भी इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन वजह कुछ और ही निकली। जिसे जानने के बाद से लोग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सादगी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया उसकी शायद किसी को कल्पना भी नहीं होगी। दरअसल दिखावे को पीछे छोड़ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न कराई। जहां और भी सामान्य जोड़ों का विवाह हुआ। इनमें रिक्शा चालक सहित एकदम आम आदमी शामिल थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का छोटा बेटा डॉ.अभिमन्यु यादव और उनकी डॉक्टर दुल्हन इशिता, जो लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जिन्हें आशीर्वाद देने कई मशहूर हस्ती आई, तो बाबा बागेश्वर और बाबा रामदेव उज्जैन में संपन्न हुए सामूहिक विवाह में नए जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। यह सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सामाजिक समरसता ,सादगी और सद्भाव की मिसाल बन गया है। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रजातंत्र में एक तरह से प्रदेश का शासक या यू कहें कि प्रजातंत्र का राजा होता है तो शायद गलत नहीं होगा। मगर वही मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से करता है तो आम जनता के मुंह से बरबस ही वाह निकलती है। यह इस कारण भी स्वाभाविक है कि एक ओर जहां राजनेताओं, प्रशासनिक अफसरों और नवधनाढ्यों के लिए शादियां दिखावे का इवेंट हो गया है। मगर इस कालखंड में यदि कोई व्यक्ति समर्थ होने के बाद भी अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करता है तो निश्चित ही वह एक बहुत बड़ी लकीर खींचता है। लेकिन यह साहस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कर दिखाया है, जो इस कालखंड में देश के एकमात्र ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न कराकर न केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया है बल्कि इतिहास के पन्ने में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

आम इंसानों के बीच आम इंसान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने नवाचारों के साथ सादगी पूर्ण और आडंबर रहित जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद और राजनीति में कई बड़े सोपान चढ़ने के बाद भी उनका ठेठ बिंदास मालवी मानस और मालवी अंदाज व उनके मानस के साथ व्यवहारिक जीवन में जीवंत दिखाई देता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्य और कार्यकाल जनता जनार्दन के सामने ऑडिट के लिए है ही जो अपेक्षाकृत बेहतर ही माना जाता है। बेशक वे एक मुख्यमंत्री के तौर पर निश्चित खरे उतरे हो मगर एक बेटे के पिता और परिणय सूत्र बंधन में बंधने जा रहे पुत्र के अभिभावक के रूप में उन्होंने पिछले दिन उज्जैन में जो किया है वह अब देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और बड़े प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री हैं और उनके चाहने मात्र से उनके पुत्र अभिमन्यु का विवाह समारोह किसी सेवन स्टार होटल में राजसी ठाट-बाट के साथ आयोजित हो सकता था। मगर एक सही और प्रजा पालक शासक के रूप में उन्होंने अपने पुत्र का विवाह उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने का निर्णय लेकर आम जनता को यह संदेश दिया कि बेशक मैं मुख्यमंत्री जरूर हूं लेकिन मैं आप जैसा आम इंसान, जो अपनों के बीच इस खुशी को बांटकर, आम इंसानों के बीच आम इंसान ही बना रहना चाहता है। इस सम्मेलन में उनके पुत्र सहित विभिन्न समाजों के कुल 21 जोड़े परिणय सूत्र बंधन में बंधे जिन्हें आशीष देने के लिए विभिन्न राजनेताओं के साथ देश का प्रतिष्ठित संत समाज भी उपस्थित था।

- **मोहन यादव ने बेहद सादगी, सामाजिक समरसता और सद्भाव के साथ अपने छोटे बेटे डॉ अभिमन्यु यादव का विवाह संपन्न कराया है क्या इससे अन्य जनप्रतिनिधि, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी प्रेरणा लेंगे? क्या यह लोग भी मोहन यादव के पदचिह्नों का अनुसरण करेंगे? क्योंकि गंगा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है।**
- **दिखावे को पीछे छोड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु यादव की डॉ. इशिता से शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न कराई, जहां और भी सामान्य जोड़ों का विवाह हुआ, इनमें रिक्शा चालक सहित एकदम आम आदमी शामिल थे।**

सहजता, सादगी की मिसाल

इस सामूहिक विवाह समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें विभिन्न समाज, जाति और वर्ग के जोड़े बिना किसी भेदभाव ऊंच, नीच और जाति, वर्ग के एक ही मंडप के बीच परिणय सूत्र में बंध रहे थे। इन्हीं सबके बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र और पुत्र वधू भी थे। निश्चित रूप से यह कोई फिल्मी सेट पर किसी फिल्म का दृश्य शूट नहीं हो रहा था बल्कि जीवन के रंग मंच का वह दृश्य था जो जाति, वर्ग और आर्थिक असमानता से ऊपर उठकर वसुदेव कुटुंबकम और हम सब एक हैं की आत्मा को साकार प्रस्तुत कर रहा था यह सामाजिक सद्भाव और समरसता की वह जीवंत प्रस्तुति थी जो सालों बाद देखने में आई और बाबा महाकाल के साथ उज्जैन की धारा इसकी साक्षी बनी। इस समारोह में हमारे सनातन मूल्य के दर्शन भी हुए, क्योंकि मंच पर देश के विख्यात साधु संतों ने मंत्रोचार से नवदंपत्तियों को न केवल आशीष दिया बल्कि सप्तपदी की रस्म पूरे वैदिक, सनातनी, विधि विधान से संपन्न भी कराई। बेशक इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे की शादी जरूर थी मगर विवाह की पाती बेहद साधारण सरल और सादगी से परिपूर्ण थी। इसमें डॉ. मोहन यादव के बेटे का नाम जरूर था मगर उन सभी 21 जोड़ों के बीच और खास बात यह है कि मोहन यादव का नाम इस निमंत्रण पाती में बतौर मुख्यमंत्री नहीं था बल्कि अविभावक के रूप में सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव भर था। अब सहजता, सादगी और आडंबर से दूर इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? यह इस बात को भी दर्शाता है कि मोहन राज में आम आदमी और मोहन यादव के परिवार में कोई फर्क नहीं है क्योंकि सत्ता शिखर पर बैठे व्यक्ति का पुत्र और सामान्य तथा दलित का पुत्र एक ही मंडप के नीचे परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। सामाजिक समरसता शायद यही है और सामाजिक समरसता ऐसी होनी और रहनी भी चाहिए। मोहन यादव का यह प्रयास निश्चित रूप से उन तमाम लाखों परिवारों के लिए एक संदेश है जो महंगी शादी के कारण न केवल कर्ज के बोझ से दब जाते हैं बल्कि अपनी जीवन भर की बचत को भी इसमें लगा बैठते हैं। उनका यह आयोजन यह भी स्पष्ट करता है कि विवाह केवल पैसे का दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं है बल्कि एक संस्कार युक्त वह आयोजन है जिसका हमारे सनातन में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण है।

- **डॉ मोहन यादव के बेटे की शादी जरूर थी मगर विवाह की पाती बेहद साधारण थी, इसमें डॉ. मोहन यादव के बेटे का नाम जरूर था मगर उन सभी 21 जोड़ों के बीच और खास बात ये कि मोहन यादव का नाम इस निमंत्रण-पत्र में बतौर सीएम नहीं था बल्कि अविभावक के रूप में सिर्फ मोहन यादव था।**
- **मुख्यमंत्री के चाहने मात्र से उनके पुत्र का विवाह किसी 7 स्टार होटल में ठाट-बाट से हो सकता था, मगर एक प्रजा पालक शासक के रूप में उन्होंने अपने पुत्र का विवाह उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने का निर्णय लेकर आमजन को यह संदेश दिया कि बेशक वो सीएम हैं लेकिन अपनों के बीच खुशी बांटकर एक आम इंसान बना रहना चाहते हैं।**

विवाह इवेंट, नहीं आध्यात्मिक प्रक्रिया है

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आंगन की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन मात्र नहीं थी जो प्रशासनिक दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र लगे बल्कि सांस्कृतिक अर्थ और मायने में यह हमारे नैतिक और सनातन मूल्य के पुनर्जागरण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा उद्घोष है जिसकी गूंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से पूर्वोत्तर तक सुनाई देगी। क्योंकि इस आयोजन में ना तो शाही तामझाम का दिखावा था और ना ही सुपर प्रीमियम व्यवस्थाएं। बस आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से डॉ. मोहन यादव ने बेहद सादगी, सामाजिक समरसता और सद्भाव के साथ अपने छोटे बेटे डॉ अभिमन्यु यादव का विवाह संपन्न कराया है क्या इससे अन्य जनप्रतिनिधि, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी प्रेरणा लेंगे? क्या यह लोग भी मोहन यादव के पदचिह्नों का अनुसरण करेंगे? क्योंकि गंगा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। यकीन मानिए यदि यह संभव हो गया तो इस प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में महंगी और खर्चीली शादियों का मिथक धीरे-धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और हम एक बार पुनः उस सनातन की ओर लौट पड़ेंगे जिसमें विवाह संस्कार ही महत्वपूर्ण होता था। विवाह एक इवेंट ना होकर आध्यात्मिक प्रक्रिया होती थी जिसका हमारे 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था यदि यह हुआ तो डॉ. मोहन यादव का नाम इसमें मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने निश्चित ही मरुधर में उस गंगा को लाने का प्रयास किया है जिसकी गोद में सामाजिक सद्भाव, समरसता, सनातन और आपसी सौहार्द पनपेगा, वहीं इन दिनों विवाह में शामिल हो गए तथाकथित इवेंट, कुरीतियां और अनावश्यक लग्जरी खर्च तिरोहित हो जाएंगे। यहां मुझे प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की गजल की शुरुआती पंक्ति याद आती है...।

पीर पर्वत सी गहरी है पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

पहल

जादुंग गांव होगा टूरिस्ट स्पॉट

केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खाली हुए गांवों को दोबारा आबाद किया जाना है, पर्यटन विभाग का लक्ष्य आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले मूल स्वामित्व वाले वंचितों के वंशजों को वापस गांव लाना है, हालांकि लम्बे समय से नेलांग व जादूंग के ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे थे, कि उन्हें अपने पुराने गांव में रहने कि अनुमति दी जाए।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

भारत-चीन की सीमा पर प्राकृतिक रोमांच पर्यटन का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। सरहद के पहले जादुंग गांव में होमस्टे बनने शुरू हो गए हैं। जिसमें पहले चरण में 6 होमस्टे बन रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 8 होमस्टे और बनाए जाएंगे। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटकों को ये जगह खास पसंद आएगी। ये जादुंग गांव 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय खाली कराया गया था। यानी 1962 के भारत-चीन युद्ध का गवाह रह चुके ग्रामीणों को अपने पुस्तैनी आशियाने छोड़कर जाना पड़ा था। तब से नेलांग और जादुंग गांव समेत आसपास की सीमाएं वीरान पड़ी थी। हालांकि स्थानीय ग्रामीण अपने देवस्थानों की पूजा के लिए गांव में आते-जाते रहे हैं। भारत-चीन अंतराष्ट्रीय सीमा पर बसे जादुंग गांव को दोबारा बसाने के लिए पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 6 होमस्टे के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। यानी केंद्र और राज्य सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना परवान चढ़ रही है। शासन ने इसके लिए करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। जिससे 14 होमस्टे का निर्माण होना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले नेलांग और जादुंग गांव समुद्र तल से 11,400 फीट की ऊंचाई पर है। 1962 के युद्ध से पहले उत्तरकाशी के नेलांग और जादुंग गांव में रोंगपा या भोटिया जनजाति के लोग रहते थे। किंतु युद्ध के समय इन जनजाति के परिवारों को बगोरी गांव में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से बहुत से परिवार आज बगोरी में ही रह रहे हैं। युद्ध के बाद नेलांग और जादुंग गांव के घरों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपनी चौकियां बना ली थी। लेकिन सरकार की योजना है कि सरहद से सटे गांवों को फिर से बसाया जाए। इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज नाम दिया गया है। जादुंग गांव में होम स्टे बनाने के पीछे पर्यटन विभाग का मकसद पर्यटकों को जादुंग गांव में रुकने का मौका देने से है। अभी गांव में कई बंकर और घरों को आईटीबीपी इस्तेमाल कर रही है। किंतु अब पर्यटन विभाग जादुंग गांव में छह जीर्ण-शीर्ण घरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें होमस्टे में बदलेगा। इस परियोजना का एक विशिष्ट पहलू यह है कि पर्यटन विभाग पुनर्विकास की देखरेख करेगा, जबकि इन होमस्टे का संचालन ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। नवीनीकरण में स्थानीय वास्तुकला का पालन किया जाएगा और स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।

सीमांत गांव हो रहे आबाद

देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग यानी गरतांग गली को भी ठीक किया गया है। अब गंगोत्री नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थान पर रुकने और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का मौका मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों को आबाद करने की पहल केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत की जा रही है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खाली हुए गांवों को दोबारा आबाद किया जाना है। इस पहल के तहत पर्यटन विभाग का लक्ष्य आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले मूल स्वामित्व वाले वंचितों के वंशजों को वापस गांव लाना है, ताकि गांव को पुनर्जीवित किया जा सके। लम्बे समय से नेलांग व जादूंग के ग्रामीण भी सरकार से यही मांग कर रहे थे, कि उन्हें अपने पुराने गांव में रहने कि अनुमति दी जाए। अब सरकार खुद नेलांग व जादुंग गांव के लोगों को खोज कर यहां बसाने का प्रयास कर रही है। हालांकि शीतकाल में बर्फवारी की वजह से सीमांचल के इन गांवों के परिवार डुंडा ब्लाक के वीरपुर गांव में चले जाते हैं। सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना से इन परिवारों को रोजगार से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। यानी जो होमस्टे बनाए जा रहे हैं उनका संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे।

उत्तराखंड का जादुंग गांव जीवंत गांव के रूप में परिवर्तित होकर पर्यटकों को आकर्षित करेगा, साथ ही रिर्वस माइग्रेशन की दिशा में सरकारी हस्तक्षेप और पर्यटन के नए अवसर पैदा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा, इस योजना से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद जगी है।

होमस्टे संचालकों का चयन उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा एक समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें गांव के मूल निवासियों के आवेदन शामिल होंगे। होमस्टे के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। होमस्टे संचालकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, पर्यटन विभाग निरंतर कौशल और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। इसके अलावा विभाग इन होमस्टे के विपणन और प्रचार-प्रसार में भी सहयोग करेगा।

रिर्वस माइग्रेशन की उम्मीद

उत्तराखंड का जादुंग गांव जीवंत गांव के रूप में परिवर्तित होकर पर्यटकों को आकर्षित करेगा। साथ ही रिर्वस माइग्रेशन की दिशा में सरकारी हस्तक्षेप और पर्यटन के नए अवसर पैदा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद जगी है। सरकार की योजना के तहत गांव के मुख्य पैदल रास्तों को टाइल्स से बनाया गया है। साथ ही तीन स्थानों पर व्यू प्वाइंट का निर्माण किया गया है। जनकताल ट्रेक पर प्रकृति के रोमांच के अद्भुत नजारों के बीच जादुंग गांव में होमस्टे में ठहरकर पर्यटक यहां के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकेंगे। करीब 10 किलोमीटर का जनकताल ट्रेक भी पर्यटकों का रोमांच बढ़ाएगा। इसलिए उत्तरकाशी प्रशासन और गंगोत्री नेशनल पार्क जनकताल तक ट्रेकिंग की तैयारी भी कर रहा है। इनर लाइन इलाके में पड़ने वाले नेलांग घाटी के लिए अभी तक उपजिलाधिकारी भटवाड़ी कार्यालय से परमिट मिलने के बाद ही यहां एक दिवसीय यात्रा पर जादुंग गांव तक पर्यटक जा सकते हैं। लेकिन जादुंग गांव में होमस्टे बनने का बाद टूरिस्ट यहां रात्रि निवास भी कर सकेंगे। जादुंग गांव जाने के लिए पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचना होगा। उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी के बाद जादुंग गांव जाने के लिए करीब 40 किलोमीटर सड़क मार्ग से दूरी तय करनी होगी।

वाइब्रेंट विलेज योजना पर नजर

उत्तराखंड का सीमांत जादुंग गांव अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनेगा। जहां स्थानीय लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के साथ ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। निर्माणाधीन कार्यों की निगरानी जिला प्रशासन कर रहा है। ताकि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकें। 5 अक्टूबर को भारत-चीन सीमा से सटे जादुंग गांव पहुंचे उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि योजना के प्रथम चरण में पारंपरिक शैली में 6 होमस्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि

- **मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है जादुंग को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए कार्य शुरू किया गया है हमारी यही कोशिश है कि सीमांत गांव जादुंग पर्यटन के मानचित्र में प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आए इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें।**
- **उत्तराखंड का सीमांत जादुंग गांव अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनेगा, जहां स्थानीय लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के साथ ही विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, निर्माणाधीन कार्यों की निगरानी जिला प्रशासन कर रहा है, ताकि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकें।**

दूसरे चरण में 8 होम स्टे और बनाए जाएंगे। कुल 14 होमस्टे का काम पूरा होने पर जादुंग गांव में आने वाले पर्यटकों के ठहरने की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इससे एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यानी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का कहना है कि निकट भविष्य में जादुंग गांव सीमांत पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ स्थानीय संस्कृति व अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यहां जिलाधिकारी ने आईटीबीपी और सेना के अधिकारियों से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की। क्योंकि 1962 से यह गांव भारत-तिब्बत पुलिस (आईटीबीपी) की निगरानी में है।

खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन

उत्तरकाशी जिले का जादुंग गांव भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गया था अब इस गांव को पर्यटक ग्राम के रूप में पहचान मिलने वाली है। जादुंग गांव की सुंदरता को बेहतर तरीके से निखारने के लिए यहां उत्सव मैदान बनाया जाएगा इसके लिए 997.31 लाख रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा भैरों घाटी जादुंग मोटर मार्ग पर हिंडोलीगाढ़ में कारवां पार्क के विकास के लिए 999.89 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। 91.38 लाख रुपये की लागत से प्रवेश द्वार और चेक पोस्ट निर्माण का काम अप्रैल में शुरू हो गया है। भैरौघाटी जादुंग मोटर मार्ग पर गरतांग गली के सामने स्थित हवा बैंड में व्यू प्वाइंट बनाने के लिए 50 लाख रुपये, श्रीकांठा में व्यू प्वाइंट बनाने के लिए 66 लाख रुपये सरकार ने मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है जादुंग को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए कार्य शुरू किया गया है हमारी यही कोशिश है कि सीमांत गांव जादुंग पर्यटन के मानचित्र में प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आए इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद ये गांव बर्फीली पहाड़ियों और हरी-भरी वनस्पतियों से ढका है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। शायद ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा गांव है जहां खूबसूरती होने के बावजूद लोग आज भी 1962 के उस भयानक युद्ध को नहीं भूल पाए हैं। उत्तराखंड का ये जादुंग गांव तिब्बत से सीमा साझा करता है। इस कारण ये सीमावर्ती गांवों में से भी एक है। सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके बाद सुंदर झरनों और पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव पर्यटकों का मन मोहने के लिए काफी होगा। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए यह गांव बेहद खास और शांत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होगा। कुल मिलाकर पर्यटन और रोमांच के शौकीनों को जल्द उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर अद्भुत सौगात मिलने वाली है।

हिमवन्तवासी जिसे भुला दिया

भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' की गढ़वाली भाषा में 'एक ढांगा की आत्मकथा' और 'सीता बणवास' चर्चित रचनाएं हैं, यह दोनों कृतियां उनके देहान्त के बाद प्रकाशित हुई, हाल ही में उनका 'हिमवन्तवासी' प्रकाशित हुआ है 'नागखेंत कू नागदेव' (गढ़वाली कथा संग्रह) और 'चील और कुहरा' (हिंदी कहानी संग्रह) 'हिमवन्तवासी' की अप्रकाशित रचनाएं हैं।

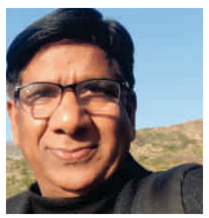

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी गढ़वाल

तुम मन्खी जूनी वळों कू जब क्वी स्यूं-बाघ मारदा, त वैकु तुम नरभक्षी-मैस्वाक बोळ्द्यां, पर जब तुम हम पशुवूं कू कचै-कचै की मारद्यां, त वो हूंद तुमारो कौथिक। हम पशुजूनी वळौ कू द्वता छ नन्दी। ब्वा रे हमरा नन्दी। अर ब्वा रे तेरी बल्द-बुद्धि। क्य करे तिन हमरा पशुवर्ग का वास्ता। अर क्य करे तेरा पशुपतिनाथ ना। हमरी खातिर? तुम छ्यां कि बैठ्यां वै ऊंच्या कैलास पर। अरे डौरं बजावा डौरं...। एक ढांगा की आत्मकथा। गढ़वाली और हिंदी के कहानीकार भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' का जन्म 17 अगस्त, 1927 को जोश्याणा, पैडुलस्यूं, पौड़ी (गढ़वाल) में हुआ था। भगवती प्रसाद जोशी उत्तर-प्रदेश, प्रादेशिक राजकीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। साथ ही ताउम्र 'हिमवन्तवासी' उपनाम से स्वतंत्र लेखन से भी जुड़े रहे। किशोरावस्था में लिखी कहानी 'कुणाल' से उनकी साहित्य सजृन की यात्रा का शुभारम्भ हुआ था। युवा अवस्था में 'सरस्वती' पत्रिका में प्रकाशित 'घना डांड्यूं का सौड़ मा' कहानी को 'मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्मान' (1945) मिला। प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं यथा-'हंस', 'सरस्वती', 'माधुरी', 'मनोहर कहानियां, 'हमारी बात', 'स्त्री-भूषण', 'बालसखा', 'सेवाग्राम', नेशनल हेराल्ड, हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि में प्रकाशित कविता, कहानी और लेखों से उन्होंने साहित्य जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई। आकाशवाणी के वे नियमित वार्ताकार थे। अपने निवास दुगड्डा, पौड़ी (गढ़वाल) में कथाकार भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' का हृदय गति रुकने से 20 अप्रैल, 1988 को देहान्त हुआ था।

गढ़वाली जन-जीवन की अभिव्यक्ति

भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' की गढ़वाली भाषा में 'एक ढांगा की आत्मकथा' (कहानी संग्रह-1988) और 'सीता बणवास' (खंड काव्य-2002) चर्चित रचनाएं हैं। यह दोनों कृतियां उनके देहान्त के बाद प्रकाशित हुई। हाल ही में उनका 'हिमवन्तवासी'(कहानी-संग्रह-2024) प्रकाशित हुआ है। 'नागखेंत कू नागदेव' (गढ़वाली कथा संग्रह) और 'चील और कुहरा' (हिंदी कहानी संग्रह) 'हिमवन्तवासी' की अप्रकाशित रचनाएं हैं। 'हिमवन्तवासी' की लिखी 'हेड मास्टर हिरदैराम' और 'एक ढांगा की आत्मकथा' गढ़वाली भाषा की अनमोल और सर्वोत्तम कहानियों में शामिल हैं। 'एक ढांगा की आत्मकथा' कहानी-संग्रह प्रतिष्ठित 'जयश्री सम्मान' से अलंकृत है। 'हिमवन्तवासी' प्रकाशन, दुगड्डा से 1988 में प्रकाशित कहानी संग्रह 'एक ढांगा की आत्मकथा' में सात कहानियां शामिल हैं। 'हेडमास्टर हिरदैराम', 'भूत कू चुफ्फा हाथ' 'कुकुड्ध्वज', 'एक ढांगा की आत्मकथा', 'तीन त्रिगट', 'शिब्बा बोडी अर गूंगा नौन्याल' तथा 'हाय रे मनिआर्डर'। पुस्तक में कालिका प्रसाद काला और पीताम्बर डेवरानी ने इन कहानियों पर अपना अभिमत जाहिर किया है। चालीस से साठ के दशक के गढ़वाली जन-जीवन की रोचक अभिव्यक्ति इन कहानियों में हुई है। 'हेडमास्टर हिरदैराम' की कथा-व्यथा आज भी उत्तराखंड के जन आचरण और सरकारी सेवा में प्रभावी तौर पर विद्यमान है। 'एक ढांगा की आत्मकथा' कहानी में 6 दशक पूर्व पहाड़ी जनजीवन में बाजारवाद की घुसपैठ से उपजी विसंगतियों को एक बूढ़ा बैल उद्घाटित करता है। किसी किसान परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के नाते वह उसी परिवार में जवान हो रहे नवयुवक को सचेत करता है। दशकों पूर्व लिखी इस कहानी में गढ़वाली जनजीवन में पनपते बाजारवाद के कारण पशुओं की दुर्दशा का प्रारंभिक चरण था। आज वह अपने चरम पर है और आम जनता तथा सरकार पहले भी इस ओर लापरवाह थी आज भी हैं।

गढ़वाली गद्य साहित्य की समृद्धता

इस कथा संग्रह की अन्य कहानियां भी गढ़वाली गद्य साहित्य की समृद्धता और संवेदनशीलता को बताती हैं। गढ़वाली मुहावरों, कहावतों और किस्से-कहानियों का दिलचस्प प्रवाह इन कहानियों में है। लोक छंद और लोक गीतों की तर्ज पर

भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' की गढ़वाली भाषा में कहानी-संग्रह एक ढांगा की आत्मकथा (वर्ष-1988) और खंड-काव्य सीता बणवास (वर्ष-2002) चर्चित रचनाएं हैं, हिमवन्तवासी जी की लिखी हेड मास्टर हिरदैराम और एक ढांगा की आत्मकथा गढ़वाली भाषा की अनमोल और सर्वोत्तम कहानियों में शामिल है।

'सीता वणवास' (गढ़वाली खंडकाव्य) भगवती प्रसाद जोशी की द्वितीय प्रकाशित रचना है। 'हिमवन्तवासी' प्रकाशन, दुगड्डा से 2002 में उनके पुत्र यदु जोशी और जागेश्वर जोशी के सम्पादन में इसका प्रकाशन हुआ था। यह संपूर्ण रचना नारी संघर्ष की कहानी पर आधारित है।

'नी छ कथा या राजों की, क्वी नी छ कहाणी राणी की,
व्यथा नारी की एक सिर्फ, ज्वा बणी छै माटी-पाणी की।

शिक्षाविद् पीताम्बर डेवरानी और बुद्धिबल्लभ थपलियाल 'श्रीकंठ' ने इस पुस्तक में 'हिमवन्तवासी' के रचना कार्य पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। 'हिमवन्तवासी' (कथा संग्रह) भगवती प्रसाद जोशी की नवीनतम कृति है। उनके सुपुत्र लेखक यदु जोशी और व्यंग्य चित्रकार जागेश्वर जोशी ने इस पुस्तक का संपादन किया है। डॉ. नागेन्द्र ध्यानी 'अरुण', प्रो. नन्दकिशोर ढौंडियाल और प्रो. राजेन्द्र जुयाल ने 'हिमवन्तवासी' की रचनाशीलता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। विनसर पब्लिशिंग कंपनी, देहरादून से फरवरी, 2025 में प्रकाशित 'हिमवन्तवासी' (कथा संग्रह) के प्रकाशन में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। 'हिमवन्तवासी' (कथा संग्रह) में 15 कहानियां यथा- 'घना डांड्यूं का सौड़ मा', 'एक नदी के दो किनारे', 'अध्यापक के अनुभव', 'अंधेरे में', 'सुजलाम सुफलाम', 'ढेला सिंह', 'तीन मोड', 'दो चुम्बन', 'भूत का चुफ्फा हाथ', 'शिब्बा बोडि' और 'गूंगे नौनिहाल', 'सैनिक', 'हरफनमौला', 'बकरी और भेड़िये, 'चील और कोहरा' तथा 'गोरखधंधा' शामिल हैं। इन शामिल कहानियों में कुछ कहानियां भगवती प्रसाद जोशी ने गढ़वाली भाषा में लिखी थी। जिनका इस नवीन कथा संग्रह में हिंदी अनुवाद संपादकों द्वारा किया गया है।

पहाड़ी गांव के शहर बनने की कहानी

ये सभी कहानियां पहाड़ी जीवन की विकटता और विडम्बनाओं से भरी हैं। ये कहानियां विगत शताब्दी के मध्यकाल के उत्तराखंडी समाज और जनजीवन के संक्रमणकाल की हैं। जब समूचे समाज के आवरण में धीरे-धीर बदलाव आ रहा था। जो दिखता कम था महसूस ज्यादा होता था। आज की तारीख में पहाड़ के कुछ दृश्य बदलें होगें पर सामान्य परिदृश्य इन कहानियों में वर्णित जैसा ही है। ये कहानियां पहाड़ी गांव के शहर बनने के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक और राजनीतिक मिजाज के बदलने की सीधी-सादी कहानियां हैं। पहाड़ से महानगरों की ओर रोजगार के लिए भटकते युवा कैसे अपने ही लोगों से ठगे जाते हैं। वो ही युवा कुछ समय बाद महानगरों की चालाकियों को अपना कर फिर नए आने वालों को इसी तरह ठगी का शिकार बनाने की विद्वेषपूर्ण परम्परा निभाते हैं। इन कहानियों में उत्तराखंड की परंपरागत राजनीति की शक्ल हू-ब-हू कुलांचे मारती दिखाई देती है। भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' संपूर्ण राजकीय सेवा में गढ़वाल के विविध इलाकों में रहे हैं और जहां भी वे रहे वहीं रमे रहे। तभी तो वे स्वयं लिखते हैं कि 'स्यूं गाड से गंगाड, ढांगू से ढंग्यार, नयार से पयार, औली से गिवाली, बाण से बंगाण अर बधाण से लेकी सलाण तलक मिन देखी अर समझी सर्यो गढ़वाल। जख भी गयूं आंकू-बांकू ही लगे। अर लग्दू किलई ना? घ्वीड़ कू ता अपणू चांठू ही लग्दना प्यारू?'

'एक ढांगा की आत्मकथा' (कहानी संग्रह)

भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' ने प्रेमचंद, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ 'रेणू,' शैलेश मटियानी कथाकारों की तरह अपने रचनाकर्म में सामाजिक विषमताओं पर सीधे-सीधे धारदार लेखनी से प्रहार किया है। वर्तमान में चर्चित गढ़वाली साहित्यकार महेशानन्द इसी परम्परा के संवाहक हैं। डॉ. नागेन्द्र ध्यानी 'अरुण' ने लिखा है कि 'उनका भाषिक शब्द सौष्ठव, वाक्य विन्यास और विमर्श कहीं भी अकृत्रिम नहीं लगता। स्वभावोक्ति, प्रकृति चित्रण, मनोभावों का यथातथ्य चित्रण, उनकी कहानियों में सर्वत्र मिलता है। ये कहानियां तब भी प्रासंगिक थी आज भी वैसी ही प्रासंगिक हैं।' निःसंदेह, भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' को जीवन समय और साधन उपलब्ध हो पाते तो हिंदी-गढ़वाली कथा साहित्य के और भी चर्चित व्यक्तित्व होते। फिर भी अल्प जीवनकाल में जितना भी उन्होंने लिखा है, वह उल्लेखनीय है। शिक्षाविद् पीताम्बर डेवरानी इसलिए चिंता जाहिर करते हैं कि 'जीवन भर यह रचनाकार स्वयं को हमें समझाता रहा, परंतु हम इसे समझने से नकारते रहे। लेकिन वह अब समझाने को नहीं रहा तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? अब भी समय है। देखना होगा कि विद्वान रचनाकार की विद्वता बेलिखी न रह जाए।'

'एक ढांगा की आत्मकथा' कहानी में 6 दशक पूर्व पहाड़ी जनजीवन में बाजारवाद की घुसपैठ से उपजी विसंगतियों को एक बूढ़ा बैल उद्घाटित करता है, किसी किसान परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के नाते वह उसी परिवार में जवान हो रहे नवयुवक को सचेत करता है, दशकों पूर्व लिखी इस कहानी में गढ़वाली जनजीवन में पनपते बाजारवाद के कारण पशुओं की दुर्दशा का प्रारंभिक चरण था।

गढ़वाली भाषा की अनमोल कहानियां

भगवती प्रसाद जोशी 'हिमवन्तवासी' की गढ़वाली भाषा में कहानी-संग्रह एक ढांगा की आत्मकथा (वर्ष-1988) और खंड-काव्य सीता बणवास (वर्ष-2002) चर्चित रचनाएं हैं। हिमवन्तवासी जी की लिखी हेड मास्टर हिरदैराम और एक ढांगा की आत्मकथा गढ़वाली भाषा की अनमोल और सर्वोत्तम कहानियों में शामिल है। यदि आपने अभी तक ये कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो मेरी सलाह पर पढ़ने के बाद आप मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। क्योंकि ये कहानियां गढ़वाल गद्य साहित्य की समृद्धता और संवेदनशीलता को बताती हैं। गढ़वाली मुहावरों, कहावतों और किस्से-कहानियों का दिलचस्प प्रवाह इन कहानियों में है। साथ ही पहाड़ी जीवन की विकटता और विडम्बना को इन कहानियों के माध्यम से आज भी महसूस किया जा सकता है। ●

अर्बन नक्सलवाद ज्यादा खतरनाक

मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, पर अरबन नक्सलवाद कब खत्म होगा? क्योंकि राजधानी दिल्ली में नक्सलियों का समर्थन करने वालों का असली चेहरा 23 नवंबर को सबके सामने था, सवाल ये भी कि युवाओं के जहन में भरा नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? जंगल के नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के बहाने नक्सलियों का समर्थन करने वाले थे।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सुरक्षाबल सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जिससे नक्सलियों में खौफ पैदा हुआ है। इसलिए सैकड़ों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। हाल ही में नक्सलियों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले हिडमा को सुरक्षाबलों ने आंध्र प्रदेश में मार डाला। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खौफ का आलम ये है कि बैन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर 15 फरवरी, 2026 तक हथियार छोड़ कर मुख्यधारा से जुड़ने की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने सरकार से उनके द्वारा तय की गई तारीख 15 फरवरी तक सुरक्षा बलों के एंटी-माओवादी ऑपरेशन रोकने की अपील भी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई और गृह मंत्री विजय शर्मा तथा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र में कहा गया है, स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़ना चाहती है और सरकार की रिहैबिलिटेशन और पूनमरगम स्कीम को मानना चाहती हैं। हम तीनों राज्यों की सरकारों से समय देने की निवेदन करते हैं। चूंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के सिद्धांतों को मानती है, इसलिए हमें मिलकर इस फैसले पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत के नाम से 22 नवंबर को जारी पत्र में माओवादियों ने अपनी गतिविधियां रोकने की भी पेशकश की है। इसमें आगे कहा गया है, हम समझते हैं कि यह समय थोड़ा लंबा है, लेकिन यह माओवाद को खत्म करने के लिए सरकार की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 के अंदर है। तब तक हम तीनों राज्यों की सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे थोड़ा कंट्रोल रखें और अपने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन रोक दें। लेकिन इस पत्र के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि माओवादियों को एक ठोस ऑफर देने की जरूरत है। उन्होंने लेटर में दी गई डेडलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा, मैंने लेटर देखा है और ऑडियो भी सुना है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो 15 फरवरी के बारे में कहते हैं। इसमें इतना समय नहीं लगता और किसी के पास इतना समय नहीं है लिहाजा उन्हें एक ठोस प्रपोजल देना चाहिए था।

अरबन नक्सल का क्या होगा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की डेडलाइन में अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन माओवादियों की कमर अभी से टूट गई है। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 17 साल तक सदस्य रहे और 45 साल तक अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने वाले पिल्लारी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना ने माना कि नक्सलियों में मतभेद अब खुलकर सामने आ चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि वामपंथी चरमपंथ का सर्वाइव करना मुश्किल है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जंगल के नक्सलवाद की डेडलाइन तो निश्चित हो गई, माना जा रहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन अरबन नक्सलवाद कब खत्म होगा? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में नक्सलियों का समर्थन करने वालों का असली चेहरा 23 नवंबर को सबके सामने था। सवाल ये भी कि युवाओं के जहन में भरा अरबन नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? जंगल के नक्सलवादियों से ज्यादा खतरनाक दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के बहाने नक्सलियों का समर्थन करने वाले थे। 23 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण का विरोध करने के लिए युवा इंडिया गेट पर जुटे। जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कम किया, लेकिन एक करोड़ रुपये के ईनामी नक्सलवादी माडवी हिडमा की मौत का मातम ज्यादा मनाया।

प्रदर्शनारियों के हाथ में एनकाउंटर में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर थे और जुबान पर 'कितने हिडमा मारोगे', 'हर घर से हिडमा निकलेगा', 'हिडमा अमर रहे' जैसे नारे थे। प्रदर्शनकारी जब सड़क जाम करने लगे तो पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वामपंथी विचारधारा और अरबन नक्सलवाद के समर्थकों ने पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया। एक करोड़ के ईनामी टॉप नक्सली कमांडर माडवी हिडमा (43) को सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर को एनकाउंटर में मार गिराया था। कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा उस दहशत का नाम था जिस पर कम से कम 26 बड़े नक्सली हमलों का आरोप था। सरकार ने उसे भी हथियार डालने का संदेश दिया था, लेकिन वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुर्दान्त नक्सली कमांडर हिडमा ने 2010 में दंतेवाड़ा में हमला किया था जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी नरसंहार में 27 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा-बीजापुर में हमला कर हिडमा ने 22 सुरक्षाबलों के जवान शहीद किए थे। जरा सोचिए दिल्ली के इंडिया गेट पर मानवता के हत्यारे को अपना आदर्श मान कर उसका समर्थन करने वाले कितने खतरनाक होंगे, जो हमारे और आपके ही बीच में रह रहे हैं? हालांकि हिडमा का समर्थन करने और पुलिस पर मिर्च स्प्रिे से हमला करने वाल 22 लोगों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शकारियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की अर्बन नक्सलियों से लिंक की जांच भी कर रही है। हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197 भी जोड़ दी है। बीएनएस की धारा 197 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा या समुदाय के विरुद्ध ऐसी बातें कहता या फैलाता है, जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता या भारत की संप्रभुता के लिए किसी भी तरह से खतरा पैदा हो, तो उस व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। यह कानून ऐसे नैरेटिव को रोकने के लिए है, जिसके जरिए देश को तोड़ने की कोशिश होती है या झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। अगर यह अपराध किसी धर्म स्थल पर किया जाता है तो सजा बढ़ाकर पांच साल तक या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

नौजवानों को सरकार की तरफ से नौकरी, रोजगार मिलने पर नक्सलवाद कमजोर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, इसे पूरी तरह खत्म करना है तो उन समस्याओं को खत्म करना होगा, जिसकी वजह से नक्सलवाद शुरू हुआ था, ये समस्याएं हैं समाज में असमानता और गरीबी की है, अगर सरकार इन्हें खत्म कर देती है तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।

माओवादियों को एक के बाद एक झटके

माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 17 साल तक सदस्य रहे और 45 साल तक अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने वाले प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना ने खुद की बिगड़ती सेहत और सरकार के कसते शिकंजे को देखते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया था। चंद्रन्ना का कहना है कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी में अब वैचारिक मतभेद चरम पर हैं। इन मतभेदों और माओवादियों को लगे एक के बाद एक झटकों ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। उनका मानना है कि मुख्यधारा में लौटना और हथियार डालकर सरेंडर करने में फर्क है। क्योंकि माओवादी विचारधारा अभी जिंदा है, लेकिन बदले राजनीतिक और राष्ट्रीय हालात को देखते हुए पार्टी के राजनीतिक और सैन्य ढांचे में भी बदलाव हो रहे हैं। जब मैं पार्टी में था, तब हम कुछ दस्तावेज तैयार कर रहे थे। कुछ दस्तावेज तैयार हो भी गए थे। इन सभी का मकसद बदलाव लाना था। गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के सवाल पर चंद्रन्ना का कहना था कि पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्च तक इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ हथियारबंद पार्टी नहीं है, यह लोगों के बीच रहकर काम करने वाली पार्टी है। देश में इसके हजारों कार्यकर्ता हैं। 16 राज्यों में इसका अस्तित्व है। 2019 में भी पार्टी को कुछ झटका लगा था, लेकिन हमें एकजुट रहकर लोगों की भलाई के लिए काम करते रहना होगा। चंद्रन्ना ने माना कि 21 मई तो नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज का मारा जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। दंडकारण्य के 4 जोन में से सिर्फ दक्षिणी बस्तर जोन में अब पार्टी बची है। दोनों के बीच डिफरेंस है। नॉर्थ जोन में पार्टी और ब्यूरो को बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन साउथ जोन सेफ है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा वगैरा के कैडर देवूजी की लाइन पर चलते हैं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

- **एनकाउंटर में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगे 'कितने हिडमा मारोगे', 'हर घर से हिडमा निकलेगा', 'हिडमा अमर रहे' प्रदर्शनकारी जब सड़क जाम करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अरबन नक्सलवाद के समर्थकों ने पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे से हमला कर दिया।**
- **एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत के नाम से 22 नवंबर को जारी पत्र में माओवादियों ने अपनी गतिविधियां रोकने की भी पेशकश की है, इसमें आगे कहा गया है, हम समझते हैं कि यह समय थोड़ा लंबा है, लेकिन यह माओवाद को खत्म करने के लिए सरकार की डेडलाइन 31 मार्च, 2026 के अंदर है।**

असमानता से जनमा नक्सलवाद

45 साल तक अंडरग्राउंड रहकर माओवादी नीतियों का प्रचार-प्रसार करने वाले चंद्रन्ना का कहना है कि 70 के दशक में तेलंगाना में पार्टी की शुरुआत हुई थी। फिर पीपल्स वॉर ग्रुप बना और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। इसकी बदौलत कई लोगों को जमीने वापस मिलीं। उनका कहना था कि बस्तर में सत्ताधारी पार्टियां कहती थी कि यह इलाका माओवादियों की वजह से पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह सच नहीं है। आजादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन यह क्षेत्र अब तक पिछड़ा क्या हैं? इसकी वजह माओवादी नहीं, सत्ताधारी पार्टियां हैं। माओवादी आंदोलन तो 80 के दशक में परवान चढ़ा था। लंबे अरसे तक माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे चंद्रन्ना ने माना कि कारगर ऑपरेशन और सरकार की सरेंडर पॉलिसी की वजह से पार्टी के कई नेता अलग हो गए। पार्टी में विभाजन साफ दिख रहा है। कैडर पर भी असर पड़ा है। आगे और भी लोग पार्टी से बाहर आ सकते हैं। सरकार जो वित्तीय सहायता दे रही है, लोगों को उसकी जरूरत है। लोगों को रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। नौजवानों को सरकार की तरफ से नौकरी, रोजगार मिलने पर नक्सलवाद कमजोर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसे पूरी तरह खत्म करना है तो उन समस्याओं को खत्म करना होगा, जिसकी वजह से नक्सलवाद आंदोलन शुरू हुआ था और ये समस्याएं हैं समाज में असमानता और गरीबी की है। अगर सरकार इन्हें खत्म कर देती है तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।

लुप्त हो रहे नौले

पहाड़ों में अब आखिरी पीढ़ी बची है, जो नौलों के महत्व को लेकर संवेदनशील है, हमारा परंपरागत ज्ञान तभी सुरक्षित रह सकता है, जब हम नौले के पास जाएंगे, उसकी आत्मीयता को महसूस करेंगे, इसलिए देखने में आ रहा है कि नौलों के प्रति पुराने लोग काफी चिंतित हैं।

भारत भूषण
आईएफटीएम

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नौलों की अपनी एक संस्कृति रही है। हिमालय क्षेत्र में जितने भी पुराने नौले हैं, वहां कत्युरी राजाओं की छाया देखी जा सकती है। नौलों में हमारी संस्कृति भी दिखती है, जितने भी नौले हैं, वहां यक्ष देवता की मूर्ति हर नौले में रखी मिलती थी। बुजुर्ग बताते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में यक्ष देवता को प्रणाम करने के बाद ही पानी लेने का विधान रहा है। नौलों में जूता पहनकर जाने की सख्त मनाही होती थी, इसलिए पानी लेने वाला शख्स जूतों को खोलकर नौले में रखे देवता को प्रणाम करके ही पानी लेता था। यानी पुराने समय में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता था, यह परंपरा शहर में पानी का पाइप लाइन आने के बाद लगभग खत्म ही हो गई है। अब तो पानी के लिए लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। इस तरह उपेक्षित बहुत से नौले लुप्त हो गए हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि इन नौलों को बचाने से हम पानी के संकट से बच सकते हैं। समाज को शुद्ध पानी निशुल्क मिल सकता है। इतना ही नहीं आधुनिकता की आंधी में नौलों के साथ हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव को भी पहाड़ के समाज ने भुला दिया है। पहाड़ों में अब आखिरी पीढ़ी बची है, जो नौलों के महत्व और इतिहास को लेकर संवेदनशील है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परंपरागत ज्ञान तभी सुरक्षित रह सकता है, जब हम नौले के पास जाएंगे, उसकी आत्मीयता को महसूस करेंगे। इसलिए देखने में आ रहा है कि नौलों के प्रति पुराने लोग काफी चितिंत हैं। लेकिन नौलों के प्रति उनकी चिंता कम और परियोजना के प्रति उसमें आकर्षण अधिक नजर आता है। यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो समाज की सहभागिता और प्रशासन के सहयोग से यह काम किया जा सकता है।

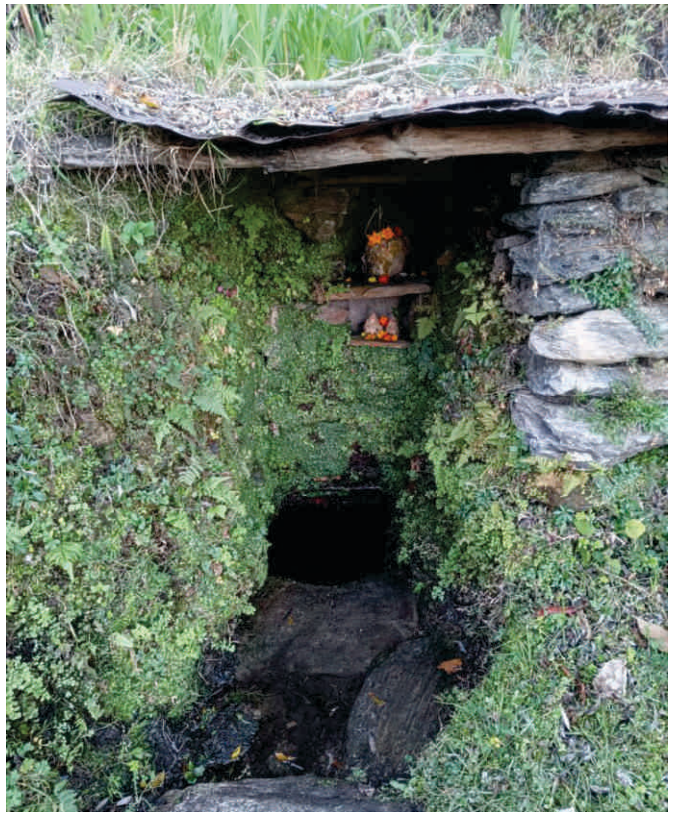

नौला सफाई अभियान

अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मित्रों के साथ मिलकर नौलों की सफाई का काम शुरू किया था। बहुत से नौलों में उन्होंने सफाई अभियान चलाया। रानी नौला, लक्ष्मीश्वर नौला, सिद्ध नौला, कपिना नौला में सफाई की। यह सब उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं किया, बल्कि नदी बचाओ अभियान चलाते हुए किया। उन्हें लगा कि नदी तभी बचेगी, जब नौले और धारे बचेंगे। उन्होंने नौले और धारों की सफाई के अभियान की शुरुआत इसलिए की क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस तरह से नौलों धारों की सफाई के काम से समाज को जोड़कर वे दूसरे नौले की सफाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जबकि तीन चार सप्ताह सफाई करने के बाद लोगों के फोन उनके पास आने लगे कि इस बार सफाई के लिए क्यों नहीं आए? लोग इस तरह के अभियान से जुड़ते नहीं बल्कि उनकी आदत निर्भर रहने की हो गई। कोई बाहर से आए और उनकी सारी फैलाई हुई गंदगी समेट कर अपने साथ ले जाए। हालांकि नौलों का इतिहास प्राचीन है। इतिहास गवाह है कि शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के नाम से छठीं शताब्दी में कत्युरी साम्राज्य स्थापित हुआ। इसकी सीमा अफगानिस्तान तक फैली थी। कत्युरी राजाओं का युद्ध मुगलों से हुआ। काठगोदाम के पास रानी बाग में जिया रानी मुगलों से लड़ती हुई मारी गई। लेकिन अपने जीवन में मुगलों को पहाड़ पर नहीं आने दिया। हालांकि इतिहासकार अल्मोड़ा शहर को बसाने का श्रेय चंद राजाओं को देते हैं। 1563 में चंद राजा बालो कल्याणचंद ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले यह शहर कत्युरी राजाओं की देखरेख में था और चंद राजाओं की राजधानी उस समय पिथौरागढ़ हुआ करती थी। जानकार बताते हैं कि मुगलों ने चंद राजाओ से समझौता किया था। समझौते के तहत चंद राजाओं ने मुसलमानों को अपने यहां रहने के लिए जगह देने का आश्वासन दिया और अल्मोड़ा शहर में राजपुरा उसी समझौते के का नतीजा है। मुसलमानों के बसने से पहले आम जन के बीच देवताओं का भय था कि वे नौलों में स्वच्छता नहीं रखेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये डर समाज के अंदर से जाता रहा है और समाज का नैतिक मूल्यों का पतन होता रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नौले और धारों की सफाई का अभियान चलाया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस तरह से नौलों धारों की सफाई से समाज को जोड़कर वे दूसरे नौले की सफाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सफाई करने के बाद लोगों के फोन उनके पास आने लगे कि इस बार सफाई के लिए क्यों नहीं आए?

आध्यात्मिक बोध खत्म

अब युवा पीढ़ी को परिवार और समाज से नैतिक शिक्षा नहीं मिलती। वैसे अनैतिकता के आग्रह के साथ विकास कर रहे समाज को परवाह हो ना हो, पर नौलों में उतरने पर ईश्वर की मूर्तियां अब भी वहां विराजमान है। वहां गोल विष्णु चक्र मिलेगा। कत्युरी राजा मानते थे कि जल ही विष्णु है। जो हमारा लालन-पालन करते हैं। अब भेड़चाल ने हमारे अंदर का आध्यात्मिक बोध खत्म हो कर दिया है। भौतिक बोध बच गया है कि हमें नहाना है, इसलिए हम नदियों और नौलों को प्रदूषित कर रहे हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं रही कि हमारे बाद भी लोग यहां आएंगे। हम अपने कल के लिए प्रकृति को संवारने में यकीन खो रहे हैं। अल्मोड़ा शहर जिसे कभी 360 नौलों का शहर कहा जाता था, जिसका जिक्र पंडित बद्रीदत्त पांडेय ने 'कुमाऊं के इतिहास' में किया है। दूसरी तरफ नैनीताल की कथित तौर पर खोज करने वाला बैरन जो 1840 में अल्मोड़ा आया। उसने लिखा कि अल्मोड़ा में उस समय लगभग 100 जल स्त्रोत (नौले) थे। 'पर्वतीय जल स्त्रोत' नामक किताब के लेखक प्रफुल्ल चंद पंत ने 1988-93 के बीच नौलों और धारों पर गंभीर अध्ययन करने पर पाया कि बैरन ने अपनी किताब में सच लिखा है।

प्रदूषिक हो चुके हैं नौले

1864 में स्थापित अल्मोड़ा नगर पालिका भारत की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। इसके नियम कानून की पुस्तिका में लिखा है कि चेचक के रोगियो अथवा किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े धोने के लिए अलग नौले की व्यवस्था थी। रजस्वला स्त्रियों के स्नान के लिए नौले अलग थे। पीने का पानी जहां से लिया जाए वहां कपड़े धोने और स्नान करने की मनाही थी। क्रिया कर्म के नौले अलग थे। यहां नियम का पालन ना करने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था थी। मृत्यु के बाद 12 दिनों तक चलने वाले कर्मकांड के लिए क्रिया नौलों का इस्तेमाल किया जाता था। यहां उल्लेखनीय है कि जिन नौलों का इस्तेमाल क्रिया कर्म के लिए किया जाता था, उन्हीं नौलों का पानी कुमाऊं में पीने योग्य बचा है। बाकी नौलों की हालत खराब है। संभव है समाज में मौजूदा मृत्यु से भय ने क्रिया नौलों की रक्षा की होगी। सुनारी नौला, चौधरी नौला जैसे जाति आधारित नौले भी कुमाऊं में देखने को मिलते हैं। कोसी पेयजल योजना 1952 में बनी। बावजूद इसके अल्मोड़ा में पानी के लिए नौलों की शरण में जाना मजबूरी थी। इस योजना का पानी भी अल्मोड़ा के लिए पर्याप्त नहीं था। 1882 में अल्मोड़ा की जनसंख्या 5000 थी। उस वक्त भयानक सूखा पड़ा था। सारे जल स्त्रोत (नौले) सूख गए थे। बची थी सिर्फ कपीना धारा। उन दिनों कपीना धारा पर चाय का बगान था। उस धारा के पानी ने लगभग 135 साल पहले पूरे अल्मोड़ा शहर के जीवन की रक्षा की थी। पंडित बद्री दत्त जोशी जिन्होंने बदरिश्वर मंदिर बनाया ने तब जिलाधिकारी को जल परियोजना के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें इस घटना का उल्लेख मिलता है। बल्ढ़ौटी में पांच जल स्त्रोत थे। उस पानी को पहली बार पाइप के जरिए अल्मोड़ा शहर में लाया गया लेकिन उस पानी से अल्मोड़ा की जरूरत पूरी नहीं हुई। कचहरी के पास रम्फा नौला है। वहां जल परियोजना का पानी छोड़ा गया। 1928 में स्याही देवी जल परियोजना आई। स्याही देवी अल्मोड़ा के पास एक बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को अल्मोड़ा के अभिभावक जैसा माना जाता है। कसार देवी और वानर देवी की पहाड़ी को मिला दें तो इस तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरने की वजह से अल्मोड़ा का मौसम ना अधिक गर्म हो पाता है और ना अधिक ठंडा। लेकिन अब अल्मोड़ा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। अल्मोड़ा के थपलिया में एक राज नौला भी है। इस नौले का नाम राज नौला इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से राजा के लिए पानी जाता था। आज वहां का पानी पीने लायक नहीं बचा, वह प्रदूषित हो चुका है। अल्मोड़ा के प्राकृतिक जल स्त्रोत एक के बाद एक प्रदूषण के शिकार हो गए हैं। उनका पानी पीने योग्य नहीं बचा। गिनती के नौले और धारे कुमाऊं में बचे हैं, जिनका पानी पीने योग्य है। वर्ष 1947 में देश जब आजाद हुआ, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में ड्रेनेज की जो व्यवस्था थी, 2016 में हम उस व्यवस्था से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। इतने सालों में कुछ नहीं बदला। उलटे ड्रेनेज के साथ जुड़े गदेरे अतिक्रमण के शिकार हो गए और घर बन गए। गदेरों के आसपास सबसे अधिक नौले मौजूद हैं। गदेरे खत्म किए गए और शहर का सारा गंदा पानी नौलों में जा मिला।

जनसहभागिता आवश्यक

सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से कई बार शहर के नौलों के पानी का परीक्षण हुआ। उसके परिणाम चिंताजनक थे। लेकिन इन परिणामों के बाद भी शहर में पीने के पानी को लेकर कोई बहस नहीं हुई।

- **बुजुर्ग बताते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में यक्ष देवता को प्रणाम करने के बाद ही पानी लेने का विधान रहा है, नौलों में जूता पहनकर जाने की सख्त मनाही होती थी, इसलिए पानी लेने वाला शख्स जूतों को खोलकर नौले में रखे देवता को प्रणाम करके ही पानी लेता था।**
- **मुसलमानों के बसने से पहले आम जन के बीच देवताओं का भय था कि वे नौलों में स्वच्छता नहीं रखेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये डर समाज के अंदर से जाता रहा है और समाज का नैतिक मूल्यों का पतन होता रहा है।**

जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यह समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए थी क्योंकि जब हर तरफ अतिक्रमण करने वालों का कब्जा होगा, फिर अल्मोड़ा का गंदा पानी किस रास्ते बाहर जाएगा? अल्मोड़ा के घर-घर में सेप्टिक टैंक पहुंच गया लेकिन वहां इकट्ठा हो रहे मल मूत्र के निपटारे के लिए शहर के पास कोई कार्ययोजना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि नौलों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? यदि वास्तव में इस विषय को लेकर कुमाऊं का समाज गंभीर है तो इसके लिए सबसे पहले नौले के कैचमेंट एरिया को सुरक्षित करना होगा। ऐसा करने से नौले में पानी बढ़ेगा। क्योंकि नौलों और धारों की उपेक्षा के कारण अल्मोड़ा जिस पानी की संकट से गुजर रहा है, यदि आने वाले समय में शहर इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है तो इसका हल जनसहभागिता से ही निकल सकता है। जनसहभागिता से ही बदलाव आ सकता है। सरकारी परियोजनाएं एक हजार करोड़ की भी आ जाएं तो इस समस्या से कुमाऊं बाहर नहीं आ सकता। समाधान के लिए पानी के प्रति समाज में जागृति जरूरी है। पानी का मोल जब तक कुमाऊं नहीं समझेगा और पानी की गुणवत्ता को लेकर वह जागरूक नहीं होगा, तब तक उसे इस बात की समझ नहीं होगी कि पानी से जुड़ी सभी बीमारियों के जड़ में प्रदूषित पानी है।

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, शुरुआती दौर में उनका सफर साधारण रहा, लेकिन उनकी रौबदार पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने जल्द ही उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के जाने से उनके फैंस दुखी है, 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने जुहू स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र अपने पीछे न सिर्फ यादगार फिल्में छोड़ गए, बल्कि इंडस्ट्री में अपने शुरुआती सालों की अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियां भी छोड़ गए। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में केवल कृष्ण देओल के घर जन्मे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद उनका इलाज घर पर ही किया जाने लगा। लेकिन वक्त के साथ तबीयत नहीं सुधरी और 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उनका सफर साधारण रहा, लेकिन उनकी रौबदार पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने जल्द ही उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। धर्मेंद्र की शुरुआती फिल्मों ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया, लेकिन आने वाले वर्षों में उनकी अदाकारी, एक्शन और रोमांस की अनोखी शैली ने उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में मजबूती से स्थापित किया। 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' इस दिग्गज अभिनेता की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म 'इक्कीस' की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है। महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है।

89 की उम्र में धर्मेंद्र सोशल मीडिया से जुड़े रहे

धर्मेंद्र ने छह दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और अपने दमदार एक्शन किरदारों की वजह से उन्हें 'ही-मैन ऑफ बॉलीवुड' कहा गया। उनकी अदाकारी और व्यक्तित्व ने पीढ़ियों को प्रभावित किया और वे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग के प्रतीक बन गए। उनकी गर्मजोशी, सादगी और अभिनय के प्रति गहरा समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। धर्मेंद्र की विरासत आने वाले कलाकारों और फिल्मकारों को प्रेरित करती रहेगी। 89 वर्ष की उम्र में भी धर्मेंद्र सोशल मीडिया के जरिये अपने फैंस से जुड़े रहे। वो अपने फार्म हाऊस पर खेतों में काम करते हुए वीडियो पोस्ट करते थे, ट्रैक्टर चलाते दिखते थे, जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव साझा करते थे और लोगों को सरल, देसी और जैविक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। धर्मेंद्र का फार्म हाउस करीब 100 एकड़ में फैला है जिसमें स्विमिंग पूल और एक्वा थेरेपी एरिया जैसी सुविधाएं हैं। फार्म हाउस में जिम और दूसरी सुविधाएं भी हैं। शहर की जिंदगी से दूर रहने के लिए ये उनकी पसंदीदा जगह थी। उनके फार्म हाउस में कई गाय-भैंस भी हैं जिनके वीडियो वो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते थे। किसान परिवार से आने वाले धर्मेंद्र को ऑर्गेनिक खेती का शौक था। जिसे वह अपने फार्महाउस में करते थे। अपने फार्म में वो कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते थे और सालों से ऐसा करते आ रहे थे। मुंबई की भीड़ से दूर यहां सुकून के पल बिताना धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा पसंद था।

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग में सक्रिय थे, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी, इस फिल्म की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है, महज 21 साल की उम्र में देश के लिए इस सैन्य अधिकारी ने बलिदान दिया था, फिल्म में धर्मेंद्र ने आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार निभाया है।

राष्ट्रपति व पीएम ने शोक जताया

'ही-मैन ऑफ बॉलीवुड' और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दीं। भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में, वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह जीवंत बन उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु-वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा प्रमुख मायावती, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

धर्मेंद्र के भाई का दर्दनाक किस्सा

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह देओल का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीरेंद्र सिंह देओल 80 के दशक में धर्मेंद्र से भी बड़े स्टार थे। पंजाबी सिनेमा के वो सुपरस्टार थे। उनके दरवाजे पर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर की लाइन लगी रहती थी। सभी उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। 37 साल पहले 6 दिसंबर 1988 में फिल्म के सेट पर ही दर्दनाक तरीके से वीरेंद्र सिंह हत्या कर दी गई थी। 6 दिसंबर को वीरेंद्र 'जट ते जमीन' की शूटिंग कर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म के सेट पर ही उनकी हत्या कर दी जाएगी। शायद यही वजह है कि आज की पीढ़ी उनके नाम से कम ही वाकिफ है। वीरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र के कजिन थे। उनकी मौत का रहस्य आज तक नहीं खुल सका है। जबकि धर्मेंद्र के कजिन वीरेंद्र सिंह को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था। वीरेंद्र फिल्म निर्माता और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने करियर में 25 फिल्मों में काम किया। हैरानी की बात यह है कि ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। वीरेंद्र सिंह की हत्या किसने की या करवाई, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में दबी जुबान से इस बात की चर्चा जरूर रही कि वीरेंद्र सिंह की पॉपुलैरिटी ही उनकी दुश्मन बन बैठी थी। वीरेंद्र सिंह ने 1975 में आई फिल्म 'तेरी मेरी एक जिंदड़ी' से अपने करियर की शुरुआत की थी। धर्मेंद्र ने भी इस फिल्म में काम किया था। फिल्म हिट हुई और यहीं से वीरेंद्र के करियर ने नया मोड़ लिया। उन्होंने अपना स्क्रीन नाम वीरेंद्र सिंह देओल से बदलकर सिर्फ वीरेंद्र रख लिया। फिर क्या था, यही नाम उनकी पहचान बन गया था। बॉलीवुड में जहां 70 के दशक में धर्मेंद्र का सिक्का चलने लगा था, वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन उनकी सफलता ही उनकी जान की दुश्मन बन गई।

धर्मेंद्र के बचपन का प्यार हमीदा थी

सलमान खान के गेम शो 'दस का दम' से वायरल हुए वीडियो में ऐसा एक पल देखने को मिला था, जब धर्मेंद्र ने खुलकर बताया कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म से कितना कमाया और उसे कैसे खर्च किया। धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल के सामने अपनी उस मासूम लव स्टोरी को भी याद किया था, जो उनके बचपन से

- **किसान परिवार से आने वाले धर्मेंद्र को ऑर्गेनिक खेती का शौक था, जिसे वह अपने फार्महाउस में करते थे, अपने फार्म में वो कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते थे और सालों से ऐसा करते आ रहे थे, मुंबई की भीड़ से दूर यहां सुकून के पल बिताना धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा पसंद था।**
- **फिल्म इंडस्ट्री को धर्मेंद्र ने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, 'सीता और गीता', 'शोले' और 'यादों की बारात' जैसी फिल्मों ने न सिर्फ उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई, बल्कि अपने समय के सबसे भरोसेमंद एक्टर्स में से एक के तौर पर उन्हें पहचान दिलाई।**

जुड़ी थी। धर्मेंद्र ने पहली बार अविभाजित भारत में हमीदा को अपने एक रिश्तेदार के गांव में देखा था और पहली ही नजर में उस पर दिल हार बैठे थे। उन्होंने हमीदा के साथ अपनी लव स्टोरी को याद करते हुए कहा था-'हम मन ही मन में बात करते थे। एक-दूसरे को देखकर आहें भरते थे। सामने किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था।' धर्मेंद्र ने इसी दौरान बताया कि वह बहुत शर्मीले थे, लिहाजा वह कभी हमीदा को अपने दिल की बात नहीं कह पाए। धर्मेंद्र ने शो के दौरान खुलासा किया था कि उन्होंने हमीदा की याद में एक कविता भी लिखी थी। उन्होंने बताया था-जब मैं पढ़ता था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात है। मैं छोटा था, मासूम था मेरी उम्र क्या थी, वो तो याद नहीं, पर उसके पास उसके साथ बैठने को जी चाहता थी। वो आठवीं क्लास में थी, मैं छठी में था। हमीदा हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद हमीदा और धर्मेंद्र हमेशा के लिए अलग हो गए। हमीदा अपने परिवार के साथ सिंध चली गई और धर्मेंद्र जहां थे वहीं रह गए। भले ही धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर और हेमा मालिनी से शादी की, लेकिन उनका पहला प्यार हमीदा थी, जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे में छूट गया।

धर्मेंद्र की पहली कमाई

'दस का दम' शो में धर्मेंद्र बड़े बेटे सनी देओल के साथ आए थे। गेम शो में 1 लाख जीतने के बाद सलमान ने धर्मेंद्र से पूछा था कि जब वह एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पंजाब से मुंबई आए थे तो उनके लिए उस रकम का क्या मतलब था। धर्मेंद्र ने तुरंत जवाब दिया था, उस समय लाख रुपये... हे भगवान। फिर सलमान ने उनसे उनकी पहली फिल्म की सैलरी के बारे में पूछा। धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए याद किया, 3,500-7,000 रुपये, पर उससे पहले एक और फिल्म मिली थी, अर्जुन हिंगोरानी की। तीन पार्टनर थे और मैं उनके आफिस में केबिन के किनारे बैठा सोच रहा था कि मुझे कम से कम 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्होंने साइनिंग अमाउंट के तौर पर सिर्फ 51 रुपये दिए थे। धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्होंने '51 रुपये से शराब खरीदी ताकि वह अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकें।' याद करते हुए और हंसते हुए उन्होंने कहा था, जब हमने अपना 'पहला पैग लिया तो मैंने गिलास को रूमाल से पकड़ा ताकि उस पर मेरे फिंगरप्रिंट न लगें।' मुझे लगा कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। फिर धर्मेंद्र ने मजाक में कहा, 'तीसरे पैग तक, मैंने रूमाल छोड़ दिया।' फिल्म इंडस्ट्री को धर्मेंद्र ने कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। 'सीता और गीता', 'शोले' और 'यादों की बारात' जैसी फिल्मों ने न सिर्फ उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई, बल्कि अपने समय के सबसे भरोसेमंद एक्टर्स में से एक के तौर पर उन्हें पहचान दिलाई। 1970 के दशक में अपना स्टारडम बनाए रखने के बाद धर्मेंद्र ने 1980 के दशक में आसानी से एक्शन जॉनर में कदम रखा। उनकी एक्टिंग ने ही उन्हें इंडिया के ही-मैन का आइकॉनिक टाइटल दिलाया।

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आपके वरिष्ठ इस माह देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। अप्रेल में आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे-साथ ही आपको आकस्मिक उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं मिलेंगे। उपाय: मानसिक हिंसा से बचे, प्रभु में विश्वास रखें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृषभ:-

इस माह आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने-पहचाने से महसूस होंगे। यह माह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी सुकूनभरी और रुशनुमा रहेगी। इस माह आपको सब-कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। कार्यालय में कोई आपको बढ़िया खबर दे सकता है। उपाय: गणेशजी की चार परिक्रमा लेकर आशीर्वाद ले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मिथुन:-

इस माह खीज और चिढ़चिढ़ेपन के अहसास को खुद पर हावी न होने दें। इस माह धन योग है। आप काफी धन कमा सकते हैं। बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और सुकून देंगे। प्रिय के साथ बाहर जाते समय अपने पहनावे और बरताव में नयापन दिखाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जीवनसाथी के साथ शांत रहे ताकि लड़ाई-झगड़ा न हो। उपाय: काले चने, उड़द, तिल, सरसो का तेल दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

कर्क:-

इस माह बिना वजह के वाद-विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई बेहतरीन विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। अपने शब्दों पर काबू रखें, वरना परिवार के बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। उन्हें अहसास कराएं कि आप उनका खयाल रखते हैं। इस माह के अंत में कारोबार के लिए की जाने वाली यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी आपका काम बिगाड़ सकता है। धैर्य रखें। उपाय: काला-सफेद कपड़ा साधु संतों को दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

सिंह:-

इस माह आपका आत्मविश्वास और आसान कामकाज आपको आराम के लिए समय देंगे, लेकिन धन आपकी मुट्ठी से सरक सकता है। आपके अच्छे सितारे आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती हैं, जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता होगा। कार्यालय में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपाय: गुरु या पिता की आज्ञा का पालन करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कन्या:-

इस माह रियल एस्टेट संबंधी निवेश अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है। घर में कुछ बदलाव भावुक बना सकते हैं। अपने प्रिय जीवनसाथी के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकती हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरुकता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए यह माह खूबसूरत रोमानी रहेगा। सेहत का ख्याल रखे वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: धर्म स्थान पर झंडा दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

तुला:-

लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि इस माह आपको मिल जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाने का समय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: अपने पार्टनर को गुलाब दें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृश्चिक:-

रिश्तेदारों का सहयोग तनाव कम करेगा। सगे संबंधियों से मिलन होगा। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। बच्चे और परिवार को केंद्र में रखें। किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की प्रबल संभावना है। अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं वह टल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। जीवनसाथी प्रेम से भरपूर रहेगा। उपाय: पूजा स्थान पर सफेद शंख स्थापित करें, कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

धनु:-

इस माह खुद को किसी सृजनात्मक काम में व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन धन का व्यय आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। प्रिय से रोमांटिक मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती। जीवनसाथी यह बताएगा कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखे सुबह घर के बाहर पेड़ पौधों में डाले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मकर:-

यह माह मौज-मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है। जल्दी ही आपको जीवन-साथी मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आने का प्रबल योग है। उपाय: किसी तरह का घमंड न करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कुंभ:-

इस माह कमीशन, लाभांश या रायल्टी के जरिए फायदा होने का योग बन रहा है। आपको ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाने में सहायक हों। आपका प्यार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। लेखन और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी ख्याति प्राप्त होने से प्रसन्नता होगी। अपने व्यक्तित्व और रंग-रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

मीन:-

यह माह फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी से राहत और आराम महसूस करेंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपकी बचत को मुश्किल बना देगा। आप अपनी कामयाबी की फेहरिस्त में एक नया मोती जड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। इस माह आपको निराशा हाथ लग सकती है। उपाय: अपने प्रिय को पिंक कलर के मोती या सिप की बनी हुई वस्तु गिफ्ट करें। कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 3